R.N.I. NO.HIN/2002/8718 M.P./BHOPAL/642/2021-23

• क्या पूरा होगा सिंधिया का सपना? • किसान कैसे होगा आत्मनिर्भर?

In Pursuit of Truth

पाक्षिक

अक्स

www.akshnews.com

मप्र के माननीय सबसे अव्वल

वर्ष 19, अंक-14 16 से 30 अप्रैल 2021 पृष्ठ-48 मूल्य 25 रूपये

कोरोना की मार...

बेबस जनता

नाकाम सरकार

“ मोदी जी के सपने को, पूरा करता मध्यप्रदेश ”

मध्यप्रदेश शासन

जनसेवा का एक साल

श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री

“प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के ‘आपदा में अवसर’ के मंत्र पर चलते हुए हम उनके ‘आत्मनिर्भर भारत’ के सपने को पूरा करने के लिये आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश का निर्माण कर रहे हैं।”

- शिवराज सिंह चौहान

प्रमुख कार्य

- **विभिन्न योजनाओं में एक लाख 18 हजार करोड़ रुपये की सहायता सीधे प्रदेशवासियों के खातों में।**
- भू-माफिया के कब्जे से 9 हजार करोड़ रुपये की तीन हजार हेक्टेयर से अधिक की शासकीय जमीन मुक्त।
- कोरोना काल में भी 129 लाख मी. टन से अधिक गेहूं की खरीदी कर 25 हजार करोड़ रुपये किसानों के खातों में।
- कोरोना संक्रमितों की पूरी तरह मुफ्त जाँच एवं इलाज। कोरोना को रोकने के लिए बड़े स्तर पर इलाज की सुविधाएं और जरूरतमंद लोगों के लिए खाना, दवा और आर्थिक मदद के इंतजाम।
- प्रदेश के इतिहास में मनरेगा योजनांतर्गत सर्वाधिक 30 करोड़ से अधिक मानव दिवसों का सृजन।
- 2000 ग्रामों में शत्-प्रतिशत घरेलू नल कनेक्शन का प्रदाय।
- मोबाइल पर खसरा/खतौनी/नक्शे की नकल, आय/मूल निवास प्रमाण-पत्र प्रदान करने की सुविधा।
- केन-बेतवा नदी जोड़ो योजना का अनुबंध सम्पन्न।

नई योजनाएं

- मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना
- मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना
- सी.एम. राइज योजना
- मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना
- मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना
- मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना
- पुलिसकर्मियों के लिए कर्मवीर योद्धा पदक योजना
- मुख्यमंत्री कोरोना योद्धा कल्याण योजना
- मुख्यमंत्री प्रवासी मजदूर सहायता योजना।

योजनाएं फिर शुरु

- मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना
- मुख्यमंत्री कन्यादान/निकाह योजना
- दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना
- किसानों को शून्य ब्याज दर पर ऋण योजना
- मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप देने की प्रतिभा प्रोत्साहन योजना
- पंच-परमेश्वर योजना
- मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद्।

कानूनों और नियमों में बड़े बदलाव

- किसानों को फसल बेचने के बेहतर विकल्प देने के लिये मंडी कानूनों में सुधार
- मध्यप्रदेश धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम-2020
- साहूकारों से मुक्ति दिलाने के लिये अनुसूचित जनजाति ऋण विमुक्ति अधिनियम-2020
- शहरी भूमियों के बेहतर उपयोग के लिये नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 2012 में संशोधन।

देश में अग्रणी

- गेहूं खरीदी में देश में पहला स्थान
- एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना में पहले स्थान पर
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में पहला स्थान
- मनरेगा योजना की बजट वृद्धि में दूसरा स्थान
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में पहला स्थान
- प्रधानमंत्री स्व-निधि योजना के तहत पथ विक्रेताओं को ऋण देने में पहला स्थान
- स्मार्ट सिटी रैंकिंग में दूसरा स्थान
- जल जीवन मिशन में 18 लाख नल कनेक्शन देकर दूसरा स्थान
- सुगम व्यवसाय रैंकिंग में चौथा स्थान

मास्क लगाएं, जीवन बचाएं

शिवराज सरकार - भरोसा बरकरार

इस अंक में

विवाद

9 | धान मिलर्स बने मुसीबत

मप्र की शिवराज सरकार के लिए अब धान मिलर्स मुसीबत बन गए हैं। वे अपनी जिद छोड़ने को तैयार नही हैं, तो सरकार भी अपनी जिद पर अड़ी हुई है। इसकी वजह से प्रदेश में अब तक धान से चावल निकालने का काम शुरू...

चौसर

16-17 | दिग्गजों की असली परीक्षा

मप्र की दमोह विधानसभा सीट पर 17 अप्रैल को उपचुनाव के लिए मतदान होंगे। मतदान से पूर्व दोनों पार्टियां अपनी-अपनी जीत के दावे कर रही है। उधर, क्षेत्र का मतदाता पूरी तरह मौन साधे हुए है। ऐसे में भाजपा-कांग्रेस...

भर्राशाही

19 | कोयला के लिए जंगल पर आरी

देश में एक तरफ सरकार वनीकरण और हरियाली को बढ़ावा देने की योजना पर काम कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कोयले के लिए करीब 15,000 एकड़ जंगल काटने की तैयारी हो रही है। इसमें से मप्र में 7 खानों के लिए 838.03 हैक्टेयर...

योजना

21 | सैटेलाइट से होगा सीमांकन

भू-अभिलेख कार्यालय द्वारा प्रदेश में सैटेलाइट इमेज के जरिए सीमांकन करने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए मोबाइल की तरह ही एक रोवर होगा, जो किसी भी खेत की बाउंड्री पर रखने पर घूमने लगेगा और मात्र 15 से 20 मिनट में ही पूरी जमीन का सीमांकन करने के साथ...

आवरण कथा 24, 25, 26, 27, 28

ये जलते और दफन होते मृत शरीर। पसीने से भीगे नीले-सफेद पीपीई किट में रिश्तेदार। मुंह-नाक पर बचाव का मास्क और आंखों में अपनों को खोने का बहता हुआ दर्द। ये तस्वीरें नहीं हैं...ये हमारी लापरवाही, लचर सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था और प्रशासन की कमजोरियों की जलती और दफन होती लाशें हैं। देश में ऐसे भयावह दर्दनाक नजारे हर तरफ से देखने को मिल रहे हैं। ये तस्वीरें कोरोना वायरस के गंभीर संकट को दिखा रही हैं।

राजनीति

30-31 | दिशा भ्रम का शिकार कांग्रेस

राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है कि 'आदमी कमजोर पहले होता है पराजय उसकी बाद में होती है।' उन्होंने यह बात भारत के गुलाम होने के संदर्भ में लिखी थी लेकिन वह कांग्रेस पर खरी उतरती है। हार कमजोरी और दिशा भ्रम कांग्रेस का प्रारब्ध बन गया है।

राजस्थान

37 | सियासी क्षत्रपों का कड़ा इम्तिहान

राजस्थान में 3 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव का घमासान अपने चरम पर है, सुजानगढ़, सहाड़ा और राजसमंद में उपचुनाव के लिए 17 अप्रैल को मतदान होना है। प्रदेश में बढ़ती गर्मी के तापमान के साथ-साथ सियासत का पारा भी चढ़ने लगा है।

विदेश

40 | म्यांमार में लोकतंत्र की तलाश

म्यांमार में लोकतंत्र की सबसे बड़ी उम्मीद आंग सान सू की से कहां चूक हो गई कि वहां की सत्ता पर एक बार फिर सेना का कब्जा हो गया। दशकों के संघर्ष के बाद उन्हें देश की कमान मिली थी। 2015 के चुनाव में जब सू की को जबर्दस्त जीत मिली थी...

6-7 अंदर की बात
41 महिला जगत
42 अध्यात्म
43 कहानी
44 खेल
45 फिल्म
46 व्यंग्य

अपनी बात

ईवीएम को बना दिया बाजारू...!

ग त दिनों सोशल मीडिया पर यह पंक्तियां पढ़ने को मिलीं...

...ताउम्र दरबारी यही गलती करता रहा,
खोट नेता में थी, वो ईवीएम पर दोष मढ़ता रहा।

कुछ ऐसी ही स्थिति भारतीय लोकतंत्र में ईवीएम की हो गई है। विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में मतदान किसी महापर्व से कम नहीं है। इस महापर्व को विवादरहित बनाने के लिए ईवीएम को अपनाया गया। लेकिन आज ईवीएम को बाजारू बना दिया गया है। हार के बाद राजनीतिक दलों द्वारा ईवीएम को दोष देना परंपरा सी बन गई है। लेकिन वर्तमान समय में 5 राज्यों में ईवीएम के दुरुपयोग के जो मामले सामने आए हैं, उससे तो ऐसा लगने लगा है, जैसे ईवीएम अब बाजार में बिकने लगी है। अब तक संपन्न हुए चुनावों में कुछ घटनाओं को लेकर चुनाव आयोग की किरकिरी हो रही है। एक के बाद एक ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, जिससे निर्वाचन आयोग के काम करने के तरीके पर सवाल उठने लगे हैं। सोशल मीडिया पर चुनाव आयोग को लेकर लगातार मीम्स शेयर किए जा रहे हैं और चुनाव आयोग को ट्रोल किया जा रहा है। दरअसल, कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं, जिससे ईवीएम और चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बीच चेन्नई में दो लोग स्कूटर पर रखकर ईवीएम ले जा रहे थे। कुछ लोगों ने देखा तो उन्हें रोक लिया और मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। इसी बीच डीएमके से जुड़े लोग भी वहां आ गए। उन्होंने आरोप लगाया कि इन ईवीएम से छेड़छाड़ करने के लिए इन्हें ले जाया जा रहा था। इस दौरान पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। हालात बिगड़ते दिखे तो पुलिस ईवीएम ले जा रहे लोगों को अपने साथ ले गई। घटना को लेकर लोगों में पुलिस के खिलाफ भी गुस्सा देखा गया। लोगों का आरोप था कि पुलिस ने ईवीएम ले जा रहे लोगों से पूछताछ तक नहीं की। वहीं असम का एक जिला है धीमा हसाओ, यहां के बूथ 107(ए) खोतलिर एलपी स्कूल पर 90 लोग मतदान करने के योग्य थे, लेकिन यहां 171 वोट गिरे। इस मामले को लेकर केंद्रीय चुनाव आयोग ने 5 पोलिंग अफसरों को सस्पेंड किया है। एक और मामले में 1 अप्रैल को असम में मतदान के बाद करीमगंज जिले की पथरकंडी विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी कृष्णेंदु पॉल की सफेद बोलेरो कार में ईवीएम मिली थी। हालांकि जो ईवीएम भाजपा पथरकंडी से भाजपा प्रत्याशी कृष्णेंदु पॉल की गाड़ी में मिली थी, वो राताबारी विधानसभा के पोलिंग 149 की है। कृष्णेंदु ने बताया था कि उनके भाई गाड़ी से आ रहे थे और रास्ते में किसी ने लिफ्ट मांगी तो उन्होंने दे दी, गड़बड़ी का मकसद नहीं था। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि भले ही ईवीएम और वीवीपैट जैसी चीजें सील बंद पाई गई हैं, लेकिन फिर भी बूथ नंबर 149 इंदिरा एमवी स्कूल पर दोबारा वोटिंग कराई जाएगी। इस मामले में पीठासीन अधिकारी और 3 अन्य अधिकारियों को सस्पेंड भी किया गया है और पीठासीन अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। पूछा गया है कि उन्होंने ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल का उल्लंघन क्यों किया? मामले में स्पेशल ऑब्जर्वर से रिपोर्ट भी तलब की गई है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में टीएमसी के एक नेता के घर पर चार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और लगभग इतनी ही संख्या में वीवीपैट मशीन मिलने के बाद एक चुनाव अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ईवीएम इतनी आसानी से लोगों को कैसे मिल रही है। क्या वाकई ईवीएम बाजार में बिक रही है। सवाल चिंतनीय है।

– राजेन्द्र आगाल

पाक्षिक अक्स

वर्ष 19, अंक 14, पृष्ठ-48, 16 से 30 अप्रैल, 2021

प्रकाशक एवं संपादक : राजेन्द्र आगाल

सम्पादकीय कार्यालय :
प्लाट नम्बर 150, जोन-1 मनोरमा कॉम्पलेक्स,
एफ-03, 04, प्रथम तल, एम.पी. नगर
भोपाल- 462011 (म.प्र.),
फोन नं. 0755-2557777, टेलीफेक्स - 0755-4017788
email : akshmagazine@gmail.com
W ebsite : www.akshnews.com
RNI NO. HIN/2002/8718 MPBPL/642/2021-23

ब्यूरो
मुंबई :- ऋतेन्द्र माथुर, **कोलकाता:**- इंद्रकुमार,
जयपुर:- आर.के. बिन्नानी, **छत्तीसगढ़:**- संजय शुक्ला, मार्केण्डेय तिवारी, टी.पी. सिंह, **लखनऊ :**- मधु आलोक निगम।

प्रदेश संवाददाता
094251 25096 (इंदौर) विकास दुबे
098276 18400 (जबलपुर) धर्मेन्द्र कथूरिया
094259 85070, (उज्जैन) श्यामसिंह सिकरवार
098934 77156, (विदिशा) ज्योत्सना अनूप यादव

क्षेत्रीय कार्यालय
नई दिल्ली : ईसी 294 माया इंक्लेव मायापुरी-फोन : 9811017939
जयपुर : सी-37, शांतिपथ, श्याम नगर (राजस्थान) मोबाइल-09829 010331
रायपुर : एमआईजी 1 सेक्टर-3 शंकर नगर, फोन : 0771 2282517
भिलाई : नेहरू भवन के सामने, सुपेला, रामनगर, भिलाई, मोबाइल 094241 08015
इंदौर : 39 श्रुत्रि सिलटर निपानिया, इंदौर मोबाइल - 7000123977

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक, राजेन्द्र आगाल द्वारा आगाल प्रिंटर्स, प्लाट नं. 150, जोन-1, प्रथम तल, एफ-03, मनोरमा काम्पलेक्स, एम.पी. नगर भोपाल 462011 (म.प्र.), से मुद्रित एवं प्रकाशित

इस अंक में प्रकाशित सामग्री लेखकों के अपने विचार हैं इनसे सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं हैं समस्त विवादों के लिए न्याय क्षेत्र भोपाल होगा।

पत्र–संपादक के नाम

aksnews.com

अवैध शराब पर रोक जरूरी

अवैध और अमानक शराब को लेकर मप्र की राजनीति का पारा भी गर्म है। प्रदेश में अवैध और अमानक शराब ने अब तक कई लोगों की जान ले ली है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और जल्द से जल्द अवैध व जहरीली शराब के कारोबार पर रोक लगानी चाहिए।

● **सुरेश मीना,** भोपाल (म.प्र.)

कैसे बनेगी स्मार्ट सिटी?

मप्र सहित देशभर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जारी है। प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट शुरुआत से ही विवादों के साये में रहा है। राजधानी भोपाल को देशभर में चमकाने के लिए सरकार लगातार प्रयास तो कर रही है लेकिन उसे और अधिक काम करने की जरूरत है।

● **विकास सोनी,** इंदौर (म.प्र.)

डकैतों का खौफ

हाल ही में कई ऐसी घटनाएं सामने आईं जिससे यह कहा जा सकता है कि बीहड़ में डकैत पनपने लगे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के कारण डकैत सक्रिय हो गए हैं। अगर ऐसा है तो यह सरकार के लिए एक सोचनीय विषय है।

● **वीरेंद्र सिंह,** उज्जैन (म.प्र.)

कोरोना में चुनाव

एक तरफ देशभर में कोरोना की मार पड़ी हुई है, दूसरी तरफ 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। चिंता की बात यह है कि चुनाव वाले राज्यों में पश्चिम बंगाल से कोरोना मामलों का लगातार ताजा अपडेट नहीं मिल रहा है। हाल में आई खबरों में कहा गया था कि पश्चिम बंगाल में कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है। जिसमें 500 से अधिक कोरोना के नए मामले आने की बात कही गई थी। ममता सरकार पर कोरोना के मामले छिपाने का आरोप भी लगता रहा है। बावजूद इसके इस चुनावी राज्य में कोरोना को लेकर संवेदनशील तरीके से नहीं निपटा जा रहा है। अगर कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं तो ऐसे माहौल में चुनाव कराना कहां तक उचित है।

● **आदर्श नागर,** शिवपुरी (म.प्र.)

केन–बेतवा परियोजना पर समझौता

एनडब्ल्यूडीए द्वारा देश में प्रस्तावित 30 नदी जोड़ो परियोजनाओं में से एक केन–बेतवा लिंक परियोजना भी है। इसकी अनुमानित लागत लगभग 45000 करोड़ है, जिसका 90 फीसदी केंद्र सरकार वहन करेगी। इस परियोजना में केन नदी से बेतवा नदी में पानी पहुंचाया जाएगा। इसके लिए दाऊधन डैम बनाया जाएगा और एक नहर के जरिए दोनों नदियों को जोड़ा जाएगा। केन–बेतवा लिंक परियोजना दो राज्यों मप्र और उप्र का संयुक्त प्रोजेक्ट है। संयुक्त परियोजना होने के कारण दोनों राज्यों के बीच पानी के बंटवारे का भी प्लान तैयार किया गया है।

● **रिचा शर्मा,** राजगढ़ (म.प्र.)

भूमाफियाओं पर कार्रवाई

मप्र में भूमाफियाओं का राज बढ़ते जा रहा है। कई जिलों में अतिक्रमण को लेकर आए दिन शिकायतें आती रहती हैं। इसी को लेकर सरकार भी ठोस कदम उठा रही है। मप्र में इन दिनों भूमाफिया के खिलाफ धनाधन कार्रवाई हो रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने अधिकारियों को साफ शब्दों में कह दिया है कि उन्हें माफियामुक्त प्रदेश चाहिए। इस बारे में वे कई बार मंच से भी बोल चुके हैं। जिससे लोगों के मन में भूमाफियाओं का खौफ कम हो रहा है।

● **प्राची गावटे,** गुना (म.प्र.)

पाठकों से निवेदन

कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं पक्ष या विपक्ष जो भी संभव हो इस पते पर भेजें

अक्स

150 जोन–1, मनोरमा काम्पलेक्स,
एफ–02, 03, एमपी नगर, भोपाल

चुनाव नतीजे तय करेंगे जी-23 का भविष्य

कांग्रेस में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा उन असंतुष्ट नेताओं के भविष्य पर होती है जिन्होंने पार्टी में भारी सुधारों की मांग करते हुए एक प्रकार से गांधी परिवार पर निशाना साध डाला है। पार्टी सूत्रों का दावा है कि यदि असम और केरल के नतीजे पार्टी के लिए सुखद रहते हैं, तो चुनाव बाद न केवल राहुल गांधी एक बार फिर से पार्टी अध्यक्ष बनेंगे, बल्कि इन असंतुष्ट नेताओं को भी पूरी तरह से ठिकाने लगा दिया जाएगा। हालांकि चर्चा इस बात की भी यहां लगातार हो रही है कि यदि नतीजे पार्टी के मनमाफिक नहीं रहे तो जी-23 में कुछ अन्य नेता भी शामिल हो, गांधी परिवार के खिलाफ मोर्चा खोल सकते हैं। जानकारों का दावा है कि गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल और भूपेंद्र हुड्डा को आने वाले समय में पार्टी के सभी महत्वपूर्ण पदों से हटाया जाना तय है। सूत्रों का यह भी कहना है कि पार्टी की परफॉरमेंस इन पांच राज्यों में जैसी भी रहे राहुल गांधी ही दोबारा अध्यक्ष पद संभालेंगे। खबर यह भी जोरों पर है कि यदि ऐसा हुआ तो जी-23 में शामिल कुछ बड़े चेहरे स्वयं की पार्टी छोड़ शरद पवार की एनसीपी का हिस्सा बन सकते हैं। इतना ही नहीं यह भी कहा-सुना जा रहा है कि बंगाल चुनाव यदि ममता बनर्जी जीत लेती हैं तो जी-23 समूह का पूरा प्रयास उन्हें 2024 में प्रधानमंत्री चेहरा बनाने का रहेगा।

बढ़ रही है एंटी योगी लहर

योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली को लेकर लंबे अर्से से पार्टी नेताओं की नाराजगी के समाचार सुनने को मिलते रहते हैं। आदित्यनाथ पर उनके ही विधायकों और सांसदों का आरोप है कि वे नौकरशाहों के भरोसे सरकार चलाते हैं जिसके चलते नौकरशाह सांसद-विधायक तो दूर की बात है, मंत्रियों तक के निर्देश नहीं मानते हैं। सत्ता गलियारों में इन सब बातों के चलते चर्चा जोरों पर है कि पांच राज्यों में चुनाव बाद भाजपा आलाकमान योगी आदित्यनाथ के पर कतरने जा रहा है। चर्चा इस बात की भी गर्म है कि उप्र के मुख्यमंत्री इन दिनों केंद्रीय गृहमंत्री तक की नहीं सुनते हैं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि इन दिनों योगी केवल पीएमओ और पार्टी अध्यक्ष की बातें सुनते हैं, बाकी बड़े नेताओं की कुछ भी नहीं चल पा रही है। ऐसे में पांच राज्यों के चुनाव बाद भाजपा आलाकमान कुछ ऐसा करने का मन बना चुका है जिससे न केवल योगी की ताकत और भौंकाल पर लगाम लगाई जा सके, साथ ही पार्टी के सांसद-विधायकों की नाराजगी भी राज्य में चुनावों से पहले दूर की जा सके।

अब सोरेन की बारी

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन दिनों खासे चिंतित बताए जा रहे हैं। कारण है राज्य की खुफिया पुलिस से मिल रही खबरें कि भाजपा उनकी सरकार को गिराने का जाल बुन रही है। दिसंबर 2019 में हुए विधानसभा चुनावों में हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, एनसीपी और सीपीआई (एमएल) गठबंधन को 50 सीटों पर जीत मिली थी तो भाजपा गठबंधन 30 सीटों पर सिमटकर रह गया था। जेएमएम के पास 29 विधायक, कांग्रेस के 18 बाकी तीन घटक दलों के एक-एक विधायक हैं। खबर गर्म है कि भाजपा के निशाने पर कांग्रेस के वे 12 विधायक हैं जिन्हें राज्य मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिल पाया है। इन 12 में से कम से कम 5 विधायकों को लेकर कांग्रेस आलाकमान निश्चिंत है कि वे किसी भी लोभ-लालच में फंसने वाले नहीं हैं। संकट उन सात विधायकों को लेकर है जो खरीदे जा सकते हैं। ऐसे विधायकों पर बकौल खुफिया पुलिस दबाव बनाया जा रहा है कि वे कांग्रेस विधान दल से बगावत कर विधानसभा में एक अलग गुट बनाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष पर दबाव बनाएं। यदि ऐसा हुआ तो दलबदल कानून लागू नहीं हो पाएगा। खबर है कि मुख्यमंत्री ने इस बाबत विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो संग लंबी मंत्रणा की है।

तीरथ से नाराज आलाकमान

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को राज्य की कमान सौंपे जाने के बाद भाजपा दिग्गजों के बीच इस बात की चर्चा सबसे ज्यादा होती है कि आखिर तीरथ के हाथों 'जैकपॉट' लगा कैसे? बहुतों का मानना है कि ऐसा गृहमंत्री अमित शाह के आशीर्वाद के चलते संभव हुआ है तो बहुत सारे ऐसे भी हैं जो उनका कनेक्शन सीधे प्रधानमंत्री मोदी से बताते घूम रहे हैं। पार्टी के एक बड़े नेता की माने तो तीरथ रावत को मुख्यमंत्री बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की रही है। इन महाशय का दावा है कि नड्डा ने ही सभी बड़े नेताओं की आपसी रार को भांप एक न्यूट्रल नेता के बतौर तीरथ को चुनने का सुझाव अमित शाह को दिया। बहरहाल अब चर्चा इस बात की गर्म है कि पार्टी आलाकमान नए मुख्यमंत्री के बयानों के चलते उपजे विवादों को लेकर तीरथ से खासा नाराज हैं। पार्टी सूत्रों की मानें तो आलाकमान की इस नाराजगी से तीरथ सिंह रावत को अवगत भी करा दिया गया है। सख्त हिदायत भी दी गई है कि वे सोच-समझकर बोलें।

जगन का संकट

आंधप्रदेश के मुख्यमंत्री जगन रेड्डी के लिए आने वाला समय खासा मुश्किलों भरा होने जा रहा है। 2012 में सीबीआई द्वारा भ्रष्टाचार के आरोप के चलते हिरासत में लिए गए रेड्डी पर मनी लॉन्ड्रिग से लेकर अपने पिता के शासनकाल में खनन पट्टे, सरकारी टेंडर आदि में भारी घोटाला करने के कई मामलों की जांच सीबीआई और ईडी कर रही है। हालांकि जगनमोहन रेड्डी इन आरोपों को अपने खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र कह खारिज करते आए हैं लेकिन धीरे-धीरे उन पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। रेड्डी ने पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश एनवी रमन्ना के खिलाफ बेहद संगीन आरोप लगाते हुए एक पत्र मुख्य न्यायाधीश को भेजा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पत्र पर कोई कार्यवाही न करने का फैसला ले लिया है। कोर्ट की एक 'आंतरिक जांच' में इन आरोपों को गलत पाया गया। चर्चाओं का बाजार गर्म है कि आने वाले दिनों में जगन रेड्डी के खिलाफ चल रहे मामलों में तेजी आ सकती है।

साहब की दरियादिली

प्रदेश की प्रशासनिक वीथिका में इन दिनों एक साहब की दरियादिली की खूब चर्चा हो रही है। दरअसल साहब कुछ संस्थाओं पर इस कदर मेहरबान दिन रहे हैं कि उन्हें मुंह मांगी आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रहे हैं। साहब की इस दरियादिली की पड़ताल की गई तो उसमें कुछ अलग ही कहानी निकलकर सामने आई। दरअसल, ये साहब 2000 बैच के प्रमोटी आईएएस अधिकारी हैं। साहब लक्ष्मीजी के लिए पत्थर पर दूब उगाने के लिए जाने जाते हैं। अगले एक साल में रिटायर होने वाले इस आईएएस अधिकारी को उनके कारनामों के कारण लूपलाइन भेजा गया था, लेकिन लूपलाइन में भी वे जमकर बैटिंग कर रहे हैं। इनके पास शिक्षण संस्थाओं को आर्थिक सहायता देने का काम है। साहब ने इसको भरपूर फायदा उठाना शुरू कर दिया है। उन्होंने अपने अधिकार का फायदा उठाते हुए लक्ष्मी कमाने के कई रास्ते खोल लिए हैं। यही नहीं साहब ने अपने विभागीय मंत्री को भी साफ-साफ शब्दों में कह दिया है कि मंत्रीजी को जो लेना है लें, लेकिन मैं तो 30 प्रतिशत से कम नहीं लेने वाला। अब साहब ने खुले हाथ से सौगात बांटकर अपना घर भरना शुरू कर दिया है। आलम यह है कि जिन संस्थाओं को पिछले साल 50 लाख मिले थे उन्हें 30 प्रतिशत के लिए डेढ़ करोड़ तक मिल रहे हैं। बताते हैं कि इसमें मंत्री का भी हिस्सा है। इसकी शिकायत ऊपर तक पहुंच गई है। देखना है अब क्या कार्रवाई होती है।

किस पर गिरेगी गाज

हर बात में अड़ंगा डालकर अपनी दाल गलाने के आदी हो चुके मप्र के कुछ आईएफएस केंद्र के निशाने पर हैं। दरअसल केंद्र का मानना है कि वन विभाग के अंतर्गत काम करने वाले ठेकेदारों के काम में अड़ंगा डालकर काली कमाई करने वाले अफसर इतने निडर हो गए हैं कि वे केंद्र सरकार की योजनाओं में भी रोड़ा अटका रहे हैं। मप्र के भारतीय वन सेवा के ऐसे ही कुछ अधिकारियों से केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बेहद नाराज हैं। उनका मानना है कि मप्र में प्रस्तावित नेशनल हाईवे के निर्माण में वन विभाग अधिकारी सबसे ज्यादा अड़ंगे लगा रहे हैं। वन क्षेत्र से गुजरने वाले हाईवे को अनुमति देने के मामले में जानबूझकर देरी की जा रही है। खबर आ रही है कि गडकरी ने अपने विभाग से मप्र कैडर के उन आईएफएस अधिकारियों की सूची मांगी है जो अड़ंगे लगाने में माहिर हैं। गडकरी इन अफसरों को वीआरएस (जबरिया रिटायर) दिलाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार से चर्चा करेंगे। खबर यह भी है कि इस संबंध में गडकरी का एक पत्र वल्लभ भवन पहुंच गया है।

जुगाड़ काम आ गई

यह विश्व विख्यात है कि भारत में जुगाड़ से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। बात 100 फीसदी सही भी है। इसी जुगाड़ का फायदा उठाकर मप्र कैडर के एक आईएएस अधिकारी ने अपनी मंशा पूरी कर ली है। दरअसल, 2001 बैच के ये आईएएस अधिकारी हमेशा से लाइम लाइट में रहने के आदी हैं। उन्होंने अपने अब तक के शासनकाल में कई महत्वपूर्ण पदों को सुशोभित किया है। लेकिन वर्तमान सरकार बनने के बाद से किनारे कर दिए गए। तब से ही ये साहब सरकार के मुखिया के नजदीक पहुंचने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन बताते हैं कि सरकार के मुखिया इस अधिकारी से बेहद नाराज थे। जबकि माननीय पिछले कार्यकाल में इन साहब पर काफी भरोसा करते थे। बताते हैं कि विपक्षी पार्टी की सरकार में उक्त अधिकारी ने जिस तरह रंग बदल लिया था, उससे उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगे। अब सत्ता परिवर्तन के बाद से ही सरकार के मुखिया ने इन साहब के पर काटते हुए इनसे दूरी बना ली थी। उधर, साहब सरकार के करीब आना चाहते थे। इसके लिए पिछले 6 महीने से उनसे मिलने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन नहीं मिल पा रहे थे। अचानक अधिकारी को ऐसी जुगाड़ हाथ लगी जिसके जरिए उन्हें फिलहाल ऐसा काम मिल गया है जिससे वे सरकार के मुखिया की बैठकों में शामिल हो सकें। देखते हैं कि बैठकों के जरिए यह अधिकारी सरकार का विश्वास फिर से हासिल कर पाते हैं या नहीं?

मजबूती के लिए समझौता

मप्र में कांगेस सत्ता से इसलिए बाहर हो गई कि पार्टी के दिग्गज नेताओं में एकता कायम नहीं रह पाई। वर्तमान में भी पार्टी खंड-खंड है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ आजकल पार्टी के दो नेताओं के बीच समझौता कराने का प्रयास कर रहे हैं। बताते हैं कि इस मामले में उन्हें काफी सफलता भी मिलती दिख रही है। प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह नहीं चाहते थे कि भाजपा में गए पूर्व उपनेता प्रतिपक्ष राकेश सिंह कांग्रेस में वापस आएं। लेकिन राकेश सिंह की कांग्रेस में सम्मानजनक वापसी हो गई। कांग्रेस में आने के बाद भी अजय सिंह का विरोध जारी रहा। यही कारण है कि उन्हें मेहगांव से कांग्रेस का टिकट नहीं मिल पाया। कमलनाथ ने अब इन दोनों नेताओं के बीच समझौता कराने के प्रयास तेज कर दिए हैं। दरअसल कमलनाथ चाहते हैं कि राकेश सिंह को ग्वालियर-चंबल संभाग में कांग्रेस के ब्राह्मण चेहरे के रूप में उभारा जाए। उन्होंने इसके लिए डॉ. गोविंद सिंह को लगभग सहमत कर लिया है। बताते हैं कि अजय सिंह के भी विरोधी तेवर पहले से ढीले पड़ गए हैं। अब देखना यह है कि मजबूती के लिए समझौता हो पाता है या नहीं।

राजनीतिक भविष्य की चिंता

कहा जाता है कि राजनीति ऐसी लत है जो छूटे नहीं छूटती है। यही कारण है कि नेताओं को हर समय अपने राजनीतिक भविष्य की चिंता सताती रहती है। वर्तमान में मप्र की दो नेत्रियों को अपने भविष्य की चिंता सता रही है। एक समय मप्र की तेज तर्रार भाजपा नेत्री रहीं उमा भारती और कुसुम मेहदेले आजकल राजनीतिक बियाबान में हैं। उमा भारती का दिल्ली से मोहभंग हो चुका है और वे मप्र में सक्रिय होना चाहती हैं। इसके लिए उन्होंने शराबबंदी को मुद्दा बनाने की कोशिश शुरू कर दी है। यद्यपि उनका यह अभियान धार नहीं पकड़ पा रहा है। दूसरी ओर कुसुम मेहदेले ने स्वयं को चर्चा में लाने अपनी ही सरकार की महत्वाकांक्षी योजना केन-बेतवा लिंक परियोजना का विरोध शुरू कर दिया है। खास बात यह है कि मेहदेले और उमा भारती ने अपनी बात संगठन में करने की बजाय मीडिया में करना शुरू कर दिया है। यह तय है कि फिलहाल न तो सरकार और न ही प्रदेश भाजपा संगठन इन दोनों महिलाओं को गंभीरता से ले रहा है। ऐसे में ये दोनों मीडिया और जनता के रास्ते अपनी पैठ बढ़ा रही हैं।

असली भारत गांवों में है। इसलिए मैं गांवों की तस्वीर बदलना चाहती हूं। इसलिए अब पंचायत चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रही हूं। मैं राजनीति में रोल मॉडल बनने के लिए गांव की कच्ची-पक्की डगर से लेकर खेत-खलिहानों में घूम रही हूं।

● **दीक्षा सिंह**

जो लोग आज सत्ता में बैठे हैं, इन्होंने देश की आजादी के लिए अंगुली तक नहीं कटवाई। ये लोग अंग्रेजों से मिले हुए नहीं थे क्या? अंग्रेजों की भाषा बोलते थे। आज ये कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। आज सत्ता में बैठे लोगों पर लोकतंत्र की कृपा है। कांग्रेस ने देश में लोकतंत्र कायम रखा। इसलिए आज ये लोग सत्ता में बैठे हैं।

● **अशोक गहलोत**

आईपीएल ने क्रिकेट को बड़ा बना दिया है। आज आईपीएल के कारण भारत के पास न केवल विश्व की सबसे मजबूत टीम है, बल्कि बेंच भी कई देशों की टीम से मजबूत है। भारत ही नहीं बल्कि कई देशों के अच्छे खिलाड़ी इस टूर्नामेंट से उभरे हैं। आज आईपीएल का महत्व अन्य देशों में चलने वाले इस तरह के आयोजन से अधिक है।

● **वीवीएस लक्ष्मण**

ममता दीदी बंगाल की जनता आपके खिलाफ इसलिए है क्योंकि यहां पर घुसपैठ बिना रोकटोक के हो रही है। जनता आपके खिलाफ इसलिए है कि जो लाखों-करोड़ों शरणार्थी आए हैं, उनको नागरिकता देने का कानून सीएए मोदीजी लेकर आए, और आप विरोध कर रही हैं।

● **अमित शाह**

मैं कोरोना पॉजिटिव हो गई हूं। यह सब बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और निराशाजनक है। लेकिन एक्टिंग आपको धैर्य रखना सिखाता है। हम 2019 से फिल्म की शूटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें महामारी के कारण कई बार शेड्यूल को रोकना पड़ा। हमने पिछले साल दिसंबर में शूटिंग फिर से शुरू की, लेकिन बॉस्को कोविड पॉजिटिव हो गए थे। इसके बाद आदित्य संक्रमित हुए और अब मैं कोविड पॉजिटिव हो गई हूं। कुछ सीन्स की शूटिंग के दौरान सोशल डिस्टेंस बनाए रखना मुश्किल होता है। एक्टर्स शूटिंग के दौरान मास्क भी नहीं पहन सकते हैं। हमारी सेफ्टी क्रू-मेंबर्स के कंधों पर टिकी हुई है। सैनिटाइजर, मास्क और टेंपरेचर चेक जैसी सभी सावधानियों के बाद भी लोग इस वायरस से संक्रमित हो रहे हैं।

● **निकिता दत्ता**

वाक्युद्ध

जहां किसान मीटिंग करना चाहता है वहां कोरोना है, जहां चुनाव है वहां कोरोना नहीं है। पश्चिम बंगाल इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए पार्टियां रैली कर रही हैं और भारी भीड़ के बीच प्रचार में जुटी हुई हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कोरोना भीड़ से डर रहा है या आंकड़े छुपाए जा रहा है।

● **राकेश टिकैत**

किसानों को भ्रम में डालकर अपनी राजनीति जमीन बनाने में जुटे राकेश टिकैत पहले यह तो बताएं कि जब वे बैठकें और सभाएं कर रहे हैं तो वहां कोरोना नहीं फैल रहा है। अब किसान उनकी मंशा भांप गया है। इसलिए धरना स्थल खाली होते जा रहे हैं। टिकैत भी जल्द ही कृषि बिल को किसान हितैषी करार दे देंगे।

● **संबित पात्रा**

मप्र में इस बार धान की रिकॉर्ड खरीदी हुई है। ऐसे में सरकार की कोशिश है कि प्रदेश में अच्छी क्वालिटी का चावल तैयार किया जाए। लेकिन सरकार की राह में धान मिलर्स मुसीबत बने हुए हैं। ऐसे में सरकार ने बाहरी मिलर्स को ऑफर दिया है।

धान मिलर्स बने मुसीबत

मप्र की शिवराज सरकार के लिए अब धान मिलर्स मुसीबत बन गए हैं। वे अपनी जिद छोड़ने को तैयार नही हैं, तो सरकार भी अपनी जिद पर अड़ी हुई है। इसकी वजह से प्रदेश में अब तक धान से चावल निकालने का काम शुरू नहीं हो पाया है। इसकी वजह से सरकार को दोहरी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। पहला सरकार केंद्रीय पूल में अपने हिस्से का चावल नहीं दे पा रही है, दूसरा धान नहीं उठने की वजह से गेहूं खरीदी के इस मौसम में गोदाम खाली नहीं हो पा रहे हैं। दरअसल मिलर्स और सरकार के बीच कई दौर की बात हो चुकी है, लेकिन कोई फैसला नहीं हो पाया है। इस बीच अब सरकार ने तय किया है कि अगर मिलर्स अपनी जिद नहीं छोड़ते हैं तो बाहरी मिलर्स को बुलाकर धान से चावल निकालने का काम सौंप दिया जाएगा।

उधर सरकार ने प्रदेश के मिलर्स की परेशानी को देखते हुए धान मिलिंग के भाव दोगुना करने के साथ ही अन्य तरह के दामों में भी वृद्धि कर दी है। इसके बाद भी मिलर्स अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। बाहरी मिलर्स को बुलाने के लिए कैबिनेट की उप कमेटी की बैठक में इसको लेकर फैसला कर लिया गया है। इस कमेटी का गठन खरीफ वर्ष 2020-21 में धान उपार्जन एवं निस्तारण के लिए किया गया था। समिति की बैठक में सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने कहा कि अन्य राज्यों की तुलना में 100 एवं 200 की वृद्धि व्यवहारिक रूप से बहुत अधिक है। अब इसके लिए दूसरे राज्यों के मिलर्स को बुलाया जाना चाहिए। उनका कहना है कि जहां तक टूटन का प्रश्न है तो टूटन अन्य राज्यों में भी होती है। इसके बाद भी इस तरह के दबाव बनाना ठीक नहीं है।

खरीफ वर्ष 2020-21 के लिए धान उपार्जन एवं निस्तारण के लिए प्रदेश के बाहर के मिलर्स को आमंत्रित किया जाएगा। धान एवं निस्तारण के लिए गठित मंत्री-मंडलीय उप समिति की बैठक में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने बताया कि इस संबंध में शीघ्र ही विज्ञापन जारी कर मिलर्स को आमंत्रित किया जाएगा। समिति की बैठक में वितमंत्री जगदीश देवड़ा, कृषि मंत्री कमल पटेल, सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया, आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार एवं जल संसाधन राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने वर्चुअली भाग लिया।

खाद्य मंत्री सिंह ने बताया कि विगत दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ हुई चर्चा में मिलर्स द्वारा प्रोत्साहन राशि को 25 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 50 रुपए किए जाने का अनुरोध किया था। मुख्यमंत्री चौहान द्वारा प्रोत्साहन राशि 50 रुपए प्रति क्विंटल कर दी। बाद में मिलर्स द्वारा धान के टूटन का हवाला देते हुए नुकसान के कारण मिलिंग में रूचि नहीं लेते हुए इसे 100 एवं 200 रुपए प्रति क्विंटल किए जाने की मांग की है। मंत्री सिंह ने बताया कि अन्य राज्यों में मिलर्स को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि में उप्र में 20 रुपए प्रति क्विंटल, छत्तीसगढ़ में अरवा और उष्णा चावल के लिए 20, 40 और 45 रुपए प्रति क्विंटल, आंध्र प्रदेश में सार्टेक्स चावल के लिए 60 एवं अच्छे चावल के लिए 50 रुपए प्रति क्विंटल की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाती है। सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने कहा कि अन्य राज्यों की तुलना में 100 एवं 200 रुपए की राशि व्यवहारिक रूप से बहुत अधिक है। उन्होंने कहा कि मिलिंग के लिए अन्य राज्यों के मिलर्स को आमंत्रित किया जाना चाहिए। जहां तक टूटन का प्रश्न है टूटन अन्य राज्यों में भी होगी।

प्रदेश के धान मिलर्स को प्रोत्साहित करने के लिए इस बीच राज्य सरकार द्वारा कई तरह के कदम उठाए जा चुके हैं। इसमें समय सीमा में धान उपार्जन के दौरान मिलिंग शुरू करने के लिए नई नीति बनाकर प्रोत्साहन राशि को दोगुना कर दिया गया है। यही नहीं प्रतिभूति राशि को भी 60 से 70 फीसदी कर दिया गया है। इसी तरह से मिलर्स के लिए परिवहन की दरें भी तय कर दी गई हैं। धान की लोडिंग अनलोडिंग करने के लिए भी नई दर जारी की गई हैं। खास बात यह है कि अन्य राज्यों में मिलर्स को प्रोत्साहन राशि में क्रमशः उप्र में 20 रुपए प्रति क्विंटल, छत्तीसगढ़ में 18 से 20 रुपए अरवा और उसना चावल के लिए 20 से 45 प्रति क्विंटल, जबकि आंध्र प्रदेश में सारटेक्स चावल के लिए 60 एवं अच्छे चावल के लिए 50 प्रति क्विंटल इधर से प्रोत्साहन राशि दी जाती है। जबकि मप्र में अभी कुछ दिन पहले ही यह राशि 25 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए की जा चुकी है।

● राकेश ग्रोवर

राशि का भी संकट

दरअसल प्रदेश से बड़ी मात्रा में चावल सेंट्रल पूल में दिया जाता है। इसके एवज में ही सरकारों द्वारा समर्थन मूल्य पर धान का उपार्जन किया जाता है। जब चावल की सप्लाई हो जाती है तो उसके एवज में धान खरीदी का पैसा केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को भुगतान कर दिया जाता है। ऐसे में अगर जब चावल की सप्लाई ही नहीं की जाएगी तो केंद्र से मिलने वाली राशि भी नहीं मिलेगी। इस वजह से पहले से ही आर्थिक संकट का सामना कर रही प्रदेश सरकार के सामने राशि का बड़ा संकट बना हुआ है।

संसद में अपनी पुअर परफॉर्मेंस के लिए बदनाम मप्र के माननीयों ने 17वीं लोकसभा के दूसरे बजट सत्र में अपनी परफॉर्मेंस का लोहा मनवाया है। 29 जनवरी से 25 मार्च तक चले संसद के बजट सत्र में मप्र के 29 सांसदों में से अधिकांश ने बेहतर प्रदर्शन किया है। ओवरऑल देखा जाए तो मप्र के माननीय देश में अव्वल रहे।

मप्र के माननीय सबसे अव्वल

देश के सांसदों का अब तक के कार्यकाल के दौरान लोकसभा से लेकर धरातल तक कैसा प्रदर्शन रहा है, इसे लेकर रेटिंग और रैंकिंग जारी हुई है। पार्लियामेंट्री बिजनेस डॉट कॉम द्वारा जारी सूची का आंकलन करने पर मप्र के सांसदों की परफॉर्मेंस अन्य राज्यों के सांसदों से बेहतर रही है। ओवरऑल परफॉर्मेंस में मप्र के 7 सांसद टॉप 50 में शामिल हुए हैं। उज्जैन के भाजपा सांसद अनिल फिरोजिया 8वें स्थान पर हैं।

वर्तमान में देश के 539 लोकसभा सांसदों में से मप्र के 29 सांसदों में से 28 सांसदों (स्व. नंदकुमार सिंह चौहान को छोड़कर) की लोकसभा में उपस्थित, प्रश्न, वाद-विवाद, गैर सरकारी विधेयक, संसदीय क्षेत्र में उपस्थिति, विकास कार्यों में रूचि, जन समस्याओं के प्रति गंभीरता, सार्वजनिक छवि के आधार पर परफॉर्मेंस का आंकलन करने पर यह तथ्य सामने आया है कि इस बार मप्र के सांसदों ने बेहतर प्रदर्शन किया है।

दरअसल, आम लोग अपने जन प्रतिनिधियों का संसद से लेकर धरातल पर कार्य प्रदर्शन कैसा रहा है, यह जानने के लिए पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने पार्लियामेंट्री बिजनेस डॉट कॉम वेबसाइट का लोकार्पण किया था। यह वेबसाइट देशभर के सांसदों पर नजर रखने के लिए पहरेदार के तौर पर मैदान में काम कर रही है। ये न केवल संसद में उनके कार्य प्रदर्शन की निगरानी रख रही है, साथ ही इस आधार पर उन्हें रेटिंग और रैंकिंग जारी कर रही है। मकसद है इससे जनप्रतिनिधियों की जनता के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। यह वेबसाइट सांसदों की लोकसभा में उपस्थित, प्रश्न, वाद-विवाद, गैर सरकारी, विधेयक, सांसद निधि, संसदीय क्षेत्र में उपस्थिति, विकास कार्यों में रूचि, जन समस्याओं के प्रति गंभीरता, सार्वजनिक छवि के आधार पर रैंकिंग जारी करती है। इस वेबसाइट के आंकड़ों के अनुसार इस बार मप्र के सांसदों ने लोकसभा में उपस्थिति, सवाल पूछने, डिबेट और पब्लिक रेटिंग में अपना लोहा मनवाया है। गौरतलब है कि एक वर्ष पूर्व जब मप्र के सभी 29 सांसदों की परफॉर्मेंस का आंकलन हुआ था तो वे देश में फिसड्डी साबित हुए थे। उसके बाद भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व, संघ ने सांसदों पर नकेल कसी। इसलिए इस बार मप्र के सांसदों की परफॉर्मेंस बेहतर हुई है। गौरतलब है कि वर्तमान समय में प्रदेश के 28 सांसदों में से 27 भाजपा के हैं।

गौरतलब है कि सांसदों को उनके कार्य के आधार पर क्षेत्र की जनता द्वारा 5 मापदंडों के अंतर्गत रेटिंग दी जाती है। जिसमें क्षेत्र के विकास में योगदान, जनता के बीच सांसद की इमेज कैसी है, सांसद की क्षेत्र में उपस्थिति, स्थानीय मुद्दों के प्रति गंभीरता तथा जनता की समस्याएं निपटाने के आधार पर रेटिंग में मप्र के 13 सांसदों ने अपना लोहा मनवाया है। नरेंद्र सिंह तोमर की लोकप्रियता कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलनरत किसानों से चर्चा के कारण और बढ़ी है। तोमर को सरकार ने इस आंदोलन को मैनेज करने की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं खजुराहो सांसद तथा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने अपनी सक्रियता तथा कार्यप्रणाली से लोकप्रियता हासिल की है। कांग्रेस के एकमात्र सांसद नकुलनाथ ने भी इस बार अच्छा प्रदर्शन किया है। इनकी पब्लिक रेटिंग 4.3 है।

अनिल फिरोजिया टॉप-10 में

संसद और सांसदों के कामकाज पर केंद्रित वेबसाइट 'पार्लियामेंट्री बिजनेस डाट कॉम' के अध्ययन के मुताबिक मप्र के 29 सांसदों में से 7 सांसद ऐसे हैं जो देश में ओवरऑल टॉप 50 में जगह बना पाए हैं। इनमें उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया 8वें स्थान पर आए हैं और देश के टॉप-10 बेहतर सांसदों में शुमार हुए हैं। इनके अलावा जनार्दन मिश्रा 13वें नंबर पर, उदयप्रताप सिंह 26वें नंबर पर, महेंद्र सिंह सोलंकी 38वें नंबर पर, प्रज्ञा सिंह ठाकुर 40वें नंबर पर, छतरसिंह दरबार 43 नंबर पर और गणेश सिंह 46वें नंबर पर आए हैं। मप्र के जो 7 सांसद टॉप 50 में शामिल हैं, उनमें से अनिल फिरोजिया, महेंद्र सिंह सोलंकी और प्रज्ञा सिंह ठाकुर पहली बार सांसद बने हैं। वहीं जनार्दन मिश्रा, सुधीर गुप्ता दूसरी बार, उदयप्रताप सिंह और छतरसिंह दरबार तीसरी बार तथा गणेश सिंह चौथी बार सांसद बने हैं। इन सांसदों ने सदन से लेकर अपनी संसदीय क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है।

17वीं लोकसभा का दूसरा साल अभी पूरा नहीं हुआ है। लेकिन मप्र के भाजपा सांसदों की परफॉर्मेंस से आरएसएस गदगद है। भाजपा सूत्रों का कहना है कि सांसद बनने के एक साल के दौरान मप्र के सांसदों की परफॉर्मेंस चिंताजनक थी। उस दौरान संसद में उनकी गतिविधियों, संसदीय क्षेत्र में उनकी सक्रियता और विकासात्मक कार्यों के आधार पर आंकलन करने पर यह तथ्य सामने आया था कि प्रदेश के एक भी सांसद का प्रदर्शन औसत दर्जे का भी नहीं था। सांसदों की परफॉर्मेंस को पांच कैटेगिरी में बांटकर आंकलन किया गया था। पहली कैटेगिरी एक्सीलेंस की थी। इसमें वे सांसद शामिल किए गए थे जिनका ओवरऑल परफॉर्मेंस 90 प्रतिशत से ऊपर रहा। उसके बाद गुड की कैटेगिरी में 65 से लेकर 90 प्रतिशत वाले, एवरेज कैटेगिरी में 35 से 65 प्रतिशत वाले, औसत से नीचे की कैटेगिरी में 35 प्रतिशत से नीचे वाले और 0 प्रतिशत वाले नॉन परफॉर्मर की कैटेगिरी में। मप्र के 5 सांसद नॉन फरफॉर्मर रहे थे, वहीं 20 औसत से नीचे की कैटेगिरी में। लेकिन इस बार मप्र भाजपा के लगभग सभी सांसदों ने किसी न किसी कैटेगिरी में अपना लोहा मनवाया है।

जानकारी के अनुसार, संघ ने जनवरी 2020 में अपने अनुषांगिक संगठनों से भाजपा के सभी 303 सांसदों की परफॉर्मेंस का आंकलन करवाया था। अनुषांगिक संगठनों ने संसदीय क्षेत्र में सांसदों की सक्रियता, उनके द्वारा अनुमोदित विकास कार्यों, सांसद निधि के उपयोग, सांसद आदर्श ग्राम की स्थिति, केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रचार-प्रसार और सांगठनिक गतिविधियों में भागीदारी के आधार पर परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार की थी। इसमें सबसे पुअर परफॉर्मेंस मप्र के सांसदों की रही थी। उसके बाद संघ ने भाजपा संगठन के साथ मिलकर सांसदों के लिए कार्यक्रम तैयार करवाया। उस कार्यक्रम के साथ सांसदों को उनके संसदीय क्षेत्र में सक्रिय किया गया। साथ ही संसद में उपस्थित रहने और संसदीय गतिविधियों में शामिल रहने की हिदायत भी दी गई थी। उसके बाद सांसदों की बेहतर परफॉर्मेंस सामने आई है।

17वीं लोकसभा के दूसरे बजट सत्र के दौरान मप्र के 28 सांसदों में से अधिकांश ने संसद में अपनी सक्रियता का प्रदर्शन किया। सांसदों ने सवाल पूछने और डिबेट में बेहतर प्रदर्शन किया है। संसदीय क्षेत्र में भी इनकी सक्रियता बराबर बनी रही। वहीं कुछ सांसद ऐसे भी रहे जिनका इस बार प्रदर्शन ठीक नहीं रहा। सूत्र बताते हैं कि भाजपा का केंद्रीय संगठन ऐसे सांसदों को एक बार फिर से अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करने की सीख देगा। इस बार जिन सांसदों की संसद से लेकर सड़क तक अच्छी परफॉर्मेंस रही उनमें डॉ. वीरेंद्र कुमार, विष्णुदत्त शर्मा, गणेश सिंह, जनार्दन मिश्रा, रीति पाठक, हिमादी सिंह आदि का भी नाम शामिल है। वहीं कई सांसद ऐसे रहे जिनकी सदन में उपस्थिति 100 फीसदी रही। गुना सांसद केपी यादव प्रदेश की संसद में परफॉर्मेंस अच्छी रही और उनकी उपस्थिति 100 प्रतिशत रही। इन्होंने सदन में 40 सवाल पूछे हैं। सवाल पूछने में इनकी परफॉर्मेंस 27.59 प्रतिशत रही, तो ये 9 डिबेट में शामिल हुए। पब्लिक रेटिंग में इनको कोई अंक नहीं मिला है।

वहीं शहडोल सांसद हिमाद्री सिंह की संसद में उपस्थिति 100 प्रतिशत रही है। सवाल पूछने में इनकी परफॉर्मेंस 10.34 प्रतिशत रही, यानी इन्होंने 15 सवाल पूछे। वहीं ये 2 डिबेट में शामिल हुईं। इनकी पब्लिक रेटिंग 3 प्रतिशत रही। जबलपुर सांसद राकेश सिंह की संसद में उपस्थिति 100 प्रतिशत रही। वहीं सवाल पूछने में इनकी परफॉर्मेंस 20 प्रतिशत रही। इन्होंने सदन में 29 सवाल पूछे। वहीं ये 5 डिबेट में शामिल हुए। इनकी पब्लिक रेटिंग शून्य रही। सातवीं बार टीकमगढ़ सांसद बने वीरेंद्र कुमार की संसद में उपस्थिति 100 प्रतिशत रही। वहीं इन्होंने सदन में एक भी सवाल नहीं पूछा है। इन्होंने 16 डिबेट में भाग लिया। क्षेत्र में अच्छी पकड़ के बाद भी विकास कार्य करवाने में इन्होंने कंजूसी दिखाई है। इनकी पब्लिक रेटिंग शून्य है। खजुराहो सांसद वीडी शर्मा की संसद में उपस्थिति 55.17 प्रतिशत रही। इन्होंने सदन में एक भी सवाल नहीं पूछा, जबकि 2 डिबेट में शामिल हुए। इनकी पब्लिक रेटिंग 2.5 प्रतिशत रही।

सतना सांसद गणेश सिंह की संसद में उपस्थित 79.31 प्रतिशत रही। इन्होंने सदन में 19 सवाल पूछे और इनका परफॉर्मेंस 13.1 प्रतिशत रहा। इन्होंने 7 डिबेट में भाग लिया। वहीं इनकी पब्लिक रेटिंग 4.01 प्रतिशत है। भाजपा के अन्य सांसदों की अपेक्षा इन्होंने अपने क्षेत्र में विकास कार्य सबसे अधिक करवाया है। दरअसल, इन्होंने अपने पिछले कार्यकाल के अंतिम दिनों में कई विकास कार्यों के लिए फंड आवंटित किया था, जिससे उनकी इस पारी में काम हुए हैं। सागर सांसद राजबहादुर सिंह की संसद में उपस्थिति 82.76 प्रतिशत रही। वहीं सवाल पूछने और डिबेट में इनकी परफॉर्मेंस शून्य रही। हालांकि क्षेत्र में ये सक्रिय हैं लेकिन इनकी विकास कार्य में भागीदारी चिंतनीय है। इनकी पब्लिक रेटिंग भी चिंतनीय है। वहीं छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ की संसद में उपस्थिति 72.41 प्रतिशत रही है। इन्होंने 1 भी सवाल नहीं पूछा है। ये 1 डिबेट में भी शामिल नहीं हुए हैं। इनकी पब्लिक रेटिंग 4.3 प्रतिशत रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस बार के बजट सत्र में मप्र के लगभग सभी सांसदों ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। अपने सांसदों की परफॉर्मेंस से भाजपा संगठन के साथ ही आरएसएस भी खुश है। आगामी दिनों में माननीयों के परफॉर्मेंस पर और काम होगा।

● **कुमार राजेन्द्र**

तोमर, प्रज्ञा, सुधीर, वीडी ने मनवाया लोहा

देश के लोकप्रिय सांसदों में मप्र के 13 सांसद शामिल हैं। इस बार केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, भोपाल की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर, मंदसौर सांसद सुधीर गुप्ता ने पब्लिक रैंकिंग में पूरे 5 अंक हासिल करके अपना लोहा मनवाया है और देश के लोकप्रिय सांसदों में स्थान पाया है। पब्लिक रैंकिंग में राजस्थान के नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल देश में नंबर-1 स्थान पर हैं। अगर मप्र की बात करें तो सतना सांसद गणेश सिंह 11वें स्थान पर, सीधी सांसद रीति पाठक 67 स्थान पर रहीं। वहीं इंदौर सांसद शंकर लालवानी, रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा, खजुराहो सांसद वीडी शर्मा, गजेंद्र सिंह पटेल, रमाकांत भार्गव, हिमाद्री सिंह, नकुलनाथ, छतरसिंह दरबार ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। अपने खराब स्वास्थ्य के बावजूद भोपाल की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर लगातार सक्रिय रहीं। पहले वर्ष में जहां वे देश की सबसे फिसड्डी सांसद रहीं। वहीं दूसरे वर्ष में उन्होंने न केवल अपनी परफॉर्मेंस में सुधार किया है, बल्कि जनता के बीच लोकप्रियता भी बटोरी है।

क्या पूरा होगा सिंधिया का सपना?

ठीक एक साल पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ भाजपा का दामन थामा था। कांग्रेस में 18 साल लंबी पारी खेलने के बाद जब अपने समर्थकों के साथ उन्होंने भगवा पार्टी ज्वॉइन की थी तो यही लगा था कि अब वे प्रदेश की राजनीति में ज्यादा सक्रिय भूमिका निभाएंगे। कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने पहले मुख्यमंत्री और फिर प्रदेश अध्यक्ष पद पर इसीलिए दावा ठोंका था, लेकिन कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जोड़ी ने उनके इरादे सफल नहीं होने दिए। उनके भाजपा में जाने के बाद समर्थकों को उम्मीद थी कि सिंधिया अब मप्र में रहकर अपनी राजनीति को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन लगता है भाजपा भी उन्हें वैसे ही इस्तेमाल कर रही है, जैसे कांग्रेस करती थी। राज्य की राजनीति से दूर रखकर उन्हें केंद्रीय राजनीति में व्यस्त रखने का कांग्रेसी फॉर्मूला भाजपा भी आजमाती हुई दिख रही है।

पिछले साल नवंबर में मप्र में विधानसभा की 28 सीटों पर हुए उपचुनाव के बाद से सिंधिया मप्र से लगातार दूर हो रहे हैं। उपचुनाव में वे पार्टी के स्टार प्रचारक थे। उनकी अधिकांश चुनावी सभाओं में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा के दूसरे बड़े नेता उनके साथ होते थे। इसका एक बड़ा कारण यह था कि उपचुनाव में अधिकांश सीटों पर उनके समर्थक ही भाजपा के उम्मीदवार थे, लेकिन नतीजे आने के बाद से उनका अधिकांश समय दिल्ली में ही गुजरा है। पार्टी की ओर से उन्हें प्रदेश में कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। सिंधिया के भाजपा ज्वॉइन करने के बाद उन्हें नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मंत्री बनाने की चर्चाएं थीं, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ। उनके समर्थकों को भाजपा के प्रदेश संगठन में जगह देने की बात भी हुई, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष डी शर्मा की टीम में उनके एक भी समर्थक को शामिल नहीं किया गया। पार्टी में किसी बड़ी जिम्मेदारी का इंतजार कर रहे सिंधिया को भाजपा ने बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट में जगह दी है।

रोचक यह है कि भाजपा ने मप्र के दमोह में 17 अप्रैल को होने वाले उपचुनावों के लिए स्टार प्रचारकों में भी उन्हें रखा है, लेकिन गत दिनों जब पार्टी उम्मीदवार राहुल सिंह ने नामांकन भरा तो इसमें सिंधिया शामिल नहीं थे। राहुल ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की मौजूदगी में नॉमिनेशन किया। यह भाजपा की ओर से एक और संकेत है कि पार्टी उन्हें मप्र से दूर रखने की रणनीति पर काम कर रही है। भाजपा के पास मप्र में नेताओं की भरमार है। शिवराज सिंह चौहान चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं तो कैलाश विजयवर्गीय, नरोत्तम मिश्रा, गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह जैसे कई नेता हैं जो आगे चलकर उनके विकल्प बन सकते हैं। भाजपा इनके बीच सिंधिया को उतारकर राज्य में सत्ता संतुलन को अस्थिर नहीं करना चाहती। सिंधिया के राज्य में सक्रिय होते ही भाजपा के इन नेताओं में असंतोष पैदा होने का खतरा है। भाजपा ऐसा कोई खतरा मोल लेने के पक्ष में नहीं है और सिंधिया को इस कारण ही राज्य में बड़ी जिम्मेदारी देने से परहेज कर रही है।

इस सबके बीच सिंधिया दोराहे पर खड़े हैं। वे कई बार मप्र का मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जता चुके हैं। उनके समर्थक भी यह इच्छा जता चुके हैं, लेकिन कांग्रेस में रहते हुए उनकी यह हसरत पूरी नहीं हुई और भाजपा में भी फिलहाल उनकी इच्छा पूरी होती नहीं दिख रही। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि पिता माधवराव सिंधिया की तरह ज्योतिरादित्य का यह सपना भी कहीं अधूरा तो नहीं रह जाएगा।

मप्र में व्यापक स्तर पर दलबदल के बाद भाजपा में आंतरिक हलचल का दौर जारी है। जैसा कि पहले कयास लगाए जा रहे थे, कि सिंधिया के साथ भाजपा में आए हजारों कांग्रेसियों को एडजस्ट करना सत्तारूढ़ पार्टी के लिए चुनौतीपूर्ण साबित होगा, कमोवेश वैसे ही हालात अभी नजर आ रहे हैं। शिवराज सिंह द्वारा कैबिनेट विस्तार को फौरी तौर पर टालना और व्यापक स्तर पर मंथन के बाद टीम वीडी का फाइनल न हो पाना इसी तरफ संकेत कर रहा है। आलम कुछ यह हो गया है, कि खुद भाजपा के लिए यह चुनौती सिरदर्द साबित हो रही है और वह ज्योतिरादित्य सिंधिया से को-ऑपरेट करने की मांग कर रहे हैं।

सिंधिया के साथ भाजपा के दिग्गजों के दबाव के चलते शिवराज सिंह ने तो मंत्रिमंडल विस्तार को टाल दिया है, लेकिन इस वक्त भाजपा कार्यकारिणी के गठन में हो रही एक-एक दिन की देरी पार्टी नेतृत्व पर सवाल खड़े कर रही है और इस विस्तार के पीछे अगर कोई पेंच है तो वो हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। दरअसल उपचुनाव के बीच भाजपा ने महामंत्रियों की नियुक्ति कर दी थी, उस दौरान सिंधिया खेमे को किसी तरह की तरजीह नहीं दी गई, लेकिन उपचुनाव में बेहतर प्रदर्शन के बाद सिंधिया पूरा हिसाब करने के मूड में है और उपाध्यक्ष पद पर अपनों को एडजस्ट करने की कोशिश में लगे हुए हैं। सिंधिया ने इसके लिए तीन नाम आगे भी बढ़ा दिए हैं और उनका कहना है, कि मीडिया पेनलिस्ट के अलावा इन तीन नामों को सम्मानजनक पद दिया जाए।

● **जितेंद्र तिवारी**

सिंधिया की डिमांड, भाजपा की परेशानी

दरअसल सिंधिया का कहना है कि हाटपिपल्या विधायक मनोज चौधरी, भांडेर विधायक रक्षा संतराम और पंकज चतुर्वेदी को संगठन में सम्माजनक पद पर एडजस्ट किया जाए। महामंत्रियों की नियुक्ति के बाद अब संगठन में सम्मानजनक पद के नाम पर सिर्फ उपाध्यक्ष पद ही रह गया है, जिसके लिए भी भाजपा के दर्जनों दावेदार तैयार बैठे हैं। खबर तो यह भी है कि मंत्री पद के कई दावेदारों को भी भाजपा उपाध्यक्ष ही बनाएगी और अगर सिंधिया समर्थक चेहरों को इस पोस्ट पर एडजस्ट किया जाता है तो एक बार फिर भाजपा के खांटी नेता उपेक्षित रह सकते हैं। हालांकि भाजपा इन तीन चेहरों को संगठन में एडजस्ट करने की बात तो मान गई है, लेकिन अब वह उनकी जिम्मेदारियों को लेकर मंथन कर रही है। जिससे पार्टी के अन्य नेता भी सम्मानजनक पद पर काबिज हो सकें। इसके लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया से पार्टी के साथ को-ऑपरेट करने की मांग की गई है।

लौटी मप्र की साख!

विकास और सुशासन की पटरी से उतर चुके मप्र की साख आखिरकार 27 माह बाद लौट आई है। एक बार फिर से मप्र देश के सबसे विकसित और सुशासित राज्यों में शामिल हो गया है। यह तथ्य केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न विकास मापदंडों पर राज्यों के मूल्यांकन में हुआ है। केंद्र सरकार ने सुशासन के 10 मापदंडों के पैमानों पर राज्यों की स्थिति का आंकलन किया है। उसके बाद उनकी रैंकिंग की है। इस रैंकिंग में जहां तमिलनाडु 62.6 प्रतिशत अंक के साथ पहले पायदान पर है, वहीं मप्र 59.6 प्रतिशत के साथ तीसरे स्थान पर आ गया है। इससे पहले वह आठवें स्थान पर था।

नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार करीब एक साल पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मप्र सरकार ने विकास के पैमानों पर बेहतर प्रदर्शन कर यह मुकाम हासिल किया है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत कहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान ने आत्मनिर्भर मप्र का रोडमैप 2023 जारी कर यह संकेत दे दिया है कि तीन साल में मप्र देश का अग्रणी राज्य बनेगा।

गौरतलब है कि 2018 तक मप्र कई क्षेत्रों में देश का अग्रणी राज्य था। लेकिन दिसंबर 2018 में कमलनाथ सरकार के गठन के बाद से प्रदेश सुशासन के मापदंडों पर पिछड़ता गया। जिसका परिणाम यह हुआ कि केंद्र के सुशासन मापदंडों के पैमानों पर मप्र खरा नहीं उतरा। केंद्र सरकार ने देश के सभी राज्यों की स्थिति का आंकलन- कृषि एवं उससे जुड़े क्षेत्र, वाणिज्य एवं उद्योग, मानव संसाधन विकास, जन स्वास्थ्य, सार्वजनिक बुनियादी ढांचा, आर्थिक सुशासन, समाज कल्याण एवं विकास, न्यायिक एवं जनसुरक्षा, पर्यावरण और जल संसाधन प्रबंधन आदि पैमानों की कसौटी पर किया है। इन सभी रैंकिंग को एक साथ लेकर देखने पर राज्यों के विकास की स्थिति का निरीक्षण किया जा सकता है। यह बहुत स्पष्ट रूप से सामने आता है कि कुछ राज्य दशकों से अविकसित हैं जबकि कुछ राज्य तेजी से विकास दर्ज कर रहे हैं। मप्र ने भी पिछले एक दशक में तेजी से विकास किया, लेकिन 2019 में यहां तेजी से गिरावट भी दर्ज की गई। लेकिन 27 महीने बाद स्थितियां एक बार फिर अनुकूल हुई हैं।

मप्र पिछले 27 माह से केंद्र के सुशासन मापदंडों के पैमानों की कसौटी पर पिछड़ा था। हमेशा टॉप-5 राज्यों में रहने वाला मप्र आठवें नंबर पर था। प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि प्रदेश में पिछले दो साल राजनीतिक उठापटक में बीते हैं। पहले चुनाव, फिर सरकार बचाने और गिराने का खेल चलता रहा, जिसके कारण विकासात्मक कार्यों पर ध्यान नहीं दिया गया। इस कारण मप्र की साख गिरी है। लेकिन एक बार फिर से प्रदेश टॉप-5 में शामिल हुआ है और तीसरे नंबर पर आया है।

गौरतलब है कि इस रैंकिंग के पीछे तर्क यह है कि यह राज्यों के बीच उनकी विकास प्राथमिकताओं को ठीक करने के लिए प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करेगा। इसके अलावा, इनमें से अधिकांश मूल्यांकन किसी विशेष विकास लक्ष्य के हिसाब से एक राज्य को रैंकिंग देते हैं। उदाहरण के लिए जल संसाधनों का विकास। इन राज्यों के भीतर, 200 एस्पिरेशनल जिलों या देश के सबसे गरीब लोगों के लिए विकास का एक सूचकांक भी है। सरकार का ध्यान सबसे गरीब जिलों पर रहा है। उनके प्रदर्शन को विकास लक्ष्यों के आधार पर नियमित रूप से सूचीबद्ध करके केंद्र सरकार विकास योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना चाहती है।

केंद्र सरकार ने अपने सुशासन मापदंडों पर राज्यों की स्थिति का आंकलन किया तो यह तथ्य सामने आए कि सूचकांक में 15 राज्यों ने राष्ट्रीय औसत से नीचे स्कोर किया है। खराब प्रदर्शन करने वालों की सूची में सभी 8 पूर्वोत्तर राज्यों के साथ-साथ दिल्ली, झारखंड, उप्र, बिहार और ओडिशा जैसे राज्य भी शामिल हैं। देश का औसत स्कोर 50.33 प्रतिशत रहा है। राज्यों के 10 प्रमुख क्षेत्रों-कृषि एवं उससे जुड़े मामले, व्यापार एवं उद्योग, मानव संसाधन विकास, सरकारी निर्माण, समाज कल्याण विकास, जल संसाधन प्रबंधन, आर्थिक संरचना, न्यायिक एवं जल सुरक्षा, जन स्वास्थ्य और पर्यावरण आदि के प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग आधारित है। जिसमें 100 से अधिक संकेतक हैं।

मप्र में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने पूर्ववर्ती शासनकाल में स्वास्थ्य सुविधाओं पर हर साल बड़ा बजट खर्च किया है। इससे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कुछ हद तक सुधरी हैं। कोरोना संक्रमणकाल के दौरान प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं पर सबसे अधिक जोर दिया गया। सुशासन रैंकिंग में 14 राज्यों का स्कोर राष्ट्रीय औसत 5.02 से कम है। खराब प्रदर्शन करने वाले उत्तर पूर्व के 6 राज्यों के साथ पंजाब, झारखंड, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं। इस श्रेणी में मप्र 11वें स्थान पर है। मप्र ने अन्य क्षेत्रों में भी अच्छा काम किया है।

● राकेश ग्रोवर

कृषि ने बचाई प्रतिष्ठा

प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई सुशासित रैंकिंग में मप्र की स्थिति अभी भी कई अन्य बड़े राज्यों से बेहतर इसलिए है कि कृषि एवं उससे जुड़े क्षेत्रों में मप्र का प्रदर्शन अच्छा रहा है। इस बार प्रदेश में गेहूं की बंपर पैदावार और खरीदी हुई है। सरकार ने पिछले साल देश में सबसे अधिक 129 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं खरीदा है। वहीं 13 राज्यों का स्कोर इस क्षेत्र में राष्ट्रीय औसत से कम है। खराब प्रदर्शन करने वालों की सूची में 5 पूर्वोत्तर राज्यों के साथ दिल्ली, तेलंगाना, गोवा, केरल और पंजाब शामिल हैं। इस क्षेत्र में कृषि और उससे जुड़े क्षेत्र की विकास दर, खाद्यान्न उत्पादन की वृद्धि दर, बागवानी उत्पादन की वृद्धि दर, दुग्ध उत्पादन की वृद्धि दर, मांस उत्पादन की वृद्धि दर तथा फसल बीमा के आधार पर राज्यों का आंकलन किया गया है। मप्र सभी मापदंडों पर देश में अन्य राज्यों से बेहतर रहा। इसलिए वह पहले पायदान पर है। प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल कहते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मार्गदर्शन में खेती-किसानी को लाभदायद बनाने की दिशा में काम चल रहा है। इसी दिशा में प्रदेश में किसानों के खेत में उत्पादित एक-एक दाने को खरीदने की कोशिश की गई। इस साल मप्र में 135 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा गया है, इससे प्रदेश की स्थिति और मजबूत होगी।

आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पर मप्र को भी आत्मनिर्भर बनाने की पहल की जा रही है। मौजूदा सरकार छोटे-छोटे उद्योगों के माध्यम से इस लक्ष्य को पूरा करने का रोडमैप पहले ही बना चुकी है। 8 अप्रैल 2021 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 6 माह में 1023 इकाईयों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा और इन इकाइयों से 50 हजार से भी अधिक लोगों को रोजगार देने का भी लक्ष्य रखा।

रोजगार के लिए स्वरोजगार को बढ़ावा

कोरोना लॉकडाउन के बाद से ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मप्र में रोजगार को बढ़ाने की कार्ययोजना पर काम करना शुरू कर दिया। इसके लिए औद्योगिक विकास के साथ ही स्वरोजगार को बढ़ावा देने की नीति पर जोर दिया गया। इसके परिणाम काफी सुखद आए हैं। 8 अप्रैल को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से 1,891 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का प्रदेशव्यापी शुभारंभ किया। इसके माध्यम से 50 हजार से ज्यादा व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि नवंबर 2020 से अब तक 1,891 इकाईयां या तो स्थापित हो चुकी हैं या स्थापना की प्रक्रिया में हैं। इन इकाईयों में 4,221 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। प्रदेश में पिछले एक साल में औद्योगिक विकास की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। प्रदेश के विभिन्न अंचलों में मांग के अनुरूप 1575 से अधिक हैक्टेयर भूमि पर 20 नवीन औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की योजना तैयार की गई है। इन औद्योगिक क्षेत्रों के विकास से प्रदेश में लगभग 15,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ 10 हजार व्यक्तियों को रोजगार भी मिल सकेगा। वित्तीय वर्ष 2020-21 में 5 औद्योगिक क्षेत्रों में कुल 1 हजार 325 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल का विकास कार्य पूर्ण किया गया। साथ ही 6 विद्यमान औद्योगिक क्षेत्रों में 1 हजार 323 हैक्टेयर क्षेत्रफल में भी उन्नयन कार्य पूर्ण किया गया है। इससे औद्योगिक इकाईयों को विकसित अधोसंरचना प्राप्त होने के साथ ही प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा।

स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उनकी ब्रांडिंग तथा विपणन हेतु प्रदेश के प्रत्येक जिले का एक विशिष्ट उत्पाद चिन्हित करने का कार्य प्रारंभ किया गया है। इस संकल्प पर अमल के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इंटेलीजेंस तथा निर्यात सुविधा केंद की स्थापना के लिए कंसल्टेंट का चयन किया गया है। कोविड-19 के दौरान भी पिछले एक वर्ष में प्रदेश में 7 बड़े उद्योग स्थापित हुए। इनमें लगभग 1563 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश एवं 5705 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ। औद्योगिक क्षेत्रों में विभिन्न श्रेणी की 372 इकाईयों को 251 हैक्टेयर से अधिक भूमि आवंटित की गई। इनमें लगभग 4336 करोड़ 82 लाख रुपए का पूंजी निवेश तथा 12 हजार 509 व्यक्तियों का रोजगार संभावित है। यानी आने वाले कुछ वर्षों में मप्र रोजगार का एक बड़ा हब बनकर सामने आएगा। इससे उम्मीद की जा सकती है कि रोजगार की तलाश में पलायन कर दूसरे राज्यों में गए लोगों को अब यहीं रोजगार मुहैया कराया जाएगा।

स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उनकी ब्रांडिंग तथा विपणन हेतु प्रदेश के प्रत्येक जिले का एक विशिष्ट उत्पाद चिन्हित करने का कार्य प्रारंभ किया गया है। इस संकल्प पर अमल के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इंटेलीजेंस तथा निर्यात सुविधा केंद्र की स्थापना के लिए कंसल्टेंट का चयन किया गया है। इस एक साल में उद्योग संवर्धन नीति-2019 (संशोधित-2020) में प्रावधानित सुविधाओं यथा वैट/सीएसटी प्रतिपूर्ति सहायता निवेश प्रोत्साहन योजना, ब्याज अनुदान, ईटीपी, एसटीपी, अधोसंरचना विकास इत्यादि के अंतर्गत वृहद श्रेणी की औद्योगिक इकाईयों को राशि 387 करोड़ 55 लाख रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई। कोविड-19 से बचाव के लिए प्रदेश के नागरिकों को अधिकाधिक संख्या एवं कम कीमत में मास्क उपलब्ध कराने के साथ ही प्रदेश के शहरी क्षेत्रों की महिला उद्यमियों के रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने के उद्देश्य से जीवन शक्ति योजना लागू की गई।

मप्र सरकार ने कोविड-19 संकट के कारण उद्योगों को आ रही कठिनाइयों को देखते हुए उद्योग नीति एवं भूमि आवंटन नियम के अंतर्गत विशेष रियायत/समयावधि में छूट प्रदान की। परिधान क्षेत्र में 25 करोड़ रुपए से अधिक पूंजी निवेश की विनिर्माण इकाइयों को मेगा स्तर की औद्योगिक इकाई मान्य करने का निर्णय भी लिया गया है। इस साल निवेश संवर्धन पर मंत्रिपरिषद् समिति द्वारा भी 631 करोड़ 60 लाख रुपए के पूंजी निवेश वाले चार परियोजना प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। इन परियोजनाओं में करीब सवा 5 हजार व्यक्तियों को रोजगार मिल सकेगा।

● **विकास दुबे**

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस

भारत सरकार द्वारा व्यापार संचालन सरलीकरण के लिए राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय व्यापार सुधार कार्यक्रम-2020 के क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए हैं। इसके अंतर्गत मप्र औद्योगिक विकास निगम द्वारा औद्योगिक एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों के आवश्यक निरीक्षणों के लिए कम्प्यूटराइज्ड केंद्रीकृत निरीक्षण व्यवस्था विकसित एवं परिनियोजित की गई है। अपने उद्योग के क्रियान्वयन को प्रारंभ करने की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न विभागों की सम्मतियां/अनुमतियां 30 दिवस के अंदर प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। निगम के विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि आवंटन से संबंधित कई सेवाओं को मप्र लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम 2010 में अधिसूचित किया गया है। इसी तरह निवेशकों द्वारा ऑनलाइन अभ्यावेदन में प्लॉट, मशीनरी, शेड एवं बिल्डिंग में संयुक्त रूप से 10 करोड़ की राशि के बराबर अथवा उससे अधिक निवेश प्रस्तावित करने की स्थिति में पदाभिहित पोर्टल द्वारा आशय-पत्र उसी दिवस में स्वतः जारी किया जाएगा। निवेशकों द्वारा ऑनलाइन अभ्यावेदन में प्लॉट एवं मशीनरी, शेड एवं बिल्डिंग में संयुक्त रूप से 10 करोड़ रुपए से कम राशि का निवेश प्रस्तावित करने की स्थिति में आवश्यक रूप से 7 दिवस में आशय-पत्र जारी कर दिया जाएगा।

किसान कैसे होगा आत्मनिर्भर?

इस साल 4 एकड़ में टमाटर की फसल लगाई है। टमाटर की फसल अच्छी है, लेकिन जो रेट सोचा था नहीं मिल रहा। फसल लगाने में डेढ़ लाख रुपए का खर्चा भी आया। लगा था कि चार से पांच लाख रुपए का व्यापार हो जाएगा लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। यह कहना है 48 वर्षीय सुरेंद्र तिवारी का। सुरेंद्र मप्र के जिला रायसेन की तहसील बाड़ी में रहते हैं। वे बताते हैं कि टमाटर खरीदने वाले व्यापारी नहीं आ रहे हैं। मंडियों में गाड़ियां खड़ी हैं कोई माल उतारने को तैयार नहीं है। लॉकडाउन में नुकसान चल रहा है। इसलिए मैंने एक अप्रैल को टमाटर फेंक दिया, जो कीमत मिल रही थी उससे किराया तक नहीं निकल पा रहा था। रायसेन जिले को एक जिला-एक उत्पाद योजना के अंतर्गत टमाटर के लिए चुना गया है। इसके बाद किसानों ने यहां टमाटर की जमकर खेती की, लेकिन दाम न मिलने से अब किसान परेशान हैं। किसानों का कहना है कि मौजूदा समय में एक कैरेट (22 किलो) का रेट 40 से 50 रुपए मिल रहा है। मतलब टमाटर की कीमत किसानों को डेढ़ से दो रुपए प्रति किलो मिल रही है। इससे नाराज किसान टमाटर सड़क, नाली और नहर में फेंक रहे हैं।

किसान अकरम खान (39) ने बताया कि रायसेन का टमाटर दिल्ली, आगरा, प्रयागराज (इलाहाबाद) भी जाता है, लेकिन व्यापारी नहीं आ रहे। मैंने करीब 15 एकड़ में टमाटर लगा रखे हैं। जमीन भी चार लाख रुपए में किराए पर ली है। टमाटर के एक कैरेट की कीमत अभी 40 से 50 रुपए मिल रही है। ऐसे में मुझे 6 से 7 लाख रुपए का घाटा लगेगा। मजबूरी में टमाटर नाली और नहर में फेंक रहे हैं। टमाटर मवेशियों को खाने के लिए डाल दिया गया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब किसानों को उनकी फसल की सही कीमत नहीं मिल रही है। आलू, प्याज और टमाटर को लेकर तो अक्सर होता है। पिछले साल मई में भी टमाटर की कीमत 50 पैसे प्रति किलो तक पहुंच गई थी।

मप्र में प्याज के सीजन के समय भी कीमत गिर जाती है और एक समय ऐसा भी आता है जब यही टमाटर, प्याज बाजार में उपभोक्ताओं को 100-200 रुपए किलो में खरीदना पड़ता है, लेकिन किसानों को इसका फायदा न के बराबर ही मिलता है। मप्र उद्यानिकी विभाग के जिला कार्यालय रायसेन के सहायक संचालक एनएस तोमर ने गांव कनेक्शन को बताया कि रायसेन जिले की बाड़ी तहसील में सर्वाधिक टमाटर उत्पादित होता है। वर्ष 2019-20 में सब्जी का रकबा 13141.00 हैक्टेयर रहा। चालू वर्ष टमाटर का रकबा 5150.00 हैक्टेयर है। जिले में करीब 3000 किसान टमाटर का उत्पादन कर रहे हैं। पांच सीजन में 2018 सर्वाधिक टमाटर उत्पादन का साल रहा है। मप्र उद्यानिकी विभाग ने सब्जियों और फलों का अनुमानित ब्यौरा तैयार किया है। इसके अनुसार पिछले पांच सीजन में केवल एक साल ही सर्वाधिक बढ़ोतरी हुई है। आंकड़ों के अनुसार टमाटर की बात करें तो सीजन 2015-16 से लेकर 2019-20 तक में सर्वाधिक उत्पादन सीजन 2018-19 में 29.46 फीसदी प्रति हैक्टेयर रहा। इस वर्ष 85412.36 हैक्टेयर क्षेत्रफल में उत्पादन लिया गया। हालांकि यह क्षेत्रफल सीजन 2015-16 से कम था। तब 95395.42 हैक्टेयर था। आंकड़ों के अनुसार 2015-16 में उत्पादकता 25.71 फीसदी प्रति हैक्टेयर, 2016-17 में 25.33, 2017-18 में 24.53 और 2019-20 में 29.19 फीसदी प्रति हैक्टेयर रहा। यह पिछले सीजन से 0.27 फीसदी कम है।

मप्र उद्यानिकी विभाग में बतौर सहायक संचालक (जिला रायसेन) पदस्थ एनएस तोमर ने बताया किसानों की यह समस्या संज्ञान में है। रायसेन जिले की बाड़ी तहसील के टमाटर उत्तर और दक्षिण भारत के प्रदेशों में जाता था। इस साल जहां बाड़ी का टमाटर सप्लाई होता था, वहां की किसानों की फसल भी बढ़िया रही। इसलिए वहां के व्यापारी नहीं आ रहे। इसके अलावा प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (पीएम-एफएमई) के तहत फूड प्रोसेसिंग यूनिट बनाए जाने हैं। अभी तक तीन किसानों ने आवेदन किया है।

प्रदेश के किसान बताते हैं, इस बार बाजार भाव अच्छा न रहने के चलते टमाटर की खेती में कोई फायदा नहीं हो रहा। हमारे खेत में हर तीसरे दिन 25 कैरेट (लगभग डेढ़ क्विंटल) टमाटर निकलता था। व्यापारी अभी एक कैरेट (25 किलो) के लिए लगभग 100 रुपए दे रहे हैं। जबकि खेत से टमाटर तुड़वाने के लिए चार से पांच मजदूर लगाने पड़ते थे, जिन्हें 1,000 रुपया देना पड़ता था। अब आप बताओ कि हमने टमाटर से क्या कमाया? फसल ज्यादा दिन नहीं रख सकते इसलिए बेचना मजबूरी है।

● **बृजेश साहू**

शुरु हुआ था ऑपरेशन ग्रीन

आलू, प्याज और टमाटर की कीमत अक्सर सीजन में कम हो जाती है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने टॉप्स यानी टमाटर, प्याज और आलू को प्राथमिकता देने की बात कही थी। इसीलिए ऑपरेशन ग्रीन की शुरुआत हुई, जिसमें बाद में 22 जल्दी खराब होने वाले उत्पादों को शामिल किया गया। केंद्र सरकार की टॉप (टोमैटो, ओनियन व पोटैटो) स्कीम के तहत कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड चेन और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को प्रोत्साहन देने की योजना थी। इस योजना को चलाने का दायित्व खाद्य प्रसंस्करण विभाग को दिया गया था। इसमें किसान उत्पादक संगठन के गठन के साथ उन्हें पोस्ट हार्वेस्टिंग में नुकसान रोकने जैसी तकनीक को अपनाने और इन संवेदनशील फसलों की खेती पर जोर देना था। सरकार ने 2018-19 के बजट भाषण में ऑपरेशन ग्रीन के लिए 500 करोड़ रुपए की घोषणा की थी। इसमें प्रमुख टमाटर उत्पादक राज्य, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा, गुजरात और तेलंगाना, प्रमुख प्याज उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, बिहार और प्रमुख आलू उत्पादक राज्य, उप्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात, मप्र और पंजाब को प्रोडक्शन क्लस्टर क्षेत्र बनाया गया है, लेकिन इतने सालों के बाद अभी प्याज, टमाटर और आलू की कीमत अक्सर बहुत कम हो जा रही है, जिससे किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है।

दिग्गजों की असली परीक्षा

मप्र की दमोह विधानसभा सीट पर 17 अप्रैल को उपचुनाव के लिए मतदान होंगे। मतदान से पूर्व दोनों पार्टियां अपनी-अपनी जीत के दावे कर रही है। उधर, क्षेत्र का मतदाता पूरी तरह मौन साधे हुए है। ऐसे में भाजपा-कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की चिंता बढ़ गई है। यह उपचुनाव दोनों पार्टियों के दिग्गज नेताओं की असली परीक्षा लेगा। भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित सभी नेता चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के बड़े नेता भी क्षेत्र में डेरा डाले हुए हैं।

उपचुनाव जीतने के माहिर खिलाड़ी के रूप में ख्यात मप्र के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ ही तीन अन्य पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, उमाभारती और दिग्विजय सिंह दमोह विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में अपनी-अपनी पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए पसीना बहा रहे हैं। इस उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी राहुल लोधी और कांग्रेस के अजय टंडन तो सक्रिय हैं ही, साथ ही दोनों पार्टियों के दिग्गज नेता भी सक्रिय हैं। दरअसल, इस उपचुनाव की हार-जीत दोनों पार्टियों के दिग्गज नेताओं का भविष्य भी लिखेगा। इस कारण दमोह उपचुनाव के लिए प्रचार ने धार पकड़ना शुरू कर दिया है। भाजपा-कांग्रेस के दिग्गजों ने दमोह में डेरा जमा लिया है। कांग्रेस के मुताबिक दलबदल इस उपचुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा है, तो दूसरी तरफ भाजपा का दावा है कि विकास के नाम पर भाजपा की यहां से निश्चित जीत होगी। इसके अलावा कांग्रेस को आस है कि मलैया परिवार की नाराजगी उपचुनाव में भाजपा को नुकसान पहुंचाएगी। भाजपा, मलैया परिवार की नाराजगी की बात को ही खारिज करता है। यहां बड़ा सवाल ये है कि दमोह में उपचुनाव का मुद्दा क्या होगा? इलाके का विकास, मलैया परिवार की नाराजगी या दलबदल?

पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की हुंकार के साथ ही दमोह उपचुनाव का शंखनाद हो गया। मप्र की दमोह विधानसभा सीट के लिए 17 अप्रैल को उपचुनाव होगा, जिसका नतीजा 2 मई को आएगा। कांग्रेस विधायक राहुल लोधी के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली है। राहुल लोधी इस बार भाजपा के टिकट पर चुनाव मैदान में है, राहुल लोधी को टिकट मिलने से जयंत मलैया के बेटे सिद्धार्थ मलैया की नाराजगी भी सामने आई। हालांकि पार्टी ने दमोह में सियासी समीकरण को साधने भूपेंद्र सिंह और गोपाल भार्गव को जिम्मेदारी सौंपी है। गोपाल भार्गव को मलैया का करीबी माना जाता है। जबकि भूपेंद्र सिंह मलैया विरोधी माने जाते हैं। हालांकि भाजपा मलैया परिवार की नाराजगी की खबरों का खंडन कर रही है।

दूसरी ओर राहुल लोधी के पार्टी छोड़ने के बाद कांग्रेस ने इसे प्रतिष्ठा की सीट बना लिया है। कांग्रेस ने अजय टंडन को यहां का प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस दमोह उपचुनाव में भी गद्दार के मुद्दे को ही बड़ा मुद्दा बना रही है। इसके साथ कांग्रेस अपनी सरकार के एक साल की उपलब्धियों को लेकर भी जनता के बीच पहुंच रही है।

दमोह में भाजपा के राहुल लोधी और कांग्रेस के अजय टंडन ने अपना-अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इसके साथ ही भाजपा और कांग्रेस के दिग्गजों ने डेरा डालना शुरू कर दिया है। दोनों ही दलों के लिए ये प्रतिष्ठा का चुनाव है, लेकिन मलैया परिवार के लिए राजनीतिक भविष्य का चुनाव है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या दमोह उपचुनाव लोधी या मलैया के कैरियर को पुनर्जीवित करेगा? या कोई नया नेता

कोरोना से नहीं डरेंगे, मतदान हम जरूर करेंगे

दमोह उपचुनाव से पहले हैरान करने वाली बात सामने आई है। यहां जिला निर्वाचन अधिकारी ही लोगों से कह रहे हैं कि आप तो वोट देने आइए कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है। जिला निर्वाचन अधिकारी तरुण राठी ने मतदाता जागरूक अभियान के तहत एक पोस्टर छपवाया है। इस पोस्टर पर लिखा है- कोरोना से नहीं डरेंगे, मतदान हम जरूर करेंगे। अब इस पोस्टर को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिर इतने बड़े अधिकारी ही इस तरह के स्लोगन लिखवाएंगे तो फिर कैसे आम लोगों को जागरूक किया जाएगा और कैसै महामारी पर नियंत्रण किया जाएगा।

अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रहेगा?

तीसरी बार उपचुनाव के दौर से गुजर रही दमोह विधानसभा सीट पर प्रत्याशियों की तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। यदि कोई बड़ा राजनीतिक उलट-फेर नहीं हुआ तो 2021 के उपचुनाव में मुख्य मुकाबला भाजपा के (लगभग तय) राहुल सिंह और कांग्रेस के उन अजय टंडन के बीच होगा जिनके चुनाव संचालन में राहुल 2018 में कांग्रेस की टिकट पर दमोह सीट से चुनाव जीते थे। हालांकि शिवसेना, आप तथा बीजेसीपी के प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में होंगे लेकिन हरेक की नजर भाजपा-कांगेस के इन्हीं 2 प्रत्याशियों पर होगी। ऐसा इसलिए भी क्योंकि कांग्रेस की टिकट पर अब तक 3 बार पराजय का स्वाद चख चुके अजय टंडन के साथ दल-बदल को लेकर नाराजगी झेल रहे राहुल सिंह पर अपनी प्रतिष्ठा बचाने का भारी दबाव रहेगा। चूंकि दोनों पर दबाव ज्यादा रहेगा लिहाजा दोनों ही जीत हासिल करने के लिए एड़ी-चोटी का जोर भी लगाएंगे। माना जा रहा था कि युवा कार्ड के सहारे 2018 का चुनाव जीतने वाली कांग्रेस फिर ऐसा ही कोई कार्ड खेलेगी। चूंकि भाजपा प्रत्याशी लोधी वर्ग से आते हैं लिहाजा कांग्रेस द्वारा भी वोट काटने लोधी कार्ड खेले जाने की उम्मीद थी। कई नाम पैनल में पहुंचे भी लेकिन कांग्रेस ने न तो लोधी और न ही युवा कार्ड खेला। उसने युवा राहुल के सामने अपने पुराने व अनुभवी चेहरे अजय टंडन पर दांव लगाना तय किया। भाजपा का सबकुछ नाराजगी पर निर्भर- प्रत्याशी की घोषणा के साथ यह भी साफ हो गया है कि कांग्रेस ने प्रत्याशी फाइनल करते समय नाराजगी के मुद्दे को सबसे ऊपर रखा। महज डेढ़ साल में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाने से दमोह की जनता में राहुल को लेकर अभी भी थोड़ी-बहुत नाराजगी है। और ऐसी ही आंतरिक नाराजगी भाजपा में राहुल का नाम खुले तौर पर सामने आने के बाद से है। कांग्रेस को इसी नाराजगी और अपने परंपरागत वोट बैंक के अंदर जीत की सारी संभावनाएं दिखीं। 17 अप्रैल को होने वाले मतदान में यह फैक्टर अहम भूमिका निभा सकता है।

नाराजगी वाले मुद्दे को भाजपा भी नजरअंदाज नहीं कर रही है और मुख्यमंत्री सहित प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हर गतिविधि पर नजर रख रहे हैं। कांग्रेस का प्रत्याशी घोषित होने के साथ बनने-बिगड़ने वाले समीकरणों पर भी भाजपा बारीकी से नजर रखे है। रणनीतिक कदम उठाते हुए उसने उपचुनाव प्रभारी भूपेंद्र सिंह के साथ गोपाल भार्गव को चुनाव प्रभारी नियुक्त कर दिया है। सागर और जबलपुर के संगठन प्रभारियों को भी आगे कर दिया है। शिवराज सिंह और वीडी शर्मा भी दमोह को लेकर रोज अपडेट ले रहे हैं प्रदेश की

जातिगत समीकरण साधने कांग्रेस ने बनाया चक्रव्यूह

दमोह सीट पर होने वाले उपचुनाव में जीत के लिए कांग्रेस हर दांव आजमाने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस ने जातिगत समीकरण साधने के साथ ही राम नाम का सहारा लेने की भी तैयारी की है। राजनीतिक दल भले ही जातिगत समीकरणों के आधार पर चुनाव लड़ने की बात से इनकार करें लेकिन दमोह में कुछ जाति वर्ग का बड़ा प्रभाव माना जाता है और पार्टियां इनको ही ध्यान में रख उपना उम्मीदवार उतारती आई हैं। कमलनाथ ने दमोह के दंगल में दर्जनभर नेताओं की फौज उतारी है जो जीत के इस अहम सूत्र को पकड़कर काम करने में लगे हुए हैं। अलग-अलग वर्ग के लिए अलग-अलग प्रभावशाली नेताओं को लगाया गया है। कांग्रेस ने दमोह उपचुनाव में भाजपा को टक्कर देने के लिए जो योजना तैयार की है उसके हिसाब से यहां 14 फीसदी लोधी वोटरों को लुभाने के लिए रामसिया भारती, साधना भारती, प्रताप लोधी को पार्टी ने जिम्मेदारी सौंपी है। 11 फीसदी जैन वोटरों को साधने के लिए पूर्व विधायक निशंक जैन की ड्यूटी लगाई है। 11 फीसदी एससी वोटरों के समर्थन के लिए पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया, सज्जन सिंह वर्मा, फूल सिंह बरैया और सुरेंद्र चौधरी जैसे नेता दमोह में डेरा डाले हुए हैं। कुर्मी वोटरों के लिए विधायक कमलेश्वर पटेल को जिम्मा दिया गया है। आदिवासी वोटों के लिए विधायक कांतिलाल भूरिया और ब्राह्मण वोटों के लिए मुकेश नायक, राजा पटैरिया और जिला अध्यक्ष मधु मिश्रा को लगाया गया है। अब देखना यह है कि कांग्रेस का यह जातिगत फॉर्मूला उपचुनाव में क्या गुल खिलाता है।

दमोह विधानसभा सीट पर 17 अप्रैल को उपचुनाव होना है। इसको लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने यहां अपनी-अपनी ताकत झोंक रखी है। दोनों ही दलों के लिए यह सीट प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गई है। यही वजह है कि दोनों पार्टियां किसी भी तरह की कोई कोर-कसर नहीं छोड़ना चाहती हैं। जहां भाजपा ने यहां दो-दो मंत्रियों को चुनाव का प्रभारी बनाया है, वहीं कांग्रेस ने भी इस सीट पर दर्जनों विधायक उतार रखे हैं। मामला जातिगत समीकरण साधने का हो या फिर बूथ प्रबंधन का सभी में पूरी ताकत झोंकी जा रही है। भाजपा ने यहां से राहुल लोधी को प्रत्याशी बनाया है तो कांग्रेस ने यहां से अजय टंडन को जिम्मेदारी सौंपी है।

भाजपा ने इस सीट पर अपनी फायर ब्रांड नेता साध्वी उमा भारती को चुनाव प्रचार के लिए उतार दिया है। तो वहीं कांग्रेस ने इसकी रणनीति के तहत साध्वी रामसिया भारती को स्टार प्रचारक बनाया है। इन दोनों ही नेत्रियों की खासियत यह है कि दोनों एक ही जाति वर्ग (लोधी) से आती हैं। साथ ही दोनों धार्मिक प्रवृत्ति के प्रवचनों के लिए जानी जातीं हैं। बता दें कि राहुल लोधी को उमा भारती का खास माना जाता है। जानकारी के मुताबिक यह भी कहा जाता है कि राहुल लोधी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में उमा भारती के कहने पर ही शामिल हुए थे। बता दें कि यहां भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा लगातार यहां डेरा जमाए हुए हैं। यहां दोनों ही दलों के प्रमुख नेता लगातार डेरा जमाए हुए हैं। कांग्रेस ने इस सीट पर ऐसा चक्रव्यूह रचा है जो भाजपा के लिए फिलहाल खतरा बना हुआ है। भाजपा ने इस सीट पर राम का कार्ड चला है। इसी को देखते हुए कांग्रेस ने भी साध्वी रामसिया भारती को यहां स्टार प्रचारक के तौर पर उतारा है।

● **अरविंद नारद**

मप्र में बड़े हमले की तैयारी में नक्सली

छत्तीसगढ़ में हमले के बाद नक्सली मप्र में भी बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी में हैं। इसका खुलासा झारखंड के कोल्हान प्रमंडल में खुफिया विभाग को मिली रिपोर्ट से हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश के बालाघाट, सीधी, सिंगरौली और मंडला जिले में नक्सलियों का जमावड़ा है। नक्सली नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में बड़ी वारदात करने की तैयारी करके बैठे हैं।

खुफिया विभाग का कहना है कि छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के करीब 100 नक्सली पिछले साल मप्र की सीमा में घुसे थे। अब उन्होंने बालाघाट, सीधी, सिंगरौली और मंडला के साथ ही इनके आसपास के जिलों में अपना विस्तार कर दिया है। सूत्र बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में हमले के बाद अब नक्सली संगठन मप्र सहित झारखड़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी हमले की साजिश रच रहे हैं।

छत्तीसगढ़ के सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा इलाके में सुरक्षा बलों ने कई नए कैंप खोले हैं। ऐसे में आने वाले समय में नक्सली एक्टिविटी कम होनी चाहिए, लेकिन इन जगहों से लगे हुए दंडकारण्य में बहुत बड़े इलाके हैं, जहां नक्सली अपने छिपने का नया ठिकाना आसानी से ढूंढ लेंगे। अबूझमाढ़ में तो नक्सली पहले से ही बहुत मजबूत स्थिति में हैं। 2 मार्च 2020 की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि नक्सली महाराष्ट्र, मप्र और छत्तीसगढ़ में काम करने के लिए अमरकंटक के जंगलों में नया बेस कैंप तैयार करने में जुटे हुए हैं। सीपीआई माओइस्ट ने अपनी 21 मेंबर्स की सेंट्रल कमेटी फिर से बना ली है, जो उनके पोलित ब्यूरो के बाद सबसे अहम है। ये सब संकेत हैं कि नक्सली खुद को दोबारा मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका सबसे अधिक फोकस मप्र के आठ जिलों बालाघाट, सीधी, सिंगरौली, मंडला, डिंडौरी, शहडोल, अनूपपुर और उमरिया पर है।

अपनी राष्ट्रीय सीमा के भीतर भारत ने अनेक अलगाववादी प्रतिरोधों की पीड़ा झेली है, लेकिन इनमें से कोई भी नक्सलवाद जैसी वीभत्स, हिंसक और जटिल चुनौती नहीं रही है। वीभत्स इसलिए कि घात लगाकर सैन्य बलों की निर्मम हत्या करना ही इसकी मुख्य कार्यशैली है। हिंसक इसलिए कि सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से राज्य पर कब्जा जमाना इसका घोषित उद्देश्य है और जटिल इसलिए कि एक निर्मित और सहयोगी बौद्धिक वर्ग द्वारा राज्य की ही मशीनरी का उपयोग कर राज्य के विरुद्ध संचालित इस हिंसक आंदोलन को 'वंचना के स्वाभाविक विस्फोट' के रूपक के माध्यम से संरक्षित करने का प्रयास करना। इस बात को समझने की आवश्यकता है कि जिन कारणों को नक्सलवाद के समर्थक गिनाते हैं उसका अब नक्सलवाद से कोई संबंध नहीं है। नक्सली अपनी हिंसक कार्रवाईयों की नैतिक वैधता लेने के लिए इन कारणों को गिनाते हैं। नक्सली आंदोलन से सहानुभूति रखने वाले बुद्धिजीवी तर्क देते हैं कि विकास के वर्तमान मॉडल ने आदिवासियों और वंचितों के अस्तित्व पर संकट खड़ा कर दिया है। आदिवासियों को न केवल उनके संसाधनों से वंचित किया गया, बल्कि उन्हें अपनी सांस्कृतिक पहचान खोने के लिए भी विवश किया गया।

नक्सली आंदोलन को तार्किक ठहराने वाले कहते हैं कि अत्याधिक अभाव में जी रहे इन वर्गों को जब विशेष सरकारी संरक्षण की आवश्यकता थी तब इन्हें सरकारी असहयोग का सामना करना पड़ा। इस प्रकार शासन का जो शून्य उत्पन्न हुआ उसे नक्सलियों ने भरा। यह समुदाय जब राज्य के निर्धारित ढांचे के माध्यम से अपनी बात नहीं कह पाते तो अन्य रास्ता तलाश लेते हैं। इन्हीं कुछ आधारों पर नक्सलवाद को जायज ठहराने की कोशिश की जाती है। लेकिन यह हिंसा को छिपाने की बौद्धिक चतुराई से अधिक कुछ नहीं है। यदि नक्सलवाद इस स्थिति में सुधार का पक्षधर होता तो वह विकास कार्यों को तेज करने की मांग करता, लेकिन नक्सली न केवल अवसंरचना विकास को बाधित करते हैं, बल्कि स्कूल व अस्पताल जैसी बुनियादी सुविधाओं की पहुंच भी बाधित करते हैं। गरीबों का मसीहा बनने वाले नक्सली हर उस सरकारी प्रयास को रोकते हैं जिससे नागरिकों का जीवन स्तर बेहतर होता है। इतना ही नहीं, चुनाव प्रक्रिया को बाधित कर वो नागरिकों को लोकतांत्रिक व्यवस्था में शामिल होने से रोकते हैं। नक्सलियों के मंसूबे से लोगों को अवगत कराकर उनके खिलाफ माहौल बनाने की जरूरत है।

● सुनील सिंह

एके-47 और रॉकेट लॉन्चर से लैस

झारखंड की खुफिया विभाग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मप्र में नक्सली छोटे-छोटे दलों में सक्रिय हैं, ताकि पुलिस की नजर में न आ सकें। नक्सली एके-47 और रॉकेट लॉन्चर जैसे घातक हथियारों से लैस हैं। झारखंड और छत्तीसगढ़ में नक्सली सुरक्षा बलों में रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल कर चुके हैं। मप्र में सबसे अधिक नक्सली बालाघाट में सक्रिय हैं। विगत दिनों बालाघाट में नक्सलियों ने सड़क निर्माण कार्य में लगे दो ट्रैक्टर समेत एक ट्रक को जला दिया था और ठेकेदार व मजदूरों से मारपीट की थी। इसके अलावा विस्फोटक भी बरामद हुआ था। खुफिया विभाग का दावा है कि झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ में लगातार चलाए जा रहे अभियान से नक्सलियों को जान बचाने के लिए नए ठिकानों की तलाश में इधर-उधर भागना पड़ रहा है। ऐसे में मप्र उनके लिए सुरक्षित जगह है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुई नक्सली वारदात के बाद छिपने की गरज से नक्सली बालाघाट का रुख कर सकते हैं। इसलिए जिले के सीमावर्ती थाना व चौकियों में पुलिस ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही चौकसी बढ़ा दी गई है। नक्सलियों को रोकने के लिए हॉक फोर्स, सीआरपीएफ, जिला पुलिस बल को तैनात किया गया है। छत्तीसगढ़ से भागकर बालाघाट के जंगल में घुसने वाले नक्सलियों के संभावित रास्तों पर पुलिस ने एंबुश लगा दिए हैं।

कोयला के लिए जंगल पर चलेगी आरी

देश में एक तरफ सरकार वनीकरण और हरियाली को बढ़ावा देने की योजना पर काम कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कोयले के लिए करीब 15,000 एकड़ जंगल काटने की तैयारी हो रही है। इसमें से मप्र में 7 खानों के लिए 838.03 हैक्टेयर (लगभग 2070 एकड़) वन क्षेत्र काटा जाएगा। इसका खुलासा लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में हुआ है। केंद्र सरकार ने कहा है कि कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियों ने 22 नई कोयला खानें खोलने की योजना बनाई है। इनमें से 7 खदानें मप्र में खुलनी है।

गौरतलब है कि मप्र सहित झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा ऐसे राज्य हैं जो खनिज संपदा से परिपूर्ण हैं। सरकार इन्हीं चार राज्यों में 22 कोयला खानों के लिए 5966.84 हैक्टेयर (लगभग 14,744 एकड़) वन भूमि को उपायोग में लाया जाएगा। झारखंड में 8 खानों के लिए 2,756.62 हैक्टेयर वन भूमि को उपयोग में लाया जाएगा। जबकि मप्र में 7 खानों के लिए 838.03 हैक्टेयर वन भूमि का इस्तेमाल होगा, इसी तरह छत्तीसगढ़ में 2,022.48 हैक्टेयर वनभूमि पर 6 खानें बनाई जाएंगी। ओडिशा में एक खान के लिए 349.71 हैक्टेयर वनभूमि का इस्तेमाल किया जाएगा। जानकारों का कहना है कि कोयला खनन के लिए जिन क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है, वहां सघन वन क्षेत्र है।

77,482 वर्ग किलोमीटर में फैला मप्र का वन क्षेत्र खनिज संपदा से परिपूर्ण है। वहीं देश में 8,07,276 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में वन स्थित हैं। यह कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.67 फीसदी है। मप्र में सर्वाधिक वन वृक्ष सागौन के हैं तथा उसके बाद दूसरे स्थान पर साल के वृक्ष हैं। जिन क्षेत्रों में खदानें खोली जानी है वहां सागौन और साल के वन हैं। अब प्रदेश में खुलने वाली 7 कोयला खदानों के कारण **सागौन और सान** के पेड़ों की बलि दी जाएगी। हैरानी की बात यह है की मप्र से निकलने वाले कोयले से मप्र को कोई लाभ नहीं होता है। गौरतलब है कि विकास, रोजगार, उद्योग, बिजली उत्पादन और राजस्व के नाम पर देश में कोयले का खनन किया जाता है।

उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ सालों के दौरान देश में कोयला उत्पादन के प्रति सरकार ने अपना ध्यान बढ़ाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि भारत में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा कोयला भंडार है और हम कोयले के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक हैं तो फिर हम दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक क्यों नहीं बन सकते? उल्लेखनीय है कि कोयला मंत्रालय और केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने 2010 में एक अध्ययन के बाद भारत के कोयला भंडार को गो एवं नो-गो क्षेत्रों में वर्गीकृत किया था। इस अध्ययन में कहा गया कि जंगलों को बचाने के लिए नो-गो क्षेत्रों में खनन को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। ये जैव विविधता से भरपूर घने वन क्षेत्र थे और इसलिए, यहां खनन पर प्रतिबंध आवश्यक था। लेकिन निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार अपने ही बनाए नियमों का पालन नहीं करती है।

सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर के नंदीकेश शिवलिंगम कहते हैं, देश में अभी भले ही 600 से अधिक कोल ब्लॉक हैं लेकिन 50 या 60 कोल ब्लॉक ही हैं जहां से अधिकांश कोयला निकाला जाता है। ये सारे बड़े कोल ब्लॉक हैं और इनकी उत्पादन क्षमता अधिक है। बहुत सारी खानें **प्रोडक्टिव** नहीं हैं। इसलिए हमें सिर्फ जंगलों को खोलने पर ही जोर नहीं देना चाहिए, बल्कि अगर हम समझदारी के साथ माइनिंग करें, तो अगले कई दशकों तक बहुमूल्य जंगलों को बचा सकते हैं।

कोविड-19 लॉकडाउन के बावजूद जून 2020 में कोयले की खानों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन इसके पीछे पूरी कहानी चौकाने वाली है। जून में जब नए कोयला ब्लॉकों की नीलामी शुरू हुई, तब प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे कोयला क्षेत्र को कई वर्षों के लॉकडाउन से बाहर आने में मदद मिलेगी। लेकिन समस्या यह है कि कोयले के भंडार घने जंगलों में दबे पड़े हैं और इन जंगलों में शताब्दियों से सबसे गरीब आदिवासी बसते हैं। कोयले के लिए नए क्षेत्रों का जब खनन शुरू होगा, तब आदिवासियों और आबाद जंगलों पर अनिश्चितकालीन लॉकडाउन थोप दिया जाएगा।

● **लोकेंद्र शर्मा**

नो-गो क्षेत्र में खनन की मंजूरी

2010 में, कोयला मंत्रालय (एमओसी) और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओईएफ), (जिसे अब पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) का नाम दिया गया है) ने एक वृहद अध्ययन के उपरांत भारत के कोयला भंडार को गो एवं नो-गो क्षेत्रों में वर्गीकृत किया था। अध्ययन ने कहा कि जंगलों को बचाने के लिए नो-गो क्षेत्रों में खनन को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। ये जैव विविधता से भरपूर घने वन क्षेत्र थे और इसलिए, यहां खनन पर प्रतिबंध आवश्यक था। मंत्रालयों ने कुल अध्ययन किए गए क्षेत्रों में से 47 प्रतिशत (222) इलाकों को नो-गो क्षेत्रों के रूप में सीमांकित किया लेकिन 2010 से 2014 के बीच, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार के कार्यकाल में यह संख्या 16 प्रतिशत या सिर्फ 35 ब्लॉकों तक सिमटकर रह गई। एनडीए के सत्ता में आने के बाद भी यह काट पीट जारी रही। 2015 के बाद कई संरक्षित क्षेत्रों को खनन के लिए खोल दिया गया। 41 कोयला ब्लॉकों को नीलामी के लिए डाला गया था। ध्यान रहे कि इनमें से 12 की पहचान 2010 के अध्ययन में नो-गो क्षेत्र के रूप में की गई थी। लेकिन अगर गो क्षेत्र देश की जरूरतों के लिए पर्याप्त हैं तो नो-गो क्षेत्रों को बर्बाद क्यों करें? वैसे भी पिछले एक दशक के दौरान सरकार ने निजी निवेशकों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) को 91 कोयला खानें नीलामी या आवंटन के माध्यम से दी हैं। उनमें से 30 गो के रूप में सीमांकित क्षेत्रों में हैं। क्या ये सभी खदानें चालू हो गई हैं?

कब थमेंगी जहरीली शराब से मौतें?

मुरैना जहरीली शराब कांड में 28 मौतों के बाद बेहद सख्त तेवरों में दिखीं भाजपा नेत्री, साध्वी उमाभारती ने शराब को कलंक और तमाम झगड़ों और महिलाओं-बच्चों पर हिंसा की जड़ बताते हुए प्रदेश में 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन से शराबबंदी अभियान छेड़ने का खुला ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि अभियान का पूरा प्लान बन चुका है। हम सिर्फ पूर्ण शराबबंदी के पक्षधर हैं। मैं इस अभियान की शुरुआत सबसे पहले अपने गृहक्षेत्र की शराब दुकान बंद करा कर करूंगी। इस ऐलान से उनकी पार्टी भाजपा में भी बेचैनी फैली और शिवराज सिंह से लेकर तमाम नेताओं के बयान आने लगे कि केवल शराबबंदी से कुछ नहीं होगा, बल्कि नशा छोड़ने के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। बाद में उमा भारती की शिवराज सिंह से एक मुलाकात हुई और उसके बाद पूर्ण शराबबंदी वाले तेवरों में भी टर्न महसूस किया गया। जहरीली शराब से मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। उमाभारती के कथन और संकल्प को लेकर यह सवाल उठ रहे हैं कि उमाजी आपके प्रदेश में शराबबंदी लागू कराने के अभियान का क्या हुआ?

पता नहीं मप्र में माफिया कब गड़ेंगे, कब टंगेंगे, कब लटकेंगे? 8 मार्च तो बीत गया, पता नहीं उमा भारती कब शराबबंदी अभियान शुरू करेंगी? सूबे की जनता के जेहन में यह सवाल उठना बेहद लाजिमी है, क्योंकि एक हफ्ते के भीतर भिंड और ग्वालियर में जहरीली शराब दर्जनभर से ज्यादा लोगों की जान ले चुकी है, 4 लोगों की आंखों की रोशनी पर हमला कर चुकी है। बीते 3 महीनों में जहरीली शराब से अलग-अलग जिलों में करीब 60 लोगों की मौत और उनके परिवारों का चीत्कार यह बता रहा है, कि मप्र में शराब माफिया कितना बेखौफ है और इस माफिया के आगे सरकार और उसका सिस्टम कितना लाचार है। इसी साल जनवरी में मुरैना में जहरीली शराब से 28 लोगों की मौत के तांडव और मचे हाहाकार को कोई नहीं भूला होगा। उसके बाद छतरपुर में जहरीली शराब से आधा दर्जन मौतें भी याद ही होंगी। जहरीली शराब कुछ माह पहले उज्जैन में 16 और रतलाम में 11 की जान ले चुकी है। इन सब घटनाओं में जहरीली शराब से मौतों ने न जाने कितने बच्चों को अनाथ और परिवारों को बेसहारा किया है, यह सब सिस्टम के बही-खातों में दर्ज तो होगा ही। अब होली से रंगपंचमी के बीच भिंड के लहार विधानसभा क्षेत्र में जहरीली शराब से 7 लोगों और फिर इसी तरह से ग्वालियर में हुई 2 मौतों ने दिल दहलाकर रख दिए हैं।

3-4 दिन पहले लहार विधानसभा क्षेत्र में होली के दिन जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत हो गई और कम से कम चार लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। खुद लहार के विधायक कांग्रेस नेता डॉ. गोविंद सिंह ने इसकी पुष्टि की और बताया कि लहार के असनेट और जैतपुरा गुड़ा गांव में खुलेआम जहरीली शराब बेची जा रही है। शिकायत और जानकारी होने के बावजूद जिला, आबकारी प्रशासन एक्शन नहीं ले रहा। उन्होंने पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच और मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की है। मौतों के बाद सूबे में गरमाई सियासत के बीच मप्र कांग्रेस कमेटी ने भिंड और ग्वालियर में मौतों की जांच के लिए एक कमेटी गठित कर दी है। वहीं दूसरी ओर भिंड एसपी मनोज कुमार सिंह इन मौतों के जहरीली शराब से होने की बात को ही सिरे से खारिज करते हुए कहते हैं, मौतों की सही वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही बताई जा सकेगी। जहरीली शराब से मौतों का कोई मामला हमारे सामने नहीं आया है।

ग्वालियर के महाराजपुरा सर्किल के वार्ड नंबर 62 में चंदूपुरा खेरिया में रहने वाले विजय सिंह परिहार के बाद गत दिनों 40 साल के प्रदीप परिहार ने भी दम तोड़ दिया। सीएसपी के प्रदीप और उसके कुछ साथियों ने भाईदूज पर एक पार्टी करने के लिए हाइवे से एक ढाबे से शराब खरीदी थी। शराब जहरीली थी और उसे पीने के बाद से ही लोगों की तबियत बिगड़ने लगी और 4 लोगों को कम दिखने लगा। कलेक्टर कौशलेंद्र सिंह ने भी माना है कि शराब पीने से दो लोगों की मौत हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही असलियत पता चलेगी।

बता दें कि जनवरी में जब मुरैना में जहरीली शराब से 28 मौतें हुईं थीं, तब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ढीले सिस्टम की चाबियां कसते हुए काफी सख्त तेवर दिखाए थे। उन्होंने एक नहीं, कई मंचों से शराब माफिया सहित हर तरह के माफिया को ललकारा था, और कहा था, 'अरे सुन ले रे ओ माफिया, अब मामा आ गया है, माफिया प्रदेश छोड़ दे, वरना माफिया को टांग दूंगा, लटका दूंगा और 10 फीट जमीन के नीचे गाड़ दूंगा।' इसके बाद सरकार की कुछ दिनों सख्ती भी दिखी और राज्य के अनेक जिलों में अवैध शराब के खिलाफ अभियान छेड़ा गया तथा बड़ी मात्रा में अवैध शराब और देशी शराब बनाने वाली भट्टियां पकड़ी भी गईं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ-साथ हालात पहले जैसे हो गए।

● **नवीन रघुवंशी**

बिक रही है मिथाइल एल्कोहल मिली जहरीली शराब

ग्वालियर-चंबल संभाग में मिथाइल एल्कोहल मिली जहरीली शराब अवैध रूप से बिक रही है। इसका खुलासा ग्वालियर के महाराजपुरा इलाके में तीन मृतकों के बिसरा जांच रिपोर्ट में हुआ है। मुरैना में भी मिथाइल एल्कोहल मिली शराब पीने से ही 24 लोगों की जान गई थी। बिसरा जांच रिपोर्ट से यह तो स्पष्ट हो गया कि शराब में मिथाइल एल्कोहल थी, लेकिन अभी तक पुलिस और आबकारी विभाग की टीम इसकी जड़ तक नहीं पहुंच पाई है। मिथाइल एल्कोहल का उपयोग औद्योगिक कार्यों में किया जाता है। मिथाइल एल्कोहल जहर ही है। इसे पीने से सबसे पहले आंख की रोशनी कम होना शुरू होती है। अधिक मात्रा में पी लेने से व्यक्ति की मौत हो जाती है।

सैटेलाइट से होगा सीमांकन

भू अभिलेख कार्यालय द्वारा प्रदेश में सैटेलाइट इमेज के जरिए सीमांकन करने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए मोबाइल की तरह ही एक रोवर होगा, जो किसी भी खेत की बाउंड्री पर रखने पर घूमने लगेगा और मात्र 15 से 20 मिनट में ही पूरी जमीन का सीमांकन करने के साथ ही नक्शा भी बता देगा। इस रोवर को **कंटिन्यू ऑपरेटिंग रिफरेंस स्टेशन** से नेटवर्क मिलता रहेगा और राजस्व अमला जिस किसान के खेत का सीमांकन करना होगा उसके खेत में ले जाकर खेत की बाउंड्री पर रख देगा, फिर वह चारों तरफ घूमकर सीमांकन करने के साथ ही नक्शा भी बता देगा। इसके लिए पूरे प्रदेश में 77 स्थानों पर ऑपरेटिंग रिफरेंस स्टेशन टॉवर का निर्माण किया जा रहा है।

भू-अभिलेख आयुक्त ज्ञानेश्वर पाटिल ने बताया कि इस टॉवर के बनने के बाद किसानों को सीमांकन के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। साथ ही राजस्व विभाग के पटवारी और आरआई द्वारा भी कम समय में सीमांकन हो जाएगा। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में पूरे प्रदेश में हजारों की संख्या में सीमांकन के प्रकरण पेंडिंग पड़े हैं। राजस्व अमला कई बार मशीन की कमी होने का बहाना बनाकर प्रकरण ठंडे बस्ते में डाल देता है। आम जनता को भी कई बार कलेक्टोरेट के चक्कर लगाना पड़ते थे, लेकिन अब सैटेलाइट इमेज के जरिए सीमांकन शुरू होने से इन समस्याओं का समाधान हो जाएगा।

भू-अभिलेख कार्यालय के सूत्रों के अनुसार एक टॉवर बनाने में 25 लाख रुपए का खर्च आता है। इसमें कई आधुनिक सिस्टम लगाए जाते हैं, जिनके जरिए पूरे जिले तक उसका नेटवर्क रोवर को मिलता रहता है और सैटेलाइट इमेज के जरिए सीमांकन करने के साथ ही नक्शा भी दिखने लगता है। प्रदेश के जिन 77 स्थानों को चिन्हित कर यह टॉवर बनाया जा रहा है, उस पर 1 करोड़ 92 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे।

शासन द्वारा शुरू किए गए मप्र किसान ऐप से किसानों को काफी सहूलियत मिल रही है। सीमांकन करने के लिए किसान को अपने मोबाइल में केवल सीमांकन ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। इसके माध्यम से वह अपने खेत की सीमाओं की दूरियां और क्षेत्रफल सहित गूगल इमेज के माध्यम से पटवारी के नक्शे का भी अवलोकन कर सकेगा। इसके अलावा किसान अपने खेत की चतुर्थ सीमाओं पर पैदल घूमकर जीपीएस की मदद से अपनी भूमि की वास्तविक सीमाओं का भी ज्ञान रख सकता है कि किस खसरा नंबर की भूमि पर वह खड़ा है। इतना ही नहीं, किसान अपनी फसल की गिरदावरी के साथ-साथ ई-उपार्जन भी कर सकता है। उपार्जन के पंजीयन में अगर पटवारी द्वारा कोई गलती की गई हो तो वह आपत्ति भी ऐप के माध्यम से कर सकता है अथवा स्वयं घोषणा भी कर सकता है कि खेत में क्या फसल बोई गई है। इसके साथ ही शासन की नई कृषि योजनाओं की जानकारी भी प्राप्त कर सकता है।

नए ऐप की जानकारी सभी किसानों को नहीं है। शहरी क्षेत्र के किसानों को तो इसके बारे में जानकारी मिल रही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी किसानों को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। प्रशासन की **टीम ग्रामीण इलाकों** के किसानों को ऐप की खूबियों की जानकारियां देने के लिए उन्हें जागरूक भी करेगी।

वहीं मप्र में ब्रिटिश शासनकाल में बने नक्शे का नई तकनीकी से नवीनीकरण करने के लिए अगले माह सर्वे करने की तैयारी की गई है। इसके लिए भोपाल, इंदौर, जबलपुर व ग्वालियर सहित पूरे प्रदेश के अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। ब्रिटिश शासनकाल में जरीब से जमीनों की नपती के आधार पर नक्शे बनाए जाते थे, जिसमें कई खामियां रहती थीं, लेकिन नए नक्शे में खामियों की गुंजाइश ही नहीं रहेगी।

प्रदेश के राजस्व विभाग के पास जो नक्शे उपलब्ध हैं वह बहुत पुराने हो गए हैं तथा समय के साथ भौगोलिक स्थिति में परिवर्तन, भूमि की बिक्री, बंदोबस्त के समय तकनीकी त्रुटि एवं मैनुअल के अनुसार होने वाली मानवीय त्रुटियों के कारण नक्शे का मिलान वास्तविक स्थिति से नहीं हो पा रहा है। इसके कारण सीमांकन, नामांतरण, बंटवारा और बंटाकन आदि की प्रक्रिया बाधित हो रही है। सैटेलाइट डिजीटल के माध्यम से जो नक्शे बनाए जाएंगे, उसमें भू-राजस्व अभिलेख तो शुद्ध होंगे ही, वहीं नामांतरण और सीमांकन सहित अन्य जमीन संबंधी समस्याओं का निराकरण एवं भूमि के क्रय-विक्रय में सुगमता होगी।

● **धर्मेन्द्र सिंह कथूरिया**

अपराधों में आएगी कमी

मप्र भू-राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत धारा 65, 67,107 और 108 एवं भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख नियम 2020 के तहत नक्शे में आबादी की भूमि को छोड़कर सभी का सर्वे किया जाएगा। भू-अभिलेख आयुक्त ज्ञानेश्वर पाटिल ने बताया कि भू-अभिलेखों को आधुनिक करने का कार्य सबसे महत्वपूर्ण है, जिसे गंभीरता से लेते हुए नए नक्शे बनाए जाएंगे। वर्तमान में नक्शे और मौके पर भिन्नता होने से ग्रामीणों में आपसी विवाद की स्थिति बनती है, जो बाद में अपराधों को भी जन्म देती है। यहां तक कि कई सालों तक तहसील न्यायालय से लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जमीन संबंधी मामले चलते रहते हैं, लेकिन नए नक्शे में भूमि विवाद सुगमतापूर्वक सुलझाने से अपराधों में भी कमी आएगी। नए नक्शे में राजस्व विभाग का अपना रिकॉर्ड तो सही होगा ही, वहीं राजस्व अभिलेख पर आधारित योजनाओं को उचित ढंग से लागू करने में भी सुविधा होगी। साथ ही शासन की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत किए जा रहे भू-अर्जन में भी राजस्व अभिलेख के शुद्ध होने से आसानी होगी। इस प्रकार सर्वे रिजर्व के कार्य से जहां एक ओर भूमि स्वामी को लाभ होगा, वहीं दूसरी ओर राज्य शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन में भी आसानी होगी।

जंगलों में आग से खतरे

यह पूरे देश के वन विभाग के लिए अलर्ट मोड पर रहने का वक्त है, क्योंकि गर्मियों का मौसम शुरू होते ही जंगलों में आग लगने की घटनाएं तेज हो गई है। मप्र हो या छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा हो या उत्तराखंड, कोई राज्य इससे अछूता नहीं रह गया है। आग लगने की घटनाएं एक या दो दर्जन नहीं, बल्कि हजारों की संख्या में हो रही हैं। कई दिनों से मप्र के सबसे ज्यादा बाघों वाले बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट के 7 वन क्षेत्र आग से धधक रहे हैं। जंगल में एक नहीं, बल्कि कई जगहों पर आग लगी हुई है। इस आग से पेड़ पौधों के जलने से पर्यावरण, वन्यप्राणियों को भारी नुकसान की आशंका है।

वन विभाग का अमला टैंकरों से आग बुझाने की कोशिशों में लगा है। हालात कितने गंभीर हैं इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बांधवगढ़ में गत दिनों बड़ी संख्या में हिरण, चीतल जैसे वन्य प्राणी अपनी जान बचाने भागते हुए देखे गए हैं। बांधवगढ़ में पर्यटन फिलहाल रोक दिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आपात बैठक बुलाकर जंगलों की आग की समीक्षा के साथ ही अफसरों को खास हिदायत दी है कि वन्य प्राणियों की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री के साथ अफसरों की **बैठक** करीब एक घंटे तक चली थी, जिसमें यह बात सामने आई थी कि आग बुझाने के तमाम प्रयास फेल होने के बाद पार्क में पर्यटन रोक दिया गया है। बता दें कि एक हफ्ते पहले पन्ना टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट भी आग से झुलस चुका है। देवास के जंगलों की अलग-अलग बीटों में आग लगने की कई खबरें सामने आ रही हैं।

बता दें कि दो साल पहले भी बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट एरिया के वनक्षेत्रों में ऐसी ही भयावह आग लगी थी। गर्मियों में जंगलों में आग लगने की घटनाओं को आम माना जाता है, लेकिन इस बार आग ने कुछ ज्यादा ही विकराल रूप धारण कर लिया। यह आग बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट के खितोली, मगधी और ताला जोन में लगी है। इसके अलावा रेगुलर फॉरेस्ट एरिया में भी कई जगह आग लगी है।

इस बार जंगल की आग से भारी नुकसान की आशंका व्यक्त की जा रही है। बताया जा रहा है कि आग में जंगल के कीमती पेड़ तो जल ही गए हैं, साथ ही वन्यप्राणियों, पशु-पक्षियों को भी भारी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री के साथ आपात बैठक में वन विभाग के अफसरों ने नुकसान का आंकलन करने और वन्यप्राणियों को नुकसान नहीं होने का दावा किया। लेकिन बताते हैं कि जिस तरह की आग लगी है, उससे वन्यप्राणियों का सुरक्षित रह पाना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि प्रभावित इलाकों के लोगों ने धुएं और आग से बचने के लिए हिरन, चीतल, सूअर जैसे वन्य प्राणियों को भागते और पक्षियों को पलायन करते देखा है।

फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मप्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा और अरुणाचल समेत कई राज्यों में नवंबर से जनवरी तक जंगल में आग लगने की 2984 घटनाएं हुईं, जिनमें सर्वाधिक 470 उत्तराखंड में दर्ज की गई हैं। कुमाऊं मंडल में बीते चार माह में आग लगने की 276 घटनाएं सामने आईं। आग की घटनाओं में 396 हैक्टेयर जंगल जलकर राख हो गया और 2603 लोग इन घटनाओं में प्रभावित हुए। वहीं गढ़वाल मंडल में बीते चार महीनों में आग लगने की 430 घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें 501 हैक्टेयर जंगल जले हैं। इस आग में 6350 पेड़ जले हैं। साल 2021 में अभी तक जंगल में लगी आग की वजह से चार लोगों की मौत हो चुकी है।

छत्तीसगढ़ के जंगलों में आग लगने की घटनाएं कितनी तेजी से बढ़ी हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले साल यानी 2020 में छत्तीसगढ़ में 4 हजार 713 घटनाएं हुईं थीं। उसकी तुलना इस साल के अभी गुजरे केवल तीन शुरुआती महीनों में 11 मार्च 2021 तक 4 हजार 507 जंगलों में आग लगने की घटनाएं हो चुकीं थीं। इस साल अग्निकांड की सबसे ज्यादा घटनाएं मार्च के महीने में ही हुईं हैं। केवल एक दिन 11 मार्च को छत्तीसगढ़ के जंगलों में 715 जगह आग लगी। ये घटनाएं बीजापुर और उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व में सबसे ज्यादा हुईं। बीजापुर में 11 मार्च तक 446 और टाइगर रिजर्व में 509 जगहों पर आग लगी।

● **श्याम सिंह सिकरवार**

इन कारणों से जंगल में लगती है आग

जंगल, पहाड़ और उसकी तलहटी से सटे क्षेत्रों में आग लगने के अलग-अलग कारण हैं। इनमें कई जगहों पर जंगल से महुआ चुनने के लिए स्थानीय लोगों द्वारा ही आग लगा दी जाती है। कहीं-कहीं लोग जंगली क्षेत्र से गुजरने के दौरान बीड़ी अथवा सिगरेट पीते हुए गुजरते हैं और जलती हालत में जंगल में फेंक देते हैं, जिससे आग लग जाती है। महिलाओं के घर के चूल्हे की राख जंगल में फेंकने से भी आग पकड़ लेती है। अक्सर महिलाएं ईंधन और चारा लेने जंगल जाती हैं और पेड़ों की ठूंठों में आग लगा देती हैं। उन्हें लगता है कि आग लगाने के बाद अच्छी घास उगेगी। आप खैर मना सकते हैं कि विदेशों जैसी आग देश के जंगलों में नहीं लगती, वरना वास्तव में हमारी हैसियत फायर ब्रिगेड के जरिए या बाल्टियों में पानी भरकर बुझाने से ज्यादा नहीं है। बात सुनने में बुरी जरूर लगती है, लेकिन यह तो मानना ही पड़ेगा कि आग बुझाने के लिए आधुनिक संसाधनों की उपलब्धता के मामले में हम बहुत पिछड़े हुए हैं। जंगल हों या शहरों की इमारतें आग बुझाने के संसाधन जो हैं भी, वो भी चालू हालत में कम ही मिलते हैं। ओडिशा के जंगलों में आग लगने की घटनाओं के बारे में जानकर आप चौंक पड़ेंगे, क्योंकि राज्य में इस साल केवल 22 फरवरी से 1 मार्च के बीच जंगल में आग लगने की 5 हजार 291 घटनाएं हुईं। इसके अलावा झारखंड में भी मार्च की शुरुआत में ही हजारीबाग के पूर्वी प्रमंडल के बरही जवाहर घाट में एनएच किनारे जंगल में भयावह आग लगी थी। गत दिनों एक हिरण की यहां मौत हो गई। गुमला जिले में मार्च में जंगलों में एक-दो दर्जन नहीं 70 से ज्यादा बार आग लग चुकी है। जंगलों में आग लगने से सिर्फ पेड़-पौधों को ही नुकसान नहीं हो रहा है, बल्कि पशु-पक्षी भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। पिछले महीने दलमा के जंगलों में लगी आग में झुलसने से चार हिरणों, 8 मोरों और दर्जनभर से ज्यादा खरगोशों की मौत हो गई। कई जंगली सूअर भी आग से मारे गए हैं।

बुंदेलखंड अपनी बदहाली के लिए भले ही ख्यात है, लेकिन यहां की धरती खनिज संपदा से भरी हुई है। बुंदेलखंड के छतरपुर जिले के बकस्वाहा के जंगलों में हीरे की सबसे बड़ी खदान मिली है। इस खदान के मिलने के बाद पूरे देश की नजर इस ओर हो गई है।

मिला सबसे बड़ा हीरा भंडार

मप्र के छतरपुर जिले में देश का सबसे बड़ा हीरा भंडार मिलने का दावा किया जा रहा है। यहां के बकस्वाहा जंगल में 3.42 करोड़ कैरेट हीरे दबे होने का अनुमान है। इस हीरा भंडार को निकालने के लिए 382.131 हैक्टेयर जंगल खत्म किया जाएगा। अभी तक देश का सबसे बड़ा हीरा भंडार मप्र के ही पन्ना जिले में है। यहां कुल 22 लाख कैरेट हीरे का भंडार है। इनमें 13 लाख कैरेट हीरा निकाला जा चुका है। बकस्वाहा के जंगल में पन्ना से 15 गुना ज्यादा हीरे का भंडार होने का अनुमान है। बंदर डायमंड प्रोजेक्ट के तहत इस स्थान का सर्वे 20 साल पहले शुरू हुआ था। दो साल पहले प्रदेश सरकार ने इस जंगल की नीलामी की। आदित्य बिड़ला समूह की एस्सेल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने खनन का टेंडर हासिल किया। मप्र सरकार बकस्वाहा जंगल में हीरा भंडार वाली 62.64 हैक्टेयर जमीन इस कंपनी को 50 साल के लिए लीज पर दे रही है। वन विभाग ने इस जमीन पर खड़े पेड़ों की गिनती कर ली है, जो 2,15,875 हैं। इनको काटना पड़ेगा। इनमें सागौन, केम, पीपल, तेंदू, जामुन, बहेड़ा, अर्जुन के पेड़ हैं।

पहले आस्ट्रेलियाई कंपनी रियोटिंटो ने खनन लीज के लिए आवेदन किया था। मई 2017 में संशोधित प्रस्ताव पर पर्यावरण मंत्रालय के अंतिम फैसले से पहले ही रियोटिंटो ने यहां काम करने से इनकार कर दिया था। आपको बता दें कि रियोटिंटो कंपनी का संबंध पीएनबी स्कैम के भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी से है। इस कंपनी को दागदार माना गया है। आदित्य बिड़ला ग्रुप की एस्सेल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 382.131 हैक्टेयर जमीन की मांग की है। 62.64 हैक्टेयर में हीरा खदान होगी, बाकी 205 हैक्टेयर जमीन का उपयोग खनन और प्रोसेसिंग के दौरान निकले मलबे को डंप करने में किया जाएगा। कंपनी यहां 2500 करोड़ रुपए का निवेश करेगी।

इस जंगल के बदले बकस्वाहा तहसील में ही 382.131 हैक्टेयर राजस्व जमीन को वनभूमि में डायवर्ट करने का प्रस्ताव कलेक्टर छतरपुर ने कंपनी को दिया है। इस जमीन पर जंगल विकसित करने पर आने वाली लागत का भुगतान एस्सेल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी करेगी। छतरपुर डीएफओ अनुराग कुमार ने बताया कि वर्तमान में पर्यावरण मंत्रालय की ओर से गठित हाई पावर कमेटी के सामने सुनवाई चल रही है। कमेटी से निर्देश मिलने पर नई रिपोर्ट देंगे। दिसंबर 2020 में दी गई रिपोर्ट पुराने डीएफओ ने दी है। साल 2000 से 2005 के बीच ऑस्ट्रेलियाई कंपनी रियोटिंटो ने हीरा भंडार की खोज के लिए बुंदेलखंड क्षेत्र में सर्वे किया था, जिसमें किंबरलाइट की चट्टानें दिखाई दीं। हीरा किंबरलाइट की चट्टानों में मिलता है। गौरतलब है कि बंदर डायमंड प्रोजेक्ट के तहत इस स्थान का सर्वे 20 साल पहले शुरू हुआ था। दो साल पहले प्रदेश सरकार ने इस जंगल की नीलामी की। आदित्य बिड़ला समूह की एस्सेल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने सबसे ज्यादा बोली लगाई। प्रदेश सरकार यह जमीन इस कंपनी को 50 साल के लिए लीज पर दे रही है। इस जंगल में 62.64 हैक्टेयर क्षेत्र हीरे निकालने के लिए चिन्हित किया है।

यहीं पर खदान बनाई जाएगी लेकिन कंपनी ने 382.131 हैक्टेयर का जंगल मांगा है, ताकि 205 हैक्टेयर जमीन का उपयोग खनन करने और प्रोसेस के दौरान खदानों से निकला मलबा डंप करने में किया जा सके। इस काम में कंपनी 2500 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। पहले आस्ट्रेलियाई कंपनी रियोटिंटो ने खनन लीज के लिए आवेदन किया था। मई 2017 में संशोधित प्रस्ताव पर पर्यावरण मंत्रालय के अंतिम फैसले से पहले ही रियोटिंटो ने यहां काम करने से इनकार कर दिया था। दरअसल, 2000 से 2005 के बीच सर्वे कराया था बुंदेलखंड क्षेत्र में हीरा की खोज के लिए मप्र सरकार ने सर्वे ऑस्ट्रेलियाई कंपनी रियोटिंटो ने किया था। सर्वे में टीम को नाले के किनारे किंबरलाइट पत्थर की चट्टान दिखाई दी। हीरा किंबरलाइट की चट्टानों में मिलता है। छतरपुर के सीसीएफ पीपी टिटारे का कहना है कि जहां बंदर प्रोजेक्ट की खदान बनना है, वहां अभी 2.15 लाख पेड़ का जंगल है। इस जंगल के बदले बकस्वाहा तहसील में ही 382.131 हैक्टेयर राजस्व जमीन को वनभूमि में डायवर्ट करने का प्रस्ताव कलेक्टर छतरपुर ने दिया है। इस जमीन पर जंगल विकसित करने पर आने वाली लागत का भुगतान कंपनी करेगी।

● **सिद्धार्थ पांडे**

5 साल में रिपोर्ट बदली

हीरे निकालने के लिए पेड़ काटने से पर्यावरण को भारी नुकसान होना तय है। इसके अलावा वन्यजीवों पर भी संकट आ जाएगा। मई 2017 में पेश की गई जियोलॉजी एंड माइनिंग मप्र और रियोटिंटो कंपनी की रिपोर्ट में तेंदुआ, बाज (वल्चर), भालू, बारहसिंगा, हिरण, मोर इस जंगल में होना पाया था लेकिन अब नई रिपोर्ट में इन वन्यजीवों के यहां होना नहीं बताया जा रहा है। दिसंबर में डीएफओ और सीएफ छतरपुर की रिपोर्ट में भी इलाके में संरक्षित वन्यप्राणी के आवास नहीं होने का दावा किया है। जमीन में दबे 3.42 करोड़ कैरेट हीरे को निकालने के लिए 382.131 हैक्टेयर का जंगल खत्म किया जाएगा। वन विभाग ने जंगल के पेड़ों की गिनती की, जो 2,15,875 है। इन सभी पेड़ों को काटा जाएगा। इनमें 40 हजार पेड़ सागौन के हैं, इसके अलावा केम, पीपल, तेंदू, जामुन, बहेड़ा, अर्जुन जैसे औषधीय पेड़ भी हैं। अभी तक देश का सबसे बड़ा हीरा भंडार पन्ना जिले में है। यहां जमीन में कुल 22 लाख कैरेट के हीरे हैं। इनमें से 13 लाख कैरेट हीरे निकाले जा चुके हैं। 9 लाख कैरेट हीरे और बाकी हैं। बकस्वाहा में पन्ना से 15 गुना ज्यादा हीरे निकलने का अनुमान है। छतरपुर के डीएफओ अनुराग कुमार का कहना है कि वर्तमान में पर्यावरण मंत्रालय की ओर से गठित हाई पावर कमेटी के सामने सुनवाई चल रही है। कमेटी से निर्देश मिलने पर नई रिपोर्ट देंगे। दिसंबर 2020 में दी गई रिपोर्ट पुराने डीएफओ ने दी है।

ये जलते और दफन होते मृत शरीर। पसीने से भीगे नीले-सफेद पीपीई किट में रिश्तेदार। मुंह-नाक पर बचाव का मास्क और आंखों में अपनों को खोने का बहता हुआ दर्द। ये तस्वीरें नहीं हैं...ये हमारी लापरवाही, लचर सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था और प्रशासन की कमजोरियों की जलती और दफन होती लाशें हैं। देश में ऐसे भयावह दर्दनाक नजारे हर तरफ से देखने को मिल रहे हैं। ये तस्वीरें कोरोना वायरस के गंभीर संकट को दिखा रही हैं।

● राजेंद्र आगाल

कब होगा कोरोना महामारी का अंत? यह वह सवाल था जो पूरे 2020 में हम सब पर हावी था, विशेषज्ञों से हमने यह जाना कि कोरोना को नियंत्रित तो किया जा सकता है लेकिन अभी यह बीमारी काफी लंबे समय तक हमारे बीच रहने वाली है। इसके बाद देशवासियों का सारा फोकस कोरोना महामारी की वेव में स्थानांतरित हो गया। वर्तमान में भारत कोरोना महामारी की दूसरी राष्ट्रव्यापी लहर का सामना कर रहा है। कुछ स्थानों पर अधिक वेव देखी गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में कहा था कि शहर कोरोना महामारी की चौथी लहर के साथ दूसरी राष्ट्रव्यापी लहर देख रहा है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने कोरोना संक्रमण के दैनिक मामलों को 1.26 लाख से अधिक कर दिया है। जो कि इस समय का उच्चतम है। अब जबकि एक बार फिर से स्थिति बद से बदतर हो गई है सवाल ये है कि भारत में कोरोना की दूसरी लहर कब तक समाप्त हो सकती है?

हर तरफ मौत, मायूसी, बेबसी जैसे पसरी हुई है। जो चंद दिनों पहले कोरोना पर विजय का दंभ भर रहे थे, वे किन्हीं छद्म के आवरणों में छुप गए हैं। किसी को कुछ सूझ नहीं रहा है। ऐसे मंजर की कभी किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। नीति आयोग की एक समिति ने मई में हर रोज 6 लाख नए मामलों के अनुसार प्लान-बी बनाने का सुझाव दिया है। यानी संक्रमण का ये सिलसिला मई में दोगुना हो सकता है।

भारत अब पूरी तरह से हेल्थ इमरजेंसी की गिरफ्त में है। फिर भी सरकार नकार के मूड में है, जैसे हर समस्या से निपटने का उसके पास एक ही तरीका है, सच्चाई छुपा दो और सच बोलने वालों को धमका दो। अपने इसी अभियान के साथ सरकार ने सोशल मीडिया से कई पोस्ट डिलीट करने के निर्देश जारी कर दिए हैं, लेकिन फेसबुक, ट्विटर से लेकर सभी प्लेटफॉर्म अस्पताल में लोगों की लाचारी, अंतिम संस्कार की तस्वीरें और वीडियो से भरे पड़े हैं। इन तस्वीरों में श्मशान का मंजर भी भयावह है। श्मशान में नंबर लगाना और पांच-छह घंटे इंतजार करना पड़ रहा है।

सब नकारती सरकार

सरकार है कि किसी तरह की किल्लत मानने को तैयार ही नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने पिछले हफ्ते कहा कि रेमडेसिविर जैसी जरूरी एंटी-वायरल दवा, वैक्सीन और ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। इसके विपरीत कई मुख्यमंत्री इन जरूरी चीजों की मांग केंद्र से लगातार कर रहे हैं। कई हाइकोर्ट ऑक्सीजन की किल्लत दूर करने का निर्देश जारी कर चुके हैं। इसलिए कांग्रेस नेता तथा पूर्व केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम ने कहा, 'मैं स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के बयान से हैरान-परेशान हूं कि ऑक्सीजन, वैक्सीन और रेमडेसिविर की कोई कमी नहीं है। क्या डॉक्टर झूठ बोल रहे हैं? क्या मरीजों के परिजन झूठ बोल रहे है? क्या सारे वीडियो और फोटो फर्जी हैं?' चिदंबरम ने यह भी कहा कि, जनता को ऐसी सरकार के खिलाफ विद्रोह करना चाहिए, जो यह मानकर चल रही है कि भारत के सभी लोग मूर्ख हैं। केंद्र ही नहीं, उप्र, मप्र और गुजरात की सरकारें भी कमी स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो कहा कि, कहीं कोई कमी नहीं है। सोशल मीडिया पर और दूसरी मीडिया पर ऐसा कहने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि दूसरी लहर से निपटने के तरीके पर दुनियाभर के प्रमुख मीडिया संस्थानों ने सरकार की तीखी आलोचना की है।

दरअसल, इस साल 7 मार्च को स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने दावा किया था कि कोरोना महामारी अब खात्मे की ओर है। हालांकि उन्होंने

मप्र में आंकड़ों में 'हेरफेर'

मप्र में ऑक्सीजन की कमी ने एक गंभीर रूप ले लिया है। खासकर सूबे की राजधानी भोपाल में। गत दिनों भोपाल में 5 लोग इसी कारण मर गए, जबकि एक अस्पताल ने ऑक्सीजन की कमी के चलते बहुत से मरीजों की छुट्टी कर दी। मप्र सरकार ने भोपाल में 7 दिन के कोरोना-कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है, जिसे 12-19 अप्रैल के बीच लागू किया जा रहा है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि हर अस्पताल को ऑक्सीजन सप्लाई सुनिश्चित की जाए। लेकिन, साथी भाजपा विधायक और पूर्व राज्य स्वास्थ्य मंत्री अजय विश्नोई ने जिलों की एक समीक्षा बैठक के दौरान, 'हेराफेरी युक्त आंकड़े' पेश करने के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान पर सवाल खड़े किए हैं। जबलपुर के पास पाटन के विधायक विश्नोई ने सुलेमान से पूछा कि वो मौत के आंकड़े क्यों छिपा रहे हैं, जबकि अकेले जबलपुर में 'रोजाना 15 से 20 लोगों की मौतें हो रही हैं, जबकि उनमें से केवल तीन या चार रिपोर्ट की जा रही हैं।' विश्नोई ने बताया 'मैंने उनसे कहा कि इससे (संख्या में हेरफेर से) किसे फायदा पहुंचेगा? लोगों को अस्पतालों में बिस्तर नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं है, ये एक सच्चाई है और छिपाने की बजाय, हमें इसे स्वीकार करना चाहिए।' पूर्व मंत्री ने आखिरकार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दखल देने के बाद अपने हमले बंद किए लेकिन उन्होंने आगे कहा, 'मैंने मुख्यमंत्री को स्वास्थ्य अधिकारियों की बदइंतजामी के बारे में बताया है। हमारी प्राथमिकता इंसानी जिंदगियां बचाना है। अधिकारी लोग बेपरवाह हो गए हैं और उन्हें लगा कि कोरोना खत्म हो गया लेकिन नई लहर गंभीर है और इसके प्रकोप को रोकने तथा त्वरित टीकाकरण मुहैया कराने के लिए पूरे सिस्टम को तेजी से काम करना होगा।'

फरवरी के मध्य में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की उस चेतावनी पर ध्यान देना उचित नहीं समझा कि कोरोना की ज्यादा खतरनाक दूसरी लहर आ सकती है, और उसके लिए तैयारियां की जानी चाहिए। डब्ल्यूएचओ ही नहीं, नीति आयोग की टॉस्क फोर्स के सदस्य, दिल्ली में एम्स के निदेशक डॉ. रणदीप गुलेरिया भी दूसरी लहर से संबंधित चेतावनी दे चुके थे। असल में मार्च के पहले हफ्ते में रोजाना 10-15 हजार संक्रमण के मामले आ रहे थे और मौत का आंकड़ा 100 के करीब था। यही नहीं, केंद्र सरकार ने नवंबर 2020 में संसदीय समिति की उस रिपोर्ट को नजरअंदाज कर दिया, जिसमें कोरोना की दूसरी लहर के लिए तैयार रहने को कहा गया था।

नवंबर में ही मिल चुकी थी चेतावनी

समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव की अध्यक्षता में स्वास्थ्य पर गठित स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (एनपीपीए) को ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत का निर्धारण करना चाहिए, ताकि वह किफायती दर पर उपलब्ध हो सके। इसके अलावा समिति ने कहा था कि सरकार ऑक्सीजन के उचित उत्पादन को प्रोत्साहित करे ताकि अस्पतालों में इसकी आपूर्ति अबाध रूप से हो सके। रिपोर्ट में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए देश के सरकारी अस्पतालों में बेड की अपर्याप्त संख्या का मुद्दा भी उठाया गया था। और उसी अधूरी तैयारियों का नतीजा है कि कोरोना संक्रमण इतना बढ़ गया है।

अब सवाल यह उठता है कि जब सरकार ने कोरोना खत्म होने का जश्न मनाते हुए अपनी वैक्सीन डिप्लोमेसी पर पीठ थपथपानी शुरू कर दी थी, तो फिर मामले इतने तेजी से कैसे बढ़ गए। इसके लिए कुछ घटनाओं को याद करना भी बेहद जरूरी है। 26 फरवरी को चुनाव

जलती चिताएं खोल रही हैं सरकारी आंकड़ों की पोल

देश में कोरोना महामारी का दूसरा दौर शुरू हो चुका है। एक बार फिर से सरकार के आंकड़े भयावह हो चुके हैं। 9 अप्रैल 2021 को जारी आंकड़ों के मुताबिक गत दिनों एक दिन में कोरोना की वजह से 780 मौतें हुई और कुल मरने वालों की संख्या 1,67,642 हो चुकी है, लेकिन क्या यह आंकड़े सही है। कुछ शहरों के श्मशान घाटों में के आंकड़े तो बेहद चौंकाने वाले हैं। मप्र की राजधानी भोपाल में कोराना वायरस के शिकार शवों के अंतिम संस्कार के इंतजाम नाकाफी हो रहे हैं। गत दिनों जगह कम पड़ने पर शवों का नियत जगह से अलग सड़क पर अंतिम संस्कार करना पड़ा। एक अकेले भदभदा विश्राम घाट पर ही 36 शवों का अंतिम संस्कार किया गया, 5 शवों को कब्रिस्तान में दफनाया गया।

आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों का ऐलान कर दिया। इसके तहत पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में चुनाव होने थे। इनमें पश्चिम बंगाल इकलौता राज्य है जहां पर 8 चरणों में मतदान हो रहे हैं। इन 5 राज्यों में करीब 18 करोड़ मतदाता हैं। इन चुनाव क्षेत्रों में न तो कोई सुरक्षा प्रोटोकॉल अपनाया जा रहा है और न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। नतीजा यह हुआ कि अकेले बंगाल में चुनाव के ऐलान के बाद से कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या में 75 गुना बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान पॉजिटिविटी रेट में भी भारी उछाल आया। अभी राज्य में एक लाख के करीब सक्रिय मामले हैं। जबकि 26 फरवरी को यह संख्या सिर्फ 3343 थी।

एक असफल पूर्वानुमान

जब पिछले साल कोरोना वायरस महामारी पूरे भारत में फैल रही थी, तब सरकार ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय सांख्यिकी संस्थान और भारतीय विज्ञान संस्थान से तैयार विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त की थी। समिति ने भारतीय परिस्थितियों की खासियत के आधार पर एक सुपर मॉडल विकसित किया। सुपर मॉडल ने भविष्यवाणी की थी कि कोरोना महामारी फरवरी 2021 में भारत में हर्ड इम्युनिटी के कारणवश खत्म हो जाएगी। मॉडल ने अनुमान लगाया कि कोरोना के प्रत्येक लैब से कंफर्म हुए मामले के लिए 60-65 स्पर्शोन्मुख अवांछित संक्रमण थे। यह अनुमान इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के सीरो-सर्वे के 26-32 अनिर्धारित कोरोना मामलों के प्रत्येक प्रयोगशाला पुष्टिकरण मामले के आंकलन से काफी अलग थे। समिति ने अक्टूबर में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जब भारत का कोरोना कैसेलोड 75 लाख के आसपास था। उस संख्या को आधार के रूप में लेते हुए, सुपर मॉडल ने अनुमान लगाया कि देश का वास्तविक कोरोना केसलोड भारत की आबादी का लगभग 50 करोड़ या 40 प्रतिशत के आसपास रहा होगा। फरवरी तक, कोरोना वेव को समाप्त होना था।

'डबल म्यूटेंट' से खतरा डबल?

कोरोना वायरस के नए रूप को उसका 'डबल म्यूटेंट' वेरिएंट बताते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मार्च के तीसरे हफ्ते में जानकारी दी कि 18 राज्यों में कोरोना के कई 'वेरिएंट ऑफ कंसर्न्स' (वीओसीज) पाए गए हैं। इसका मतलब यह निकलता है कि देश के कई हिस्सों में कोरोना वायरस के अलग-अलग प्रकार पाए गए हैं जो नया संकट खड़ा कर सकते हैं। इनमें ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील के साथ-साथ भारत में पाया गया नया 'डबल म्यूटेंट' वेरिएंट भी शामिल है। इन नई जानकारियों का खुलासा देश के विभिन्न हिस्सों में कोरोना मरीजों से लिए गए नमूनों (सैंपल्स) की जीनोमिक सीक्वेंसिंग के बलबूते हुआ है। जीनोम सीक्वेंसिंग का यह काम स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन काम कर रहे 10 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के समूहों ने किया जिसे इंडियन सार्स-सीओवी-2 कंसोर्टियम ऑन जीनोमिक्स कहा जाता है। इसका गठन 25 दिसंबर, 2020 को कोरोना के फैलने के मद्देनजर जेनेटिक कोड्स को समझने और फिर समस्या के ठोस निदान के सिलसिले में किया गया था। जीनोम सीक्वेंसिंग यानी जेनेटिक कोड का खाका तैयार करने की टेस्टिंग प्रक्रिया में इसने विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोरोना संक्रमितों के 10,787 नमूने जमा किए, जिनमें से 771 में 'वेरिएंट ऑफ कंसर्न्स' पाए गए। हालांकि जिस 'डबल म्यूटेंट' वेरिएंट की चर्चा इन दिनों देश में सबसे ज्यादा है, उसे लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की टिप्पणी है कि कोरोना के मामलों में हालिया इजाफे में इसकी ज्यादा बड़ी भूमिका नहीं है। तो सवाल उठता है कि आखिर क्या वजह है जो काबू में आता वायरस एक बार फिर पकड़ से बाहर होने लगा है।

धीमा टीकाकरण या लापरवाही

भारत जैसी विशाल आबादी वाले देश में किसी भी योजना से प्रत्येक नागरिक को जोड़ने के लिए लंबा वक्त चाहिए। टीकाकरण जैसे मामलों में तो यह अवधि और भी लंबी खिंच सकती है क्योंकि अव्वल तो ऐसी मुहिमों को लेकर जागरूकता नहीं होती और संदेह भी ढेरों होते हैं। कोरोना की वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स की खबरों और अफवाहों के चलते लोग पहले से ही इस अभियान को शक की नजर से देख रहे थे, बाकी समस्या आबादी को देखते हुए इसमें उम्र के वर्गीकरण ने पैदा कर दी। उपाय यही बचता है कि टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाई जाए। सरकार ने वैक्सीन के लिए उम्र का दायरा घटाकर 45 साल तक किया। यह नया प्रबंध भी कहता है कि 45 पार की आबादी को टीका लगाने में भी चार महीने का वक्त लगेगा। इतने अरसे में तो न जाने कितना पानी गंगा में बह जाएगा। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि जब देश में हर रोज 50 हजार नए केस आने लगेंगे, तो कोरोना संक्रमण से ग्रसित लोगों को संख्या कम करने में सरकारी मशीनरी के पसीने ही छूट जाएंगे। टीकाकरण की मंद रफ्तार ही कोरोना के लौट आने की मुख्य वजह नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने अध्ययन में पाया कि महाराष्ट्र, केरल और पंजाब जैसे सर्वाधिक संक्रमण वाले राज्यों समेत देश के कुल 16 राज्यों के 70 जिले ऐसे हैं, जहां मार्च के

वैक्सीन-वेंटिलेटर पर घमासान

देश में बढ़ते कोरोना के मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है। जानलेवा कोरोना वायरस को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच जबरदस्त आरोप-प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। कांग्रेस सहित विपक्षी पार्टियों के निशाने पर केंद्र सरकार है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी देश के सभी लोगों के लिए कोरोना के टीके की पैरवी कर चुके हैं। राहुल ने कहा कि इस टीके की जरूरत को लेकर बहस करना हास्यास्पद है। हर भारतीय सुरक्षित जीवन का मौका पाने का हकदार है। इसलिए हर भारतीय को वैक्सीन मुहैया कराई जाए। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। रघु शर्मा ने कहा कि भारत सरकार ने हमें 1000 वेंटिलेटर भेजे हैं और हमने उन्हें लगाया, लेकिन ये वेंटिलेटर्स दो-ढाई घंटे में काम करना बंद कर देते हैं। जब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रिव्यू मीटिंग की और वेंटिलेटर्स बंद होने का मामला सामने आया तो मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि भारत सरकार को इन वेटिलेंटर्स के बारे में जानकारी दी जाए। रघु शर्मा ने कहा कि हम इस मुद्दे पर राजनीति नहीं कर रहे हैं। इससे पहले महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा था कि राज्य में कोरोना वैक्सीन का स्टॉक सिर्फ 3 दिन के लिए ही बचा है। ऐसे में केंद्र सरकार को महाराष्ट्र को तत्काल कोरोना वैक्सीन की 40 लाख डोज मुहैया करानी चाहिए। टोपे के इस बयान के बाद राज्य के कुछ इलाकों में कोरोना वैक्सीनेशन को बंद करना पड़ा था। इसकी वजह यह बताई गई कि इन जगहों पर वैक्सीन खत्म हो चुकी है। लिहाजा वैक्सीन आने तक टीकाकरण का अभियान बंद करना पड़ेगा। इधर, इससे उलट पूर्व केंद्रीय मंत्री और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने कहा है कि केंद्र सरकार कोरोना महामारी से निपटने के लिए महाराष्ट्र सरकार के साथ पूरा सहयोग कर रही है। पवार का यह बयान अपने आप में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं आंध्रप्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी टीकों की कमी की शिकायत की गई है। इधर, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने आरोपों का जवाब देते हुए महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ सरकार पर गलत सूचना और भय फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के नेताओं द्वारा टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं। जिनका उद्देश्य टीकाकरण पर गलत सूचना देना और भय फैलाना है। बेहतर होगा कि राज्य सरकार राजनीति पर ध्यान देने की बजाय अपनी आधारभूत स्वास्थ्य संरचना पर जोर दें। वहीं डॉ. हर्षवर्धन ने महाराष्ट्र को लेकर कहा कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा जिम्मेदारी से कार्य न करना समझ से परे है, लोगों में दहशत फैलाना मूर्खता है।

पहले पखवाड़े में कोरोनों के सक्रिय मामलों में 150 फीसदी की तेजी दर्ज की गई। यही तेजी कोरोना की दूसरी लहर उठाने का असली सबब बन गई है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि लगभग 9-10 महीने वायरस की दहशत के साये में जी लेने और फिर टीकाकरण अभियान शुरू हो जाने के बाद लोगों के मन से कोरोना का डर निकल गया। कुछेक अपवादों को छोड़कर लोग ट्रेनों में धड़ल्ले से सफर कर रहे हैं, बाजारों में उन्होंने रौनकें लगा दी हैं और उनकी बदौलत अर्थव्यवस्था की चाल फिर अपनी गति पर आने लगी है, लेकिन सामान्य जनजीवन में लौट आने वाली उनकी इस अदा का दूसरा पहलू यह है कि दो गज दूरी के नियम के उन्होंने धुर्रे उड़ा दिए हैं, मास्क पहनना उन्हें कोरोना से बड़ी मुसीबत लगने लगा है और हाथ धोने को उन्होंने पाप समझ लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आव्हान कर रहे हैं कि ट्रिपल टी (टीटीटी) यानी 'टेस्ट, ट्रेस, ट्रीट' को अमल में लाते हुए दो गज दूरी, मास्क जरूरी आदि हिदायतों का हर हाल में पालन हो, लेकिन इन सारे नियम-कायदों का चुनावी रैलियों से लेकर ऑटो-बस-कार के सफर तक में खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। प्रतीत होता है मानो लोगों ने मान लिया है कि अब कोरोना के साथ जिंदगीभर का साथ हो गया है।

कोविड-एप्रोप्रिएट बिहेवियर में कमी

कोरोना के मामले बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है कोविड-एप्रोप्रिएट बिहेवियर (कोरोना महामारी से बचाव के उपयुक्त उपाय) में कमी। कोरोनाकाल में साबुन से कई बार हाथ धोना, बाहर या भीड़-भाड़ वाले इलाकों में मास्क और सोशल डिस्टेंसिग का पालन करने जैसी आदतें लोगों के बीच आम हो गई थीं। लेकिन, बीते कुछ महीनों में लोगों में यह आदत कम होती चली गई। वैक्सीन आने की खबर ने इसे बढ़ाने में कुछ हद तक सहयोग किया। चुनावी राज्यों की रैलियों में आई भीड़ ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई। बाजारों, शॉपिंग मॉल्स आदि में लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। लोगों ने मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को केवल उन्हीं जगहों तक सीमित कर दिया, जहां मजबूरन उनका पालन करना जरूरी था। होली और कुंभ के दौरान लोगों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान लोगों में कोरोना टेस्ट और कोविड-एप्रोप्रिएट बिहेवियर को लेकर उदासीनता साफ नजर आई।

किसी भी महामारी के लंबे चलने के दौरान जब लोग उससे बचाव के तरीकों को किनारे रखते हुए पहले की तरह ही जीना शुरू कर देते हैं। इसे ही पेंडेमिक फटीग कहा जाता है। पेंडेमिक फटीग में लोगों के अंदर महामारी से संक्रमण का डर खत्म हो जाता है। लोग मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह किए बिना कहीं भी आसानी से आने-जाने और बाजारों आदि में पहुंचने लगते हैं। एक तरह से लॉकडाउन की थकावट को मिटाने के लिए जिम, स्वीमिंग पूल, सिनेमा, एंटरटेनमेंट पार्क आदि में बिना किसी डर के बड़ी संख्या में पहुंचने लगते हैं। भारत में भी अब लोग कोरोना संक्रमण को लेकर बेपरवाह होते नजर आ रहे हैं। पेंडेमिक फटीग की वजह से लोगों में गुस्सा बढ़ जाता है, चिड़चिड़ापन महसूस होता है, आत्मविश्वास में कमी आ जाती है, अनिद्रा, काम में मन न लगना आदि लक्षण सामने आते हैं।

स्थानीय स्तर पर लापरवाही

कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और कंटेनमेंट जोन जैसे शब्द लॉकडाउन के खत्म होने के साथ ही कमजोर पड़ते गए। राज्यों में रैपिड टेस्ट किए जाने लगे और आंकड़ों में कमी आने लगी। राज्य सरकारों के आदेशों के बावजूद स्थानीय स्तर पर प्रशासन ने घोर लापरवाही बरती। पेंडेमिक फटीग ने इसे और बढ़ावा दिया। इस दौरान अगर कुछ लोग

संक्रमित भी हुए, तो उन्होंने इसे आम सर्दी मानकर किसी को जानकारी भी नहीं दी। हालांकि, राज्य सरकारों ने कोरोना की दूसरी लहर सामने आने के साथ ही फिर से कमर कस ली है और कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के साथ कंटेनमेंट जोन बनाने के फैसले कर दिए गए हैं।

कोरोना वायरस के वेरिएंट

भारत में कोरोना वायरस के कई प्रकार सामने आए हैं। पंजाब में कोरोना संक्रमण की जांच में यूके वेरिएंट सामने आने से लोगों में दहशत है। दक्षिण अफ्रीकी, ब्राजील, अम अमेरिका के वेरिएंट भी भारत में पाए गए हैं। देश में कोरोना वायरस का एक नया डबल म्यूटेंट वेरिएंट सामने आया है। हालांकि, इससे संक्रमित लोगों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन, भारत में कोरोना के इतने वेरिएंट होना चिंताजनक है। इन सभी वेरिएंट की संक्रमण दर काफी ज्यादा है। कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए लोगों को महामारी से बचने के लिए सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों को मानना चाहिए। मास्क, बार-बार हाथ धोना और सोशल डिस्टेंसिंग (दो गज की दूरी) का पालन करना चाहिए। कोरोना संक्रमण के बढ़ने का कारण लोगों की इसे लेकर बढ़ी बेफिक्री है। इस पर फिर से नियंत्रण पाया जा सकता है, बस हमें कोरोना से बचाने वाले उपायों को हर जगह अपनाना होगा।

गांवों में टीकाकरण की मुश्किल राह

भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर शुरू हो गई है। वैसे इसमें एक बड़ी राहत की बात यह भी है कि अभी तक कुछ ही राज्यों में इस दूसरी लहर के संकेत मिले हैं। शोधकर्ताओं ने अलग-अलग अध्ययनों में पाया है कि दुनिया के अधिकांश देशों में कोरोना वायरस की दूसरी लहर, पहली से ज्यादा खतरनाक साबित हुई है, लेकिन हमारे देश में टीकाकरण के कार्यों में तेजी निश्चित रूप से इस संबंध में बड़ी राहत देने वाली खबर है। ऐसे में केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि 1 अप्रैल से देश में 45 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोग कोरोना रोधी टीका

लगवा सकेंगे।

दरअसल अब तक 45 से 60 वर्ष तक के केवल उन लोगों को ही टीकाकरण अभियान में शामिल किया गया था जो कुछ निर्दिष्ट बीमारियों से ग्रस्त थे। सरकारी आंकड़ों के अनुसार मार्च के आखिर तक 4.83 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। अच्छी बात यह भी है कि इनमें से लगभग 80 लाख लोगों को इस वैक्सीन का दूसरा डोज भी दिया जा चुका है। टीकाकरण कार्य में तेजी को देखते हुए सरकार को उम्मीद है कि अगस्त तक लगभग 30 करोड़ लोगों को टीका लग जाएगा। उल्लेखनीय है कि दो साल के भीतर देश की समग्र आबादी लगभग 1.3 अरब लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए रोजाना करीब 30 लाख लोगों का टीकाकरण किया जाएगा।

अगर कोरोना वायरस की चपेट में आकर प्रतिरोधक क्षमता हासिल कर चुके लोगों को टीके के दायरे से बाहर रखा जाए तो संभावित आंकड़ा थोड़ा कम हो सकता है। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि दो साल के इस लक्ष्य की पूर्ति करना क्या आसान है? निश्चित ही यह दो साल का महा मैराथन कठिन है और इस कठिनाई का कारण ग्रामीण और पिछड़े व दूरदराज के इलाकों में टीकाकरण सफल बनाना है। सर्वविदित है कि ग्रामीण और शहरी जिलों में टीकाकरण का अंतर जितना कम होगा, रोजाना के बढ़ते मामलों से निपटने में राज्य सरकारों को उतनी ही मदद मिलेगी। यानी ग्रामीण इलाकों में टीकाकरण पर उतना ही जोर देना होगा, जितना शहरी इलाकों में। वास्तव में तभी ग्रामीण इलाकों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाया जा सकेगा।

पिछले साल नीति आयोग ने देश के पिछड़ेपन की तस्वीर पेश करते हुए सबसे पिछड़े 100 जिलों की एक सूची जारी की थी। इन जिलों के पिछड़ेपन की कोई एक वजह नहीं है, इसके अनेक कारण हैं। जैसे ये दूरदराज के इलाकों में स्थित हैं, रोड और रेलवे कनेक्टिविटी खराब है। इन पिछड़े जिलों में या तो अक्सर सूखा पड़ता है या फिर उन्हें बाढ़ का प्रकोप झेलना पड़ता है। इन इलाकों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यकों की आबादी भी अधिक है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों में चुनौती और बढ़ जाती है। ऐसे क्षेत्रों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में या तो कर्मचारी नदारद हैं या फिर उनकी संख्या बहुत कम है। ऐसे में टीकाकरण को सुचारू तरीके से संपन्न कराने में जरूरत से ज्यादा संघर्ष करना होगा।

सरकारों ने महामारी के एक साल बाद भी कुछ नहीं सीखा

देशभर में एक बार फिर कोरोना बड़ी आक्रामकता से अपने पैर पसार रहा है। एक बार फिर ये बड़ी तेजी से लोगों की जिंदगियां लील रहा है। कोरोना वायरस का तांडव भारत ने पिछले साल की शुरुआत में देखा था। इस दौरान हम देशव्यापी कठिन लॉकडाउन से कोरोना वैक्सीन तक तो आ गए लेकिन आज एक बार फिर देश में माहौल बन रहा है जैसे स्थितियां सरकारों के हाथ से बाहर निकल गई हैं और फिर से लॉकडाउन हो सकता है। बड़ा सवाल यही है कि हमने महामारी के एक साल बाद भी क्या कुछ सीखा या हम अपने पुराने ढर्रे पर ही रहे। आज जो देश में हालत है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? खासकर देश की राजधानी दिल्ली जो केंद्र सरकार के सबसे पास है और यहां की राज्य सरकार भी बड़े-बड़े दावे करती है। लेकिन आज जिस तरह से केस बढ़ रहे हैं और लोग भयभीत हैं वो दोनों सरकारों की तैयारियों की पोल खोलते हैं। दिल्ली में आज भी सबसे अधिक केस आ रहे हैं। लोगों को अस्पताल में ठीक इलाज नहीं मिल रहा है। मजदूर वर्ग एक बार फिर भयभीत है कि कहीं सरकार अचानक से फिर लॉकडाउन की घोषणा न कर दे। इन सब स्थितियों के बीच सरकार टीवी चैनलों के माध्यम से बड़े-बड़े दावे भले कर ले लेकिन जमीन पर सरकारी दावे फेल होते दिख रहे हैं। राजधानी में एक बार फिर मरीजों को कोरोना के नाम पर इलाज के लिए मना किया जा रहा है।

प्रवासियों को नहीं भाया गांव

आधी मजदूरी में कब तक गुजारा

सर्वे में यह बात सामने आई है कि शहरों से जो करोड़ों लोग अपने घरों को लौटे थे उनमें से एक बड़ी संख्या वापस नहीं गई। कुछ को दोबारा काम नहीं मिला तो कुछ दोबारा शहर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। जो लोग शहरों में 500-600 रुपए रोज कमाते थे उनमें से कईयों की कमाई आधे से कम हो गई है। 40 साल के राम सिंह यादव गाजियाबाद की एक फैक्ट्री में काम करते थे। महीने में करीब 12 हजार रुपए कमाते थे लेकिन अब अपने गांव में रहते हैं और रोज के 200 रुपए की दिहाड़ी पर एक व्यापारी के यहां रात की चौकीदारी करते हैं। राम सिंह बताते हैं, लॉकडाउन में जैसे-तैसे घर लौटे। वहां फैक्ट्री मालिक ने पुराने काम के पैसे भी नहीं दिए बदकिस्मती से यहां एक एक्सीडेंट में पैर टूट गया। कुछ दिन घर में रखा राशन पानी बेचकर काम चला लेकिन बाद में खर्च चलाने के लिए जमीन (खेत) गिरवी रखनी पड़ी। पड़ोस के एक व्यापारी ने तरस खाकर काम दे दिया है, 200 रुपए रोज पर बात तय हुई है। राम सिंह का घर मप्र के टीकमगढ़ जिले कुड़ीला गांव में है। लॉकडाउन के बाद यह गांव आबाद हो गया था। इस गांव में सैकड़ों प्रवासी श्रमिक लौट आए थे। कुड़ीला गांव ने अरसे बाद एकसाथ इतने लोगों को देखा था। इस गांव के तमाम लोग दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में कमाने जाते हैं, राम सिंह के मुताबिक लॉकडाउन में वापस आने के बाद कई लोग दोबारा नहीं गए। ये आधी-अधूरी मजदूरी से काम चला रहे हैं।

कोरोना संक्रमण के चलते 23 मार्च 2020 में हुए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन में हजारों लोगों की नौकरी चली गईं, आजीविका छिन गई। देश में लॉकडाउन का एक साल पूरा होने से करीब दो माह पहले यानी 8 फरवरी 2021 को संसद के बजट सत्र के दौरान केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संतोष गंगवार ने एक रिपोर्ट सौंपी जिसमें बताया गया कि मप्र के 7,53,581 श्रमिकों सहित देशभर में 1,14,30,968 प्रवासी लॉकडाउन के दौरान अपने घरों को लौटे थे। उनके रोजगार के लिए व्यवस्था की जा रही है, ताकि वे अपने मूल स्थान पर ही अच्छी आय प्राप्त कर सकें। वहीं सेवानिवृत्त सांख्यिकी और आर्थिक सेवा अधिकारियों और शिक्षाविदों की एक टीम द्वारा किए गए अध्ययन से यह तथ्य सामने आया है कि गांव में मनमाफिक काम नहीं मिलने के कारण करीब 70 फीसदी प्रवासी श्रमिक गांव से लौट गए हैं।

पिछले साल लॉकडाउन के बाद देश के विभिन्न क्षेत्रों से मप्र लौटे किसानों को उनके गांव पर ही रोजगार मुहैया कराने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मनरेगा के तहत हर प्रवासी श्रमिक को रोजगार देने का निर्देश अधिकारियों को दिया। इसके बाद पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने मनरेगा में रोजगार देने के लिए गांवों में विकास कार्य शुरू करवा दिया। लेकिन कुछ माह बाद काम करने के बाद श्रमिकों को फिर से शहर आकर्षित करने लगा और वे गांव छोड़ चले। सेवानिवृत्त सांख्यिकी और आर्थिक सेवा अधिकारियों और शिक्षाविदों की टीम की रिपोर्ट के अनुसार मप्र के 7,53,581 प्रवासी श्रमिकों में से करीब सवा पांच लाख गांव से वापस चले गए हैं। गांव छोड़ने वाले श्रमिकों का कहना है कि उनकी 85 फीसदी आय घट गई, इसलिए शहर आना पड़ा है।

देश में एक बार फिर से कोरोना का संक्रमण विकराल रूप धारण करता जा रहा है। कोविड-19 महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए फिर से महाराष्ट्र समेत कई जगहों पर लॉकडाउन लगाया जाने लगा है। ऐसे में श्रमिकों को एक बार फिर से पलायन का डर सताने लगा है। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के प्रतिकूल असर को पूरे देश और दुनिया ने झेला लेकिन भारत के संदर्भ में प्रवासी मजदूरों की स्थितियां काफी अलग रही हैं। 8 फरवरी 2021 को केंद्र सरकार ने लोकसभा में बताया कि एक करोड़ 14 लाख 30 हजार 968 प्रवासी लॉकडाउन के दौरान अपने घरों को लौटे थे। इनमें से सबसे ज्यादा 32,49,638 प्रवासी उप्र में लौटे तो दूसरे नंबर पर बिहार रहा जहां 15,00,612 प्रवासी शहरों से घर को लौटे, तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल में 13,84,693 प्रवासी और चौथे नंबर पर मप्र में 7,53,581 प्रवासी मजदूर और कामगार शहरों से अपने गांवों को लौटे हैं। हजारों हजार मजदूर पैदल, ट्रक, साइकिल, रिक्शा और दूसरे साधनों से भूखे प्यासे और खाली जेब अपने घरों को लौटे थे। हालात बदलने पर इनमें से कुछ तो घर चलाने के लिए वापस लौट गए लेकिन एक बड़ी संख्या उनकी भी जो वापस नहीं गई। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संतोष गंगवार ने प्रवासियों को उनके आसपास काम देने के एक सवाल के जवाब में लोकसभा में बताया कि ग्रामीण प्रवासी कामगारों के कौशल के आधार पर रोजगारपारिता बढ़ाने के लिए स्किल मैपिंग कराई जा रही है। ताकि वो अपने घरों के पास रहकर काम कर सकें। इस अभियान में 50 हजार करोड़ रुपए के संसाधनों के साथ ही 6 राज्यों के 116 जिलों में काम देने के लिए प्रयास जारी हैं। पहले ही इस अभियान में 50,78,68,671 कार्य दिवस सृजित किए जा चुके हैं।

चिंता की बात यह है कि सालों से शहर की आबोहवा में घुल-मिल गए श्रमिकों का गांव में मन नहीं लगा। गांवों में रोजगार नहीं मिलने और कमाई घटने से प्रवासी मजदूर शहर की ओर रुख कर रहे हैं। सेवानिवृत्त सांख्यिकी और आर्थिक सेवा अधिकारियों और शिक्षाविदों के सर्वे से यह जानकारी मिली है। सर्वे से पता चला है कि नियमित वेतन या मजदूरी पाने वाले प्रवासी मजदूरों का गांव में मन ही नहीं लग रहा है। वहीं, गैर-कृषि क्षेत्र में सामयिक मजदूर सबसे कम प्रभावित थे। सर्वे के अनुसार, शहरों से पलायन करने के चलते मप्र में प्रवासी मजदूरों की आय 85 फीसदी कम हो गई। इसलिए मजदूर पलायन को मजबूर हैं।

● **प्रवीण कुमार**

दिशा भ्रम का शिकार कांग्रेस

राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है कि 'आदमी कमजोर पहले होता है पराजय उसकी बाद में होती है।' उन्होंने यह बात भारत के गुलाम होने के संदर्भ में लिखी थी लेकिन वह कांग्रेस पर खरी उतरती है। हार कमजोरी और दिशा भ्रम कांग्रेस का प्रारब्ध बन गया है।

बहुत पुरानी कहावत है-'पिता पर पूत, जात पर घोड़ा। नहीं ज्यादा, तो थोड़ा-थोड़ा।' बात अगर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की हो तो ये थोड़ा-थोड़ा ज्यादा-ज्यादा हो जाता है। जवाहर लाल नेहरू और इंदिरा गांधी के पूरे राजनीतिक जीवन में विचारों और दिशा को लेकर कभी कोई दुविधा नहीं रही। दिशा भ्रम की प्रवृत्ति पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी में थी। राहुल गांधी को शायद यह विरासत में मिली है। अपनी राजनीतिक नासमझी से उन्होंने इसे कई गुना बड़ा कर लिया है। नतीजा यह है कि राजीव गांधी की तुलना में नुकसान भी ज्यादा उठा रहे हैं। राजीव गांधी ने शाहबानो पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटकर और फिर अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास कराकर हिंदू-मुसलमान, दोनों को एक साथ खुश करने की कोशिश की और दोनों को नाराज कर लिया था। बोफोर्स पर भी उनकी इसी दुविधा ने उन्हें मिस्टर क्लीन से गली-गली में शोर है... के नारे तक पहुंचा दिया, फिर भी एक अंतर यह है कि राहुल गांधी दो वर्गों को अलग-अलग समय पर खुश करने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि वे राजनीति करने के बजाय कंप्यूटर पर गेम खेल रहे हैं।

सार्वजनिक जीवन में लोगों की याद्दाश्त आमतौर पर कमजोर होती है, लेकिन उतनी नहीं जितनी राहुल समझते हैं। चुनाव जब ऐसे राज्य में हो रहा हो, जहां मुस्लिम आबादी के वोट निर्णायक न हों तो वह जनेऊधारी ब्राह्मण और शिवभक्त हो जाते हैं। मंदिर-मंदिर घूमने लगते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद से उनकी शिवभक्ति सुषुप्तावस्था में चली गई है। नेता अमूमन दो तरह के होते हैं। एक जो धारा के साथ चलते हैं और दूसरे जो लाभ-हानि की चिंता किए बिना धारा के विपरीत चलने का साहस दिखाते हैं। जो धारा के विपरीत चलते हैं, वे ऐसा किसी बड़े उद्देश्य यानी समाज या देश के वृहत्तर हित के लिए करते हैं। राहुल गांधी क्या करते हैं और क्यों करते हैं, यह आप खुद तय कीजिए। मैं सिर्फ कुछ तथ्य आपके सामने रखूंगा। कांग्रेस में कौन किस पद पर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।

कांग्रेस में राहुल ही सब कुछ हैं। कुछ व्यापारी अपना सारा धंधा किसी और के नाम से करते हैं, जिससे फंसने की नौबत आए तो वे बचे रहें। दशकों पहले देवकांत बरुआ कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। उन्होंने नारा लगाया था कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। साल 1977 में इंदिरा गांधी सत्ता से बाहर हो गईं। जनता पार्टी ने आपातकाल की ज्यादतियों की जांच के लिए शाह कमीशन बनाया। कमीशन के सामने इंदिरा गांधी के खिलाफ गवाही देने वालों में देवकांत बरुआ भी थे। तो निष्ठा बड़ी चंचल होती है और माया की तरह ठगिनी भी। समय के साथ बदलती रहती है। राहुल गांधी के लिए कोई नहीं कहता कि राहुल ही कांग्रेस हैं और कांग्रेस ही राहुल, क्योंकि सबको मालूम है कि यही सच है। अब यह बताने की तो जरूरत है नहीं कि सूरज पूरब से उगता है।

साल 2014 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की ऐतिहासिक हार के बाद एंटनी कमेटी बनी। उसने अपनी रिपोर्ट में बहुत सी बातें कहीं, जो परिवार और उनके दरबारियों के अलावा किसी को पता नहीं, लेकिन एक बात बाहर निकल आई कि कांग्रेस की छवि हिंदू विरोधी और मुस्लिमपरस्त पार्टी की बन गई है। इस चुनाव में पहली बार भाजपा को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत मिला। तबसे देश की राजनीति वाम से दक्षिणमार्गी हो गई है। तीन-चार साल उस रिपोर्ट पर सोने के बाद कांग्रेस यानी राहुल गांधी ने तय किया कि धारा के साथ बहना ठीक है। वह शिवभक्त हो गए। देश में मंदिर दर्शन नाकाफी लगा तो कैलाश-मानसरोवर की यात्रा कर आए। फिर पता नहीं क्या हुआ कि धीरे-धीरे शिवभक्ति उन्हें निरर्थक लगने लगी। कोई शंका रही भी हो तो 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजे ने खत्म कर दी। ऐसी शिवभक्ति किस काम की जो अमेठी तक हरा दे।

लोकसभा चुनाव में ही केरल के वायनाड में मुस्लिम मतों ने उन्हें लोकसभा में पहुंचा दिया। अब शायद उसका कर्ज उतार रहे हैं। वायनाड में उनका चुनाव एक तरह इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने लड़ा। वैसे लीग से कांग्रेस का पुराना नाता है। शायद उन्हें लगा इतने से बात नहीं बनेगी। सो असम में इत्र व्यापारी बदरुद्दीन अजमल की ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट से गठबंधन कर लिया। असम के दिवंगत कांग्रेस नेता और 15 साल मुख्यमंत्री रहे तरुण गोगोई ने अपने जीते जी ऐसा नहीं होने दिया, पर राहुल गांधी को कौन रोके? उन्हें रोकने का मतलब कांग्रेस को रोकना है। तो सब चुप, पर राहुल इससे भी संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने बंगाल में फुरफुरा शरीफ दरगाह के मौलवी की नई नवेली पार्टी इंडियन सेक्युलर फ्रंट से गठबंधन कर

नई दीर्घकालीन रणनीति

वर्तमान में पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों ने एक बात साफ तौर पर जाहिर की है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक रणनीति तैयार करने के मामले में अपने विरोधियों के मुकाबले दो कदम आगे रहती है। अमेरिका और रूस के चुनावों में विदेशी हस्तक्षेप द्वारा चुनाव प्रभावित करने की बात आरोपों में सामने आई थी, लेकिन राज्यों के विधानसभा चुनावों में विदेशी घटनाओं और विदेश नीति का इस्तेमाल किया जा सकता है, यह बात इस चुनाव में दिख भी रही है। पूर्व में भाजपा के बागी नेता जसवंत सिंह के पक्ष में सिंध के एक प्रसिद्ध धार्मिक नेता फतवा जारी कर चुके हैं जिसके अनुयायी राजस्थान में भी बड़ी संख्या में हैं। इस बार मतुआ समुदाय के मामले में यह इस्तेमाल दूसरे छोर से होता दिखा है। दरअसल भारतीय उपमहाद्वीप के सभी देशों (कृत्रिम राजनीतिक निर्मित) की नियति एक-दूसरे से काफी हद तक जुड़ी हुई है।

लिया। गठबंधन तो सीपीएम ने भी किया है, पर उसका एक मकसद है। उसे ममता को हराना है। राहुल किसे हराना चाहते हैं? ममता को या भाजपा को?

अब आप जरा मौजूदा राजनीतिक माहौल पर नजर डालिए। बंगाल में मुसलमानों की सबसे बड़ी हितैषी ममता बनर्जी चुनावी सभा के मंच से चंडी पाठ कर रही हैं और अपने को ब्राह्मण बता रही हैं। उधर तमिलनाडु में धर्म को न मानने वाली पार्टी द्रमुक के मुखिया एमके स्टालिन पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि द्रमुक हिंदू विरोधी नहीं है और उनकी पत्नी हिंदू रीति-रिवाजों का पालन करती हैं। तमिलनाडु का कोई ऐसा मंदिर नहीं है जिसका दर्शन उनकी पत्नी ने न किया हो। स्टालिन के 90 फीसदी कार्यकर्ता हिंदू हैं और वे विभूति लगाते हैं। क्या आपने करुणानिधि को कभी ऐसा बयान देते हुए सुना था? यह तो दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी धारा के विपरीत खड़े हैं, पर किसका हित साधने के लिए? समाज और देश का हित तो उनका लक्ष्य नहीं दिखता। क्या पार्टी का हित सधेगा? राहुल की हालत फिल्म 'बहू बेगम' में साहिर लुधियानवी के गीत की तरह है-'निकले थे कहां जाने के लिए, पहुंचेंगे कहां, मालूम नहीं। अब अपने भटकते कदमों को, मंजिल का निशां मालूम नहीं।' राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने 'संस्कृति के चार अध्याय' में लिखा है कि 'आदमी कमजोर पहले होता है, पराजय उसकी बाद में होती है।' हालांकि उन्होंने यह बात भारत के गुलाम होने के संदर्भ में लिखी थी, लेकिन वह कांग्रेस पर खरी उतरती है। हार, कमजोरी और दिशा भ्रम कांग्रेस का प्रारब्ध बन गया है।

भारत केवल भौगोलिक दृष्टि से एक विशाल देश नहीं है, अपितु सांस्कृतिक विरासत की दृष्टि से भी वह अपार विविधता को अपने भीतर समेटे है। एक ओर खानपान, बोली, मजहब एवं धार्मिक मान्यताओं की यह विविधता इस देश को सांस्कृतिक रूप से समृद्ध तथा खूबसूरत बनाती है तो दूसरी ओर यही विविधता इस देश की राजनीति को जटिल और पेचीदा भी बनाती है। वैसे पिछले कुछ वर्षों में देश की राजनीति की दिशा में धीरे-धीरे किंतु स्पष्ट बदलाव देखने को मिल रहा है। तुष्टीकरण की राजनीति को 'सबका साथ सबका विकास' और वोटबैंक की राजनीति को 'विकास की राजनीति' चुनौती दे रही है। यही कारण है कि वर्तमान में देश के कई राज्यों में जारी विधानसभा चुनाव परिणाम देश की राजनीति की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।

आजादी के बाद देश के सामने कांग्रेस और कम्युनिस्ट के अलावा राष्ट्रीय स्तर पर कोई और विकल्प नहीं था। धीरे-धीरे क्षेत्रीय दल बनने लगे जो अपने-अपने क्षेत्रों में मजबूत होते गए। लेकिन ये दल क्षेत्रीय ही बने रहे, अपने-अपने क्षेत्रों से आगे बढ़कर राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस का विकल्प बनने में कामयाब नहीं हो पाए। इसका दूसरा पहलू यह भी रहा कि समय के साथ ये दल अपने-अपने क्षेत्रों में कांग्रेस का मजबूत विकल्प बनने में अवश्य कामयाब हो गए। आज स्थिति यह है कि विधानसभा चुनावों में कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी इन क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ते हुए अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है।

कांग्रेस में नेताओं की कोई सुनने वाला नहीं

भारतीय राजनीति की त्रासदी और विडंबना दोनों है कि लंबे समय तक किसी पार्टी में काम करने वाले नेता अगर पार्टी के हित का ध्यान रखते हुए कुछ ऐसे प्रश्न उठाते हैं जो तात्कालिक नेतृत्व के थोड़ा भी विरुद्ध जाए तो उसे पार्टी विरोधी, विरोधी पार्टियों के इशारे पर काम करने वाला, विश्वासघाती और ना जाने क्या-क्या करार दिया जाता है। कांग्रेस के अंदर नेताओं के जिस तबके को जी-23 नाम दिया गया है उनमें ऐसे कौन है जिनकी पहचान एक कट्टर कांग्रेसी की नहीं रही है? किंतु गुलाम नबी आजाद के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। उन्हें पार्टी से निकालने की मांग की जा रही है। कहा जा रहा है कि वे भाजपा में जाने वाले हैं। अलग-अलग राज्यों में दूसरे नेताओं के खिलाफ भी पार्टी का एक समूह, जो 10 जनपथ यानी सोनिया गांधी परिवार के प्रति निष्ठा रखता है उसका रवैया लगभग ऐसा ही है। राज्यसभा में पार्टी के उप नेता आनंद शर्मा ने पीरजादा अब्बास सिद्दीकी जैसे सांप्रदायिक व्यक्ति और उनके संगठन इंडियन पीपुल्स फ्रंट के साथ गठबंधन को पार्टी के मूल सिद्धांतों के विपरीत क्या बताया उन पर भी हमले शुरू हो गए। अधीर रंजन चौधरी ने उन पर जिस तरह का जवाबी हमला किया, उनका उपहास उड़ाया, उसे यहां दोहराने की आवश्यकता नहीं। कायदे से जब ऐसे वरिष्ठ नेताओं ने चुनाव, संगठन में बदलाव, स्थाई अध्यक्ष आदि की मांग पत्र लिखकर सार्वजनिक तौर पर की तो उसे सकारात्मक दृष्टिकोण से लिया जाना चाहिए था। कार्यकारी अध्यक्ष का दायित्व था कि कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक बुलाकर संगठन चुनाव, महाधिवेशन आदि की तिथि तय करते।

वहीं आम चुनावों में कांग्रेस की स्थिति का आंकलन इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि वह लगातार दो बार से अपने इतने प्रतिनिधियों को भी लोकसभा में नहीं पहुंचा पा रही कि सदन को नेता प्रतिपक्ष दे पाए। उसे चुनौती मिल रही है एक ऐसी पार्टी से जो अपनी उत्पत्ति के समय से ही तथाकथित सेक्युलर सोच वाले दलों के लिए अछूत बनी रही। वर्ष 1980 में अपनी स्थापना, वर्ष 1984 के आम चुनावों में मात्र दो सीटों पर विजय, और फिर 1999 में एक वोट से सरकार गिरने से लेकर 2019 के लोकसभा चुनावों में 303 सीटों तक का सफर तय करने में भाजपा ने जितना लंबा सफर तय किया है उससे कहीं अधिक लंबी रेखा अन्य दलों के लिए खींच दी है।

कांग्रेस की दशा देखकर उसके कट्टर समर्थक भी निसंदेह हताश हो रहे होंगे। पार्टी के लिए चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभा चुनाव कितने महत्वपूर्ण हैं यह बताने की आवश्यकता नहीं। आपने गौर किया या नहीं, केंद्रीय नेताओं में केवल राहुल गांधी तमिलनाडु से पुडुचेरी और केरल तक के चुनाव प्रचार में दिख रहे हैं। प्रियंका वाड्रा भी असम में दिखी हैं। दूसरी ओर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के रूप में पहचान रखने वाले कई चेहरे एक साथ जम्मू में एक मंच पर दिखे। उसके बाद अन्य कार्यक्रमों में या सोशल मीडिया से हमें उनके विचार सुनने को मिल रहा है। जिस समय संपूर्ण पार्टी को एकजुट होकर, जान-प्राण लगाकर करो या मरो की भावना से विधानसभा चुनाव अभियान चलाना चाहिए था उस समय इस तरह के परिदृश्य कांग्रेस के भविष्य को लेकर निराशा ही बढ़ाएगा।

● **रजनीकांत पारे**

किसी राजनीतिक दल को जड़ से मजबूती के साथ खड़ा करने में उसके कैडर की भूमिका बहुत बड़ी होती है। भाजपा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अनुषांगिक संगठन हैं। ऐसे में उस पर आरएसएस का प्रभाव होना लाजिमी है। भाजपा को कैडर बेस राजनीतिक पार्टी कहा जाता है। यहां शीर्ष नेतृत्व से लेकर बूथ लेवल के कार्यकर्ता के बीच कनेक्शन देखने को मिल जाएगा। यहां परिवार आधारित वंशवाद नहीं है, मोदी जैसा सामान्य कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन सकता है। यही कारण है कि भाजपा आज देश की सबसे बड़ी पार्टी बनी है।

सियासी भविष्य की पटकथा

देश के चार बड़े राज्यों पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम व केरल और एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के बीच भाजपा में 6 अप्रैल को अपना 41वां स्थापना दिवस मनाया। भाजपा की स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करते हुए एकजुटता का संदेश भी दिया। साथ ही भविष्य की सियासी पटकथा भी समझाई। यह इस बात का संकेत है कि भाजपा आने वाले समय में नई रणनीति के साथ सियासत करेगी। पिछले चार दशक में भाजपा ने लोकसभा में 2 सीटों से 303 सीटों का लंबा सफर तय किया है। अटल-आडवाणी से लेकर मोदी-शाह की जोड़ी तक, इस पार्टी ने हर दशक में नई उपलब्धि हासिल की है। राम मंदिर आंदोलन, कश्मीर से लेकर प्रखर हिंदुत्व तक, कई मुद्दों ने पार्टी के लिए ऑक्सीजन का काम किया। भाजपा को आगे बढ़ाने में जितनी मेहनत उसके कार्यकर्ताओं और नेताओं ने की, उतनी ही बड़ी भूमिका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भी रही है। खासकर राहुल गांधी और मनमोहन सिंह का योगदान भाजपा कभी नहीं भुला पाएगी, क्योंकि इन दोनों नेताओं की वजह से ही नरेंद्र मोदी जैसे नेतृत्व को उभरने का मौका मिला और वो राष्ट्रीय स्तर पर छा गए। आज 18 करोड़ सदस्य संख्या के साथ भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन चुकी है। इसके सदस्यों की संख्या से दुनिया के सिर्फ 8 देशों की आबादी ही ज्यादा है।

चार दशक पहले साल 1980 में स्थापित हुई भाजपा ने आजादी से पहले स्थापित हुई कांग्रेस को सियासी गलियारे में बहुत पीछे धकेल दिया है। 'कांग्रेस मुक्त भारत' के नारे के साथ सत्ता में आई मोदी सरकार ने कांग्रेस का सबसे ज्यादा नुकसान किया है। लेकिन भाजपा को यहां तक लाने में कांग्रेस की भी बहुत बड़ी भूमिका रही है। पिछले सात दशक तक हिंदुस्तान पर राज करने वाली एक पार्टी आज अपना अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। जवाहर लाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के नाम पर चलने वाला ये राजनीतिक दल आज एक करिश्माई नेतृत्व के लिए तरस रहा है। इसी का फायदा भाजपा को मिला। मोदी और शाह की जोड़ी ने संगठन से लेकर सरकार तक मजबूती से सकारात्मक दिशा में काम किया। इसका परिणाम हमारे सामने है। आज अपने 41वें स्थापना दिवस पर भाजपा दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल और लोकतंत्र के मंदिर संसद में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में मौजूद है।

भारतीय राजनीति में करिश्माई नेतृत्व और व्यक्तित्व की भूमिका हमेशा से रही है। राजनीतिक दल किसी भी स्तर का हो, लेकिन उसकी विजय का आधार उसके नेतृत्व के

भाजपा का चार दशक का सफर

भाजपा की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी इसके पहले अध्यक्ष बने। 1984 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी की हत्या की वजह से कांग्रेस के पक्ष में सहानुभूति की लहर थी, इसलिए भाजपा को सिर्फ 2 सीटों पर जीत हासिल हो सकी। साल 1989 में बोफोर्स मुद्दा गरम हुआ, तो इसका फायदा भाजपा को मिला। उस वक्त हुए चुनाव में भाजपा को 85 सीटें मिली थीं। इसी साल पार्टी ने राम जन्मभूमि आंदोलन को समर्थन दिया। लालकृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से राम रथयात्रा शुरू कर दी। बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के आदेश पर आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद आंदोलन ने ऐसा जोर पकड़ा कि साल 1991 में भाजपा की सीटें बढ़कर 120 हो गईं। साल 1993 में उप्र, दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल और मप्र में पार्टी के प्रति जनसमर्थन बढ़ा तो वोट भी बढ़े। साल 1995 में आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, बिहार, ओडिशा, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी कमल खिला।

सामाजिक रुतबे से तय होता रहा है। आजादी के बाद कांग्रेस लंबे समय तक सत्ता में रही, उसका सबसे बड़ा कारण था नेहरू की लोकप्रियता। देश में उनके प्रति अपार श्रद्धा थी, जिसकी वजह से कांग्रेस लगातार बहुमत प्राप्त करती रही। उनके निधन के बाद कांग्रेस की बागडोर उनकी बेटी इंदिरा गांधी के पास आई। उन्होंने भी नेहरू की तरह पार्टी को संभाला। इंदिरा को आयरन लेडी कहा जाता था। पूरे देश में उनका प्रभाव था। उनकी मौत के बाद राजीव गांधी एक स्तर तक कांग्रेस का करिश्मा बनाए रखने में कामयाब रहे, लेकिन उनके निधन के बाद कांग्रेस में कोई करिश्माई नेता नहीं बचा। इधर, भाजपा में अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी जैसे नेताओं का तेजी से उदय हो रहा था। उनका प्रभाव और प्रभुत्व पार्टी में ही नहीं पूरे देश में बढ़ रहा था।

राम मंदिर आंदोलन की वजह से भाजपा को बहुत फायदा हुआ। उसके नेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। कई राज्यों और बाद में केंद्र में सरकार बनाने का अवसर मिला। साल 2010 के बाद नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री होते हुए भी देशभर में चर्चा का केंद्र थे। वहीं, कांग्रेस सोनिया और राहुल गांधी के भरोसे आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। लेकिन साल 2014 में मोदी ने अपने करिश्माई व्यक्तित्व से पूरे देश का मनमोह लिया। उधर, राहुल गांधी को पार्ट टाइम पॉलिटिशियन कहा जाता है। उनकी राजनीतिक अनिच्छा का कांग्रेस को जबरदस्त नुकसान हुआ है। पूर्व राष्ट्रपति दिवंगत प्रणब मुखर्जी ने अपनी किताब 'द प्रेसिडेंशियल ईयर्स' में लिखा है, 'कांग्रेस अपने करिश्माई नेतृत्व के खत्म होने की पहचान करने में विफल रही है। पंडित नेहरू जैसे कद्दावर नेताओं ने यह सुनिश्चित किया था कि भारत अपने अस्तित्व को कायम रखे और एक मजबूत एवं स्थिर राष्ट्र के तौर पर विकसित हो। दुखद है कि अब ऐसे अद्भुत नेता नहीं हैं।'

बिना किसी विचारधारा के राजनीति नहीं हो सकती। भारत में करीब हर राजनीतिक दल किसी न किसी विचारधारा से जुड़ा है। कुछ तटस्थ दल भी हैं, लेकिन उनका भी झुकाव देखा जाता है। राजनीतिक विचारधारा किसी सामाजिक व्यवस्था के लिए राजनीतिक या सांस्कृतिक ब्लूप्रिंट प्रदान करती हैं। इसके आधार पर ही कोई राजनीतिक दल काम करता है। हिंदुस्तान में तीन राजनीतिक विचारधाराएं प्रचलित हैं। लेफ्ट, सेंटर और राइट। इसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जैसे राजनीतिक दल लेफ्ट, भाजपा राइट और कांग्रेस सेंटर मानी जाती है। लेकिन पिछले एक दशक से कांग्रेस गांधी और नेहरू की विचारधारा से दूर होती जा रही है। वहीं भाजपा ने अपनी दक्षिणपंथी विचारधारा को मजबूती से अपनाए रखा है। इस वजह से उसकी विचारधारा के लोग पार्टी से लगातार जुड़ते गए हैं। भाजपा को वैचारिक रूप से मजबूत करने का काम आरएसएस ने बखूबी किया है। वहीं कांग्रेस में विचारधारा तो छोड़िए फिलहाल 'विचार' भी नजर नहीं आता।

किसी भी देश के विकास के लिए अच्छी और मजबूत पॉलिसी का होना बहुत जरूरी है। व्यापार, कृषि या उद्योग कोई भी क्षेत्र बिना परफेक्ट पॉलिसी के उन्नति नहीं कर सकता। लेकिन यूपीए सरकार 'पॉलिसी पैरालिसिस' की शिकार हो गई थी। अपने 10 साल के कार्यकाल के दौरान मनमोहन सिंह जैसे अर्थशास्त्री के प्रधानमंत्री रहते हुए भी देश की आर्थिक विकास की दर कम हो गई। बेरोजगारी तेजी से बढ़ने लगी। इस पॉलिसी पैरालिसिस का परिणाम यह हुआ कि देश के युवाओं को रोजगार के अवसर नहीं मिले। इस वजह से लोग मनमोहन सरकार से नाराज हो गए। रही सही कसर उनके एक बयान के बाद निकल गई, जिसमें मनमोहन सिंह ने राष्ट्रीय विकास परिषद् में दिए अपने भाषण में कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। भाजपा ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई और बहुसंख्यकों के बीच इन मुद्दों को कैश कर लिया। गुजरात में मोदी ने जो विकास का मॉडल खड़ा किया था, उसे पूरे देश में प्रचारित और प्रसारित करके लोगों को सुनहरे भविष्य के सपने दिखाए गए।

भारत में भ्रष्टाचार का मुद्दा हमेशा राजनीति के केंद्र में रहा है। कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार के दोनों कार्यकाल में जमकर भ्रष्टाचार हुआ। इतने बड़े-बड़े घोटाले हुए कि पूरा देश हिल गया। ऑयल फॉर फूड, सत्यम घोटाला, आईपीएल घपला, 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, आदर्श घोटाला, इसरो घोटाला, कोयला घोटाला, एनएचआरएम घपला और अगस्ता वेस्टलैंड घपला सबसे चर्चित केस रहे हैं। इनमें 2जी, कॉमनवेल्थ और कोयला घोटालों में शामिल रकम इतनी बड़ी है, जिसमें कई देशों की पूरी अर्थव्यवस्था समाहित हो सकती है। एक अनुमान के अनुसार मनमोहन सरकार के मंत्रियों पर करीब 1.86 लाख करोड़ की हेराफेरी का आरोप लगा था। आए दिन नए-नए घोटालों के सामने आने से लोग त्रस्त हो गए थे। मोदी की अगुवाई में एनडीए ने भ्रष्टाचार मुक्त भारत और शासन का सपना दिखाया, तो लोग उनकी ओर आकर्षित हुए। विकल्प भी कोई नहीं था। ऐसे में भ्रष्टाचार मुक्त देश के वादे के साथ मोदी सरकार सत्ता में आ गई।

● इंद्र कुमार

ऐसे भाजपा ने रच दिया इतिहास

साल 1996 में भाजपा ने 161 सीटें जीतीं। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, लेकिन बहुमत नहीं होने से 13 दिन में ही सरकार गिर गई। साल 1998 के मध्यावधि चुनावों में भाजपा ने कई राजनीतिक दलों के साथ एनडीए गठबंधन बनाया। इस गठबंधन की बदौलत भाजपा सत्ता में आ गई। लेकिन साल 1999 में जयललिता की पार्टी ने समर्थन वापस ले लिया और सरकार गिर गई। इसके बाद हुए चुनाव में एनडीए ने 303 सीटें हासिल करके स्पष्ट बहुमत पा लिया। 183 सीटों के साथ भाजपा गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी थी। साल 2004 और 2009 के चुनाव में भाजपा की स्थिति खराब हो गई। सीटें घटकर 116 रह गईं। लेकिन साल 2014 में भाजपा ने एक बार फिर अंगड़ाई ली। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी को 282 सीटें हासिल हुईं। वहीं, 336 सीटों के साथ एनडीए को बहुमत मिला। 26 मई 2014 को मोदी देश के 15वें प्रधानमंत्री बने। साल 2019 के चुनाव में 303 सीटों पर जीत हासिल कर भाजपा ने इतिहास रच दिया।

नक्सलियों की बर्बरता

बीजापुर के टेकलगुड़ा में फोर्स और नक्सलियों के बीच 3 अप्रैल को हुई मुठभेड़ की पटकथा 12 दिन पहले 22 मार्च को ही लिखी जा चुकी थी। वारदात में 22 जवान शहीद हुए पर नक्सलियों को भी बहुत नुकसान हुआ है। वह दो ट्रैक्टर में साथियों के शव लेकर भागे हैं। वारदात के करीब दो हफ्ते पहले 20 या 22 मार्च को फोर्स को सूचना मिली कि टेक्टिकल काउंटर अफेंसिव कैंपेन (टीसीओसी) के तहत नक्सलियों की बटालियन नंबर वन तुम्मापाड़-जावागट्टा गांव की तरफ सक्रिय है। नक्सलियों का एक दस्ता रोड ओपनिंग पर निकलने वाले जवानों को एंबुश में फंसाने के लिए रेकी कर रहा है। यह इलाका दुर्दांत नक्सल कमांडर हिड़मा का है। लिहाजा अधिकारी सतर्क हो गए। तुरंत जवानों के एक दस्ते को इस इलाके में भेजा गया। जवान इलाके में घुसे तो सूचना सही निकली। उन्होंने नक्सलियों का पीछा किया। नक्सली कम संख्या में थे और फोर्स को देखकर भाग खड़े हुए। यहीं से टेकलगुड़ा मुठभेड़ की इबारत तय हो चुकी थी।

फोर्स 23 साल बाद बासागुड़ा से जगरगुंडा तक 40 किमी सड़क को दोबारा खोल रही है। इसी सड़क पर तर्रेम में नक्सलियों ने 8 अक्टूबर 1998 को पहला आईईडी ब्लास्ट किया था। मेटाडोर वाहन पर तर्रेम से बासागुड़ा जा रहे 16 जवान इस ब्लास्ट में शहीद हो गए थे। इस घटना के बाद यह स्टेट हाईवे दो दशक तक बंद रहा। अब फोर्स ने तर्रेम में दोबारा थाना व कैंप खोल दिया है। इसके आगे सुकमा जिले के सिलगेर में कैंप खोला जा रहा है। सड़क को दोबारा बनाया जा रहा है। 25 या 26 मार्च को नक्सलियों ने सिलगेर के पास निर्माणाधीन पुल का काम कर रहे मजदूरों को पीटकर भगा दिया। फिर इस सड़क को जगह-जगह से काट दिया।

हिड़मा की बटालियन से लोहा लेने के लिए सुकमा व बीजापुर जिले के अलग-अलग कैंपों से जंगलवार में दक्ष डीआरजी जवानों की टीम तैयार की गई। इनमें ऐसे लड़के शामिल थे जो नक्सलियों का एंबुश तोड़ने के एक्सपर्ट माने जाते हैं। इनके साथ बस्तर बटालियन, कोबरा, सीआरपीएफ व एसटीएफ के ऐसे जवानों का चयन किया गया जिनमें नक्सल युद्धनीति की समझ हो। इन सबको मिलाकर करीब दो हजार जवानों को उस इलाके में भेजा गया, जहां नक्सली मौजूद थे। दो अप्रैल की रात में अलग-अलग टुकड़ियों में जवान रवाना हुए।

जंगलवार में दक्ष जवान कई बार जंगल में नक्सलियों को धूल चटा चुके थे। उन्हें नक्सलियों की हर चाल की पूरी जानकारी थी। वह अपने वायरलेस सेट में नक्सलियों की बात भी सुन रहे थे। उन्हें पता था कि नक्सली घिर चुके हैं और घबराए हुए हैं। जवान सुबह करीब 11.30 बजे तिमापुर गांव की उस पहाड़ी के पास पहुंचे जहां उन्हें मालूम हो चुका था कि नक्सली हैं। पहाड़ी को घेरकर जवानों ने नक्सलियों पर फायरिंग झोंक दी। इधर नक्सली अंडर बैरल ग्रेनेड लांचर (यूबीजीएल) व देशी रॉकेट लांचर से ताबड़तोड़ गोले दागने लगे। वह तीर बम चला रहे थे। बम के हमले से जवानों के मोर्चे बिखर गए। इसके बाद भी जवानों ने हौंसला नहीं खोया। उन्होंने मोर्चा बदला और फिर हमला किया। जवाबी कार्रवाई में नक्सलियों के पांव उखड़ गए और वे पहाड़ी से गायब हो गए। जब गोलीबारी बंद हो गई तो जवानों ने देखा उनके दो साथी शहीद हो गए हैं और सात घायल हैं। अब जवानों को अपने साथियों की चिंता होने लगी।

मुठभेड़ के बाद कुछ जवान अपने साथियों की तीमारदारी में लगे रहे। मौके पर जो प्राथमिक उपचार किया जा सकता था उन्होंने किया। घटनास्थल की सर्चिंग करने वाली टीम को इस बीच एक महिला नक्सली का शव मिल गया था। पास ही उसकी इंसास रायफल पड़ी थी। इलाके की सर्चिंग करते हुए जवानों का दस्ता अब टेकलगुडम गांव तक पहुंच गया था। दोपहर के करीब 3 बज रहे थे। जवान वापस चलने को तैयार थे। उन्हें पता था कि खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है। उन्होंने अपने घायल साथियों को दल के बीच में सुरक्षित कर लिया। हालांकि जवान दूसरे हमले के लिए भी तैयार थे पर टेकलगुड़ा गांव की ओर से अचानक नक्सली दोबारा पूरी तैयारी कर लौट आए।

टेकलगुड़ा गांव से उत्तर की ओर 200 मीटर दूर स्थित तालाब के पास नक्सलियों ने स्नाइपर गनर्स को तैनात कर दिया था। जवान खुले में थे। स्नाइपर्स ने निशाना लगाकर 8 जवानों की हत्या कर दी। गांव के बीच मोर्चा संभाल रहे एसआई दीपक भारद्वाज ने जैसे ही जवाबी हमला करने की कोशिश की यूबीजीएल का एक गोला उन पर आकर गिरा। कुछ नक्सली गांव में भी छिपे थे। जवानों को अचानक हुए इस दूसरे हमले में संभलने का वक्त नहीं मिला। गांव के भीतर 6 जवान शहीद हो गए। अब शहीदों की संख्या 16 हो चुकी थी। हेलीकॉप्टर से अब भी संपर्क नहीं हो पा रहा था। इसके बाद कुछ इसलिए शहीद हुए क्योंकि वह अपने घायल साथियों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ शवों को निकालने में जुटे थे इसलिए शहीद हो गए। शहीदों की संख्या बढ़ने लगी। नक्सलियों ने अपॉर्चुनिटी एंबुश (मौके के मुताबिक तुरंत घेर लेना) लगाया था। इस एंबुश से निकलने का मौका जवानों को नहीं मिला, फायरिंग इतनी हैवी थी कि वह नया मोर्चा भी नहीं बना पा रहे थे।

● **रायपुर से टीपी सिंह**

9,300 से अधिक लोगों की बर्बरता से हत्याएं

गृह मंत्रालय के अनुसार 9,300 से अधिक जिन नागरिकों की नक्सलियों ने हत्या की, वे बर्बरता और क्रूरता में माओ और पोल पोट की ही विचाररेखा पर की गई हत्याएं हैं। नक्सली 12-13 साल के बच्चों को जबर्दस्ती अपने गुट में शामिल कर लेते हैं। जो माता-पिता अपने बच्चों के अपहरण के खिलाफ आवाज उठाते हैं, उन्हें उनके बच्चों के सामने ही तड़पा-तड़पा कर मारने के उदाहरण नक्सली प्रस्तुत करते रहते हैं, ताकि उस क्षेत्र में दहशत फैल जाए। छत्तीसगढ़ में इस प्रकार के लगभग 12 छात्रावास चल रहे हैं, जिनमें नक्सलियों द्वारा मार डाले गए लोगों के अनाथ बच्चे सरकारी सहायता से पोषित किए जा रहे हैं। क्रूरता की हद यह है कि नक्सली जिन महिलाओं को अपने गिरोहों में भर्ती करते हैं, उनका दैहिक शोषण भी करते हैं। नक्सली हिंसा के शिकार सैकड़ों बच्चे आज तक राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान आकृष्ट नहीं कर पाए हैं।

'महा' संकट

महाराष्ट्र में मची अव्यवस्था ने वहां भाजपा में नई जान फूंक दी है। 2014 से ही स्वर्णिम दौर से गुजर रही पार्टी को हर बार नया संकट खड़ा होने पर तमाशे का आनंद लेने और विपक्ष की हैसियत से शोर मचाने के अलावा शायद ही कुछ करना पड़ा हो। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार इतनी अनुभवहीन दिखती है कि भाजपा न सिर्फ महाराष्ट्र में, बल्कि जहां भी वह सत्ता से बाहर है, वहां के मतदाताओं को उत्साह से बता सकती है कि कैसे केवल भाजपा सरकार ही सुशासन और विकास सुनिश्चित कर सकती है। गृहमंत्री अनिल देशमुख पर भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद हाईकोर्ट के हस्तक्षेप पर देशमुख ने इस्तीफा दे दिया है। इससे एमवीए सरकार पर महासंकट आ गया है।

नवंबर 2019 में सत्ता में आने के बाद से ही ठाकरे की अगुवाई वाली सरकार को एक के बाद एक शर्मिंदगी वाले संकटों का सामना करना पड़ रहा है, और इस प्रक्रिया में मुख्यमंत्री और उनकी टीम की प्रशासनिक अनुभवहीनता, शासन संबंधी अपरिपक्वता और अक्षम्य स्तर की अक्षमता उजागर हो रही है। इसी के साथ शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के कथित 'अपवित्र गठबंधन' के हाथों कुर्सी की दौड़ में पराजित रही भाजपा का उत्साह सातवें आसमान पर है। नंबर गेम में आगे रहने और सरकार बनाने से भी अधिक आनंददायक होता है आपको सत्ता से दूर रखने में कामयाब पूर्व में सहयोगी रहे प्रतिद्वंद्वी को लगातार शर्मिंदगी झेलते और सत्ता के नाकाबिल नजर आते देखना। क्योंकि ऐसा होने पर ही आप मतदाताओं को आश्वस्त कर सकते हैं कि केवल आप ही चुने जाने लायक हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह, जिन्हें सत्ता छिनने का ज्यादा अनुभव नहीं है, को उद्धव की समस्याओं- केंद्र से निरंतर तकरार, सहयोगी दलों से जुड़ी मुसीबतें, सुशांत सिंह राजपूत मामले से संबंधित शर्मिंदगी, कैबिनेट मंत्री संजय राठौड़ का इस्तीफा, कोविड-19 महामारी का लचर प्रबंधन और हालिया मुकेश अंबानी के घर के सामने बम (सचिन वाजे-परमबीर सिंह) प्रकरण और गृहमंत्री के इस्तीफे की वजह से अप्रत्याशित (या शायद अपेक्षित) आनंद मिल रहा होगा।

देशमुख के खिलाफ आरोप सही हो या नहीं, और परमबीर सिंह के पत्र के समय और उद्देश्य को लेकर सवाल भले ही अनुत्तरित हों, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि एमवीए सरकार मुश्किलों में घिरी हुई है। उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ा। शिवसेना-एनसीपी-कांग्रेस गठबंधन वैचारिक और राजनीतिक दोनों ही दृष्टियों से एक अस्वाभाविक समझौता है। लेकिन, शायद यह एकमात्र तरीका था जो ठाकरे के वारिस को महाराष्ट्र का शीर्ष पद दिला सकता था। हालांकि, अब यही लगता है कि पद हासिल करना उद्धव के लिए एक कठिन लड़ाई की शुरुआत भर थी। उन्होंने अपनी अनुभवहीनता और मामलों पर नियंत्रण न रख पाने के कारण अपनी सरकार की बहुत किरकिरी कराई है।

उदाहरण के लिए, कोविड के मोर्चे पर भारी कुप्रबंधन को लें। महामारी की पहली लहर के दौरान महाराष्ट्र की स्थिति सर्वाधिक चिंताजनक थी, और मुंबई एक हॉटस्पॉट बनकर उभरा था। एक समय तो महामारी का प्रबंधन इतना लचर था कि मरीज को आईसीयू बेड के लिए अस्पतालों के चक्कर काटने में अहम समय गंवाना पड़ रहा था। दूसरी लहर में, महाराष्ट्र एक बार फिर कोविड के केंद्र के रूप में उभरा है। ताजा स्थिति की बात करें, तो भारत के सक्रिय कोविड मामलों का 63 प्रतिशत अकेले महाराष्ट्र में है, जो कि किसी भी पैमाने से एक बड़ी संख्या है। टीकाकरण के मोर्चे पर भी, केंद्र को टीकाकरण की धीमी गति और 'अप्रयुक्त' टीकों के कारण राज्य की खिंचाई करनी पड़ी है। उद्धव की सरकार जहां कोविड की स्थिति पर काबू पाने में अभी तक पूरी तरह नाकाम रही है, वहीं इसने कुछ प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर केंद्र के साथ तकरार करने में भी महत्वपूर्ण समय बर्बाद किया है। सरकार के लिए शर्मिंदगी की वजह बनने में उद्धव के मंत्री भी पीछे नहीं रहे हैं। पहले एक टिकटॉक स्टार की मौत के मामले में वन मंत्री संजय राठौड़ का नाम उछला और अब गृहमंत्री अनिल देशमुख भी आरोपों के बाद अपने इस्तीफे को लेकर सुर्खियों में हैं। कानून और व्यवस्था के मोर्चे पर तो एमवीए सरकार और भी बुरी दिखी है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले के कुप्रबंधन से लेकर टीवी पत्रकार अर्णब गोस्वामी को जान-बूझकर परेशान करने, मुख्यमंत्री की आलोचना करने वाले भाजपा समर्थकों के खिलाफ मामले दायर किए जाने और एंटीलिया बम कांड तक, अनेक मामलों में इस सरकार की किरकिरी हुई है।

● **बिन्दु माथुर**

महाराष्ट्र का मामला इतना अहम क्यों है

भाजपा के लिए, शासन के मोर्चे पर शिवसेना सरकार की नाकामी मिसाल देने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में लगभग अपराजेय दिखती पार्टी महाराष्ट्र में दोबारा जीतने को लेकर काफी आश्वस्त थी। लेकिन 2019 के विधानसभा चुनावों में वो केवल 105 सीटें ही जीत पाई, जो कि 288 सदस्यीय सदन में बहुमत के आंकड़े से बहुत दूर था। इस परिणाम ने विभिन्न कारणों से पार्टी की छवि को बुरी तरह से प्रभावित किया। पहले तो, इसने मोदी-शाह की जोड़ी की सीमाओं को उजागर करने का काम किया, विशेष रूप से इसलिए कि महाराष्ट्र पार्टी के लिए असम या त्रिपुरा जैसा कोई नया इलाका नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा राज्य है जहां भाजपा के वैचारिक संरक्षक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) का मुख्यालय है। दूसरे, शिवसेना के साथ छोड़ प्रतिद्वंद्वी खेमे में जाने से, भाजपा एक स्वाभाविक सहयोगी दल तक के लिए अछूत की तरह दिखने लगी, और उसके प्रतिद्वंद्वी अधिक आकर्षक नजर आने लगे। और तीसरी एवं सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि पराजय ने पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए, जो कि भाजपा के युवा, प्रगतिशील और अगली पीढ़ी के प्रतिनिधि के रूप में देखे जा रहे थे। भाजपा के लिए, रिकॉर्ड खराब दिख रहा था। इसके सभी मुख्यमंत्री (राजस्थान से लेकर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक) स्पष्ट जीत दिलाने में नाकाम रहे थे। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर भी सत्ता गंवाते-गंवाते बचे थे।

मुख्तार अंसारी कितने लाचार

उप्र का सबसे बड़ा बाहुबली मुख्तार अंसारी इन दिनों लाचार नजर आ रहा है। आज उनके खिलाफ 40 से ज्यादा केस दर्ज हैं। वह पिछले 13 सालों से जेल में बंद हैं। जितने केस हैं, उससे कहीं ज्यादा दुश्मन हैं। हालात ये है कि जेल भी उनके लिए सुरक्षित नहीं है। यही वजह है कि लगातार उनकी जेल बदली जाती रही है। फिलहाल उसे पंजाब से लाकर उप्र की बांदा जेल में रखा गया है। लेकिन अब भी उसको डर है कि अगर उप्र में उसका एनकाउंटर हो जाएगा। उधर, उप्र सरकार एक-एक करके उसके सहयोगियों को ठिकाने लगा रही है। उसके तथा उसके सहयोगियों के रसूख पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। इससे मुख्तार काफी डरा हुआ है।

साल 1988 में मंडी परिषद् की ठेकेदारी को लेकर मुख्तार अंसारी ने सचिदानंद राय की हत्या कर दी। इसके बाद मुख्तार का नाम बड़े क्राइम में पुलिस फाइल में दर्ज कर लिया गया। इस दौरान त्रिभुवन सिंह के कांस्टेबल भाई राजेंद्र सिंह की हत्या वाराणसी में कर दी गई, इसमें मुख्तार का नाम एक बार फिर सामने आया। साल 1991 में चंदौली में मुख्तार अंसारी को गिरफ्तार किया गया, लेकिन रास्ते में दो पुलिसवालों को गोली मार फरार हो गए। रेलवे के ठेके, शराब के ठेके, कोयले के काले कारोबार को शहर से बाहर रहकर संचालित करना शुरू कर दिया। साल 1996 में मुख्तार का नाम एक बार फिर सुर्खियों में आया, जब एएसपी उदय शंकर पर जानलेवा हमला हुआ। साल 1997 में पूर्वांचल के सबसे बड़े कोयला व्यापारी रुंगटा के अपहरण के बाद मुख्तार अंसारी का नाम जरायम की दुनिया में गहरे काले अक्षरों में दर्ज हो गया। उस वक्त तक माफिया डॉन बृजेश सिंह का उदय हो चुका था। माफिया डॉन बृजेश सिंह की गैरहाजिरी में बाहुबली मुख्तार अंसारी का वर्चस्व बढ़ता गया। इधर, **आपराधिक छवि** मजबूत होने के साथ ही अंसारी परिवार की राजनीतिक छवि कमजोर होने लगी। इसका नतीजा यह हुआ कि साल 2002 में हुए विधानसभा चुनाव में कृष्णानंद राय से मुख्तार के भाई अफजल अंसारी हार गए। इसमें कृष्णानंद राय को बृजेश सिंह का भी समर्थन मिला था। इस चुनाव के बाद गाजीपुर और मऊ में हिंदू-मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण होने लगा। आए दिन सांप्रदायिक झगड़े और दंगे होने लगे। इसी बीच मुख्तार अंसारी ने शार्प शूटर मुन्ना बजरंगी की मदद से विधायक कृष्णानंद राय की उनके पांच साथियों के साथ हत्या करा दी। इसके बाद हर तरफ दंगे भड़क उठे।

साल 2005 में जब मऊ में दंगे हुए, तो मुख्तार अंसारी खुली जीप में घूम रहे थे। आरोप है कि धर्म विशेष के लोगों के खिलाफ जमकर अत्याचार किया गया था। कहा गया कि दंगा भड़काने का काम मुख्तार अंसारी ने ही किया। इन दंगों के बाद साल 2006 में उप्र के वर्तमान मुख्यमंत्री और तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ ने मुख्तार अंसारी को खुली चुनौती दी कि मऊ आकर पीड़ितों को इंसाफ दिलाएंगे, लेकिन उन्हें मऊ में दोहरीघाट में रोक दिया गया था। इसके तीन साल बाद 2008 में योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ जा रहे थे, तब उनके काफिले पर हमला कर दिया गया। उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ हुई थी। उपद्रवियों ने आगजनी की भी कोशिश की थी। उस वक्त योगी आदित्यनाथ बाल-बाल बचे थे। हमले से बचने के बाद योगी ने खुले शब्दों में मुख्तार अंसारी को चेतावनी दी थी। इसके बाद जब से योगी सूबे के मुख्यमंत्री बने हैं, तभी से उन्होंने उप्र में अपराधियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।

उप्र में योगी आदित्यनाथ के सत्ता में आने के बाद मुख्तार अंसारी जैसे अपराधियों के बुरे दिन शुरू हो गए। मुख्तार के खिलाफ लगातार पुलिस कार्रवाई की जा रही है। उसके अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिए गए। कई बेनामी संपत्तियां जब्त कर ली गईं। परिवार के लोगों पर भी कानूनी शिकंजा कसा जाने लगा। मुख्तार को पंजाब से उप्र लाने की पहले भी कई बार कोशिशें की जा चुकी थी। बताया जा रहा है कि बीते 2 सालों में उप्र पुलिस की टीम 8 बार मुख्तार को लेने पंजाब आ चुकी थी। लेकिन हर बार सेहत, सुरक्षा और कोरोना का कारण बताकर पंजाब पुलिस उसे सौंपने से इनकार करती रही। आखिरकार गत दिनों उसे उप्र की बांदा जेल में शिफ्ट कर दिया गया। वैसे असली बात ये है कि कानपुर के विकास दुबे एनकाउंटर के बाद ही मुख्तार अंसारी डरा हुआ था। यहां तक कि पंजाब सरकार को पत्र लिखकर आशंका जताई थी कि जैसे विकास दुबे की जीप पलट गई और जान चली गई, ऐसे मेरी भी जा सकती है।

जरायम की दुनिया में मुख्तार अंसारी का नाम बदनाम है, लेकिन उनके परिवार का इतिहास उतना ही गौरवशाली बताया जाता है। खानदानी रसूख की जो तारीख इस घराने की है वैसी शायद ही पूर्वांचल के किसी खानदान की हो। बाहुबली मुख्तार अंसारी के दादा डॉ. मुख्तार अहमद अंसारी स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान 1926-27 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उनकी याद में दिल्ली की एक रोड का नाम उनके नाम पर है। दादा की तरह नाना भी नामचीन हस्तियों में से एक थे। कम ही लोग जानते हैं कि महावीर चक्र विजेता ब्रिगेडियर उस्मान मुख्तार के नाना थे। उन्होंने 1947 की जंग में न सिर्फ भारतीय सेना की तरफ से नवशेरा की लड़ाई लड़ी बल्कि हिंदुस्तान को जीत भी दिलाई। हालांकि वो खुद इस जंग में हिंदुस्तान के लिए शहीद हो गए थे। मुख्तार के पिता सुब्हानउल्लाह अंसारी कम्यूनिस्ट नेता थे, इतना ही नहीं पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी मुख्तार के रिश्ते में चाचा लगते हैं।

● **लखनऊ से मधु आलोक निगम**

2 साल से पंजाब की जेल में बंद था मुख्तार

8 जनवरी 2019 को पंजाब के मोहाली के एक बड़े बिल्डर की शिकायत पर पंजाब पुलिस ने 10 करोड़ की फिरौती मांगने का केस मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज किया। 12 जनवरी को प्रोडक्शन वारंट हासिल करने के लिए पुलिस कोर्ट पहुंची। 21 जनवरी 2019 को पुलिस मुख्तार को प्रोडक्शन वारंट पर उप्र से मोहाली ले आई। 22 जनवरी 2019 को अंसारी को मोहाली कोर्ट में पेश किया। एक दिन का रिमांड मिला। 24 जनवरी को न्यायिक हिरासत में अंसारी को रोपड़ जेल भेज दिया गया। तबसे वो पंजाब की जेल में बंद था। उप्र पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद उसे पंजाब पुलिस लाने नहीं दे रही थी। यहां तक सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी हाल ही में आदेश दिया था कि मुख्तार जल्द से जल्द उप्र वापस भेजा जाए, लेकिन सियासती दांवपेच के कारण 2 सालों तक उप्र पुलिस लाचार रही। आखिरकार गत दिनों पूर्व ही पंजाब की जेल से उप्र की बांदा जेल में अंसारी को लाया गया।

सियासी क्षत्रपों का कड़ा इम्तिहान

राजस्थान में 3 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव का घमासान अपने चरम पर है, सुजानगढ़, सहाड़ा और राजसमंद में उपचुनाव के लिए 17 अप्रैल को मतदान होना है। प्रदेश में बढ़ती गर्मी के तापमान के साथ-साथ सियासत का पारा भी चढ़ने लगा है। कांग्रेस और भाजपा ने तीनों सीटों की जिम्मेदारी अपने मंझे हुए सिपहसालारों को दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा ने अपनी खास टीम उपचुनाव के प्रबंधन के लिए उतारी है, तो भाजपा प्रदेशाध्यक्ष और केंद्रीय नेतृत्व ने भी अनुभवी टीम पर भरोसा जताया है। वैसे दोनों ही पार्टियों ने प्रत्याशियों के तौर पर परिवारजनों पर भरोसा जताया है। लेकिन चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी अपने खास सेनापतियों को दी है। वहीं चुनाव को त्रिकोणीय बनाने के लिए हनुमान बेनीवाल की आरएलपी ने भी ताल ठोक रखी है। बेनीवाल उपचुनाव में अपनी उपस्थित दर्ज करवाने के लिए पूरा दम लगा रहे हैं, वैसे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मैदान में कूद जाने से अब दोनों प्रमुख पार्टियां सचेत हो गई हैं। आरएलपी ने सीधे तौर पर भाजपा के लिए परेशानी खड़ी कर दी है।

सबसे पहले बात करते हैं सहाड़ा विधानसभा सीट की, कांग्रेस ने यहां चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा को जीत दिलाने का जिम्मा सौंपा है। रघु शर्मा प्रदेश में पार्टी का ब्राह्मण चेहरा तो हैं ही, साथ ही भीलवाड़ा के प्रभारी मंत्री भी हैं। रघु शर्मा चुनाव की घोषणा के साथ ही सहाड़ा में डेरा डाले हुए हैं। पिछले 14 विधानसभा चुनावों में से 9 बार ये सीट कांग्रेस ने जीती है। कांग्रेस विधायक कैलाश त्रिवेदी के निधन के बाद, कांग्रेस ने उनकी पत्नी गायत्री देवी को यहां से उम्मीदवार बनाया है। वैसे कांग्रेस यहां सहानुभूति की लहर पर सवार है, लेकिन पार्टी के लिए ये सीट रीटेन करना चुनौती है। और इस चुनौती को रघु शर्मा ने उठाया है।

बात करें भाजपा की तो सहाड़ा में चुनावी रथ की कमान मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग के हाथ में है। प्रचार के बीच जोगेश्वर गर्ग का एक ऑडियो धूम मचा रहा है। भाजपा ने यहां रणनीति के तहत बागी लादूलाल पितलिया का नामांकन वापस दिलवा दिया है। जोगेश्वर गर्ग के साथ यहां सांसद सुभाष बहेड़िया, सीपी जोशी, विधायक विट्ठल शंकर भी कैंप किए हुए हैं। कांग्रेस की परंपरागत सीट को छीनना भाजपा के लिए चुनौती है। कांग्रेस के गढ़ सहाड़ा को भेदने के लिए भाजपा ने इस जाट बहुल सीट पर रतनलाल जाट को उम्मीदवार बनाकर उतारा है। जाट उम्मीदवार को टिकट देने की वजह जातिगत समीकरणों के साथ-साथ क्षेत्र में रतनलाल जाट की पकड़ भी है। वे मेवाड़ जाट महासभा के अध्यक्ष हैं और पार्टी में प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य भी हैं।

बात करें राजसमंद सीट की तो, राजसमंद सीट की जिम्मेदारी कांग्रेस ने मंत्री उदयलाल आंजना को सौंपी है। साथ ही पार्टी ने मंत्री प्रमोद जैन भाया को भी रण में उतारा है। लंबे समय से ये सीट भाजपा के हाथ में रही है। तेजतर्रार भाजपा नेता पूर्व मंत्री किरण माहेश्वरी राजसमंद से विधायक थीं। कांग्रेस ने इस सीट से तनसुख बोहरा को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं, भाजपा ने राजसमंद सीट पर जीत की जिम्मेदारी नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया को दी है। कटारिया के साथ सांसद दीया कुमारी, मदन दिलावर और विधायक सुरेंद्र राठौड़ भी मैदान में डटे हैं। राजपूत चेहरे के रूप में दीया कुमारी यहां भाजपा का ट्रंप कार्ड हैं।

पूर्व मंत्री किरण माहेश्वरी के बेटी दीप्ती माहेश्वरी को भाजपा ने मैदान में उतारा है, दीया कुमारी के लिए ये सीट जिताना प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। वहीं किरण माहेश्वरी द्वारा कराए विकास कार्यों की नाव पर ही सवार है। भाजपा नेताओं को लगता है कि 20 साल से विधानसभा क्षेत्र में इतने विकास कार्य हुए हैं कि मतदाता दूसरी पार्टी के बारे में नहीं सोचेगा। इसके अलावा असमय दिवंगत हुईं माहेश्वरी के कारण पार्टी को सहानुभूति वोट भी मिलेंगे।

इधर, सुजानगढ़ में पार्टी ने जीत की जिम्मेदारी कांग्रेस ने प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी को दी है। पूर्व मंत्री मास्टर भंवर लाल मेघवाल इस सीट से विधायक थे। और कांग्रेस ने उनके पुत्र मनोज मेघवाल को मैदान में उतारा है। अब तक इस सीट पर हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस 6 बार, भाजपा 4 बार, निर्दलीय 3 बार, जनसंघ और जनता पार्टी ने एक-एक बार बाजी मारी है। कांग्रेस के लिए यह सीट प्रतिष्ठा का सवाल बनी हुई है। इधर भाजपा ने तेज तर्रार नेता और उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को जीत दिलाने की जिम्मेदारी दी है। साथ ही रिजर्व सीट होने के चलते केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल को भी पार्टी ने अहम जिम्मेदारी सौंपी है। भाजपा ने पूर्व विधायक खेमाराम मेघवाल पर दांव खेला है।

दूसरी तरफ, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मुखिया हनुमान बेनीवाल ने तीनों सीटों के उपचुनाव को दिलचस्प के साथ त्रिकोणीय भी बना दिया है, केंद्रीय कृषि कानूनों को लेकर एनडीए से नाता तोड़ने वाले आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल भाजपा को झटका देने के लिए पुख्ता तैयारी करके मैदान में उतरे हैं। बेनीवाल ने तीनों सीटों पर जातिगत समीकरण बैठाते हुए ऐसे मोहरे फिट किए हैं जिससे भाजपा के साथ कांग्रेस भी अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करने को मजबूर हो गई है।

● **जयपुर से आर.के. बिन्नानी**

प्रत्याशी एक ही जाति के

राजसमंद सीट पर कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियों के प्रत्याशी एक ही जाति से हैं। यहां बेनीवाल ने गुर्जर समुदाय से प्रहलाद खटाना को टिकट देकर भाजपा की उम्मीद को झटका देने की कोशिश की। दरअसल राजसमंद में करीब 15 हजार गुर्जर मतदाता हैं। सचिन पायलट की कथित नाराजगी के चलते भाजपा को उम्मीद है कि गुर्जर मतदाता इस बार कांग्रेस के बजाय आरएलपी को वोट देंगे। सुजानगढ़ सीट पर भी बेनीवाल ने सीताराम नायक को आरएलपी से मैदान में उतारकर भाजपा के वोट बैंक में सेंधमारी की तैयारी की है। यहां नायक समुदाय भाजपा का परंपरागत वोट बैंक माना जाता है। सहाड़ा विधानसभा सीट के लिए 2018 के चुनाव में रूपलाल जाट भाजपा के उम्मीदवार थे लेकिन वे तब चुनाव हार गए थे। रूपलाल इस बार भी भाजपा से दावेदार थे लेकिन पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया। इस मौके का फायदा उठाने के लिए हनुमान बेनीवाल ने यहां रूपलाल के भाई बद्रीलाल जाट को अपनी आरएलपी से सहाड़ा से मैदान में उतार दिया।

बदले-बदले से नीतीश कुमार

हर एक व्यक्ति का व्यक्तित्व और चरित्र समय और काल के अनुसार बदलता रहता है। जवानी में समाजवादी, क्रांतिकारी और ढलती उम्र में रूढ़िवादी तथा निजीकरण व्यवस्था का समर्थक हो जाता है। प्रारंभ में प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं और ढलती उम्र में अधिनायकवाद के समर्थक बन जाते हैं। इस तरह से सामान्य व्यक्तियों में बदलाव होता है। नौकरशाहों तथा राजनीतिज्ञों में भी ये देखा जा सकता है। अनेक भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय प्रशासनिक पुलिस सेवा के पदाधिकारियों में तथा राजनीतिज्ञों में साफ-साफ यह दिखाई देता है। प्रारंभ में आईएएस-आईपीएस अपनी छवि के प्रति बहुत ही सजग दिखते हैं लेकिन 15-20 साल बाद उन्हीं पदाधिकारियों में पहले वाला जोश, उत्साह, छवि और निष्ठा के प्रति सजगता कम दिखती है।

नीतीश कुमार संसदीय प्रणाली को मजबूत करने के प्रति अपनी निष्ठा, प्रतिबद्धता और जुनून के लिए प्रसिद्ध थे, 1990 से 1995 और बिहार विधानसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य के रूप में जो निष्ठा, उत्साह संसदीय प्रणाली को मजबूत करने में दिखता था उसमें 16वीं विधानसभा में बिहार विधानसभा के रूप में गिरावट दिखाई दे रही है। नीतीश कुमार 'लवकुश' के पहले महासम्मेलन, जो सतीश कुमार द्वारा आयोजित था, उसमें भाग लेने जाने में संकोच कर रहे थे। जातीय सभा में जाना उन्हें पसंद नहीं था परंतु भारी मन से पटना के गांधी मैदान में आयोजित सम्मेलन में भाग लिया। लेकिन व्यक्ति ने नाम लिए बगैर जातीय 'लवकुश' को वोट के लिए मजबूत करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा को जनता दल (यू) के संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया। दोनों एक दूसरे की आलोचना की सीमा को पार कर टिप्पणी करते रहते थे। आज दोनों एक-दूसरे के प्रशंसक और सत्ता के लिए सहयोगी बन गए हैं।

जब नीतीश कुमार अटलजी के मंत्रिमंडल में रेल मंत्री थे तब रेल दुर्घटना की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हुए नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र दे दिया था। लेकिन समय और काल के बदलाव में नैतिकता को ताक पर रखते हुए मुजफ्फरपुर बालिका आवास गृह में 34 लड़कियों के साथ बलात्कार की घटना सामने आने पर, भागलपुर के सृजन घोटाला की घटना के बावजूद मुख्यमंत्री पद पर बने रहते हैं। उनकी नैतिकता समय और काल के अनुसार बदल गई। पहली बार 8 दिनों के लिए बिहार का मुख्यमंत्री बनने पर तत्कालीन सांसद प्रभुनाथ सिंह एवं अन्य लोग येनकेन प्रकारेण बहुमत जुटाने पर लगे हुए थे। नीति सिद्धांत सब ताक पर था। उस समय नीतीश ने चुपचाप रहकर सभी गतिविधियों का मौन समर्थन कर दिया था। अंत्वोगत्वा बहुमत के अभाव में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था और उसी समय नीतीश कुमार की नैतिकता पर प्रश्नचिन्ह लग गया था। पुन: नैतिकता के आधार पर 2014 में मुख्यमंत्री के पद से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। चूंकि लोकसभा चुनाव में इनकी पार्टी को पराजय मिल गई थी और जीतनराम मांझी को जो घर जा रहे थे तब रास्ते से लौटवाकर मुख्यमंत्री बिहार के रूप में मनोनीत कर शपथ दिलवा दी थी। फिर उसी नीतीश कुमार ने मांझी को मुख्यमंत्री के पद से हटाने के लिए जो भी कार्रवाई की, सब जगजाहिर है।

2020 के 17वें बिहार विधानसभा चुनाव में जद(यू) केवल 43 सीटों पर ही सुरक्षित रह सकी। अब नैतिकता कहां चली गई। भारतीय जनता पार्टी के साथ 'बड़े भाई के साथ छोटे भाई' का शीतयुद्ध जारी है। देखें कब, कहां और किस मौके पर उजागर होता है। आजकल मुख्यमंत्री जल्दी-जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। घटना पिछले विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद भाषण देते समय की है जब प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के टिप्पणी पर वे आग बबूला हो गए। शायद जो लोग भी नीतीश कुमार को जानते हैं, उन्होंने इससे पहले शायद ही उन्हें गुस्से में देखा होगा। आजकल 'चिढ़ा-चिढ़ा' व्यवहार दिखता है। सत्ताधारी दल के सदस्य सदन आसन की ओर उंगली दिखा रहे हैं। अध्यक्ष को 'व्याकुल' कहा जाता है। क्या संसदीय प्रणाली में आसन को अपमानित करने से सरकार या संसदीय प्रणाली मजबूत होगी। लेकिन यह सब मुख्यमंत्री देख रहे हैं।

पिछले सदन के सत्र में एक माननीय विधायक अपना आवेदन मुख्यमंत्री को देने जाते हैं। आवेदन में क्या लिखा था नहीं मालूम लेकिन गुस्से में आवेदन को किनारे रखते हुए काफी गुस्से भरी नजरों से देखा जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। सदस्य जब वापस लौटने लगे तो एक पदाधिकारी को इंगित कर बात करने को कहा। नीतीश का गुस्सा पहले दिखाई नहीं देता था। उन्हें कभी भी किसी को 'अपशब्द' या 'तुम ताम' कर बात करते नहीं देखा गया था। नीतीश हमेशा छोटा हो या बड़ा सभी के साथ आदरसूचक शब्दों से बात करते थे। उनकी यह आदत अनुकरणीय थी। परंतु कुछ दिनों से इसमें गिरावट आ गई है।

● **विनोद बक्सरी**

अब लोकतांत्रिक नहीं है...

पिछले विधानसभा के सत्र में नीतीश कुमार की बिहार सरकार ने विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 पेश किया है। जिसके बाद बिहार पुलिस को अधिकार होगा कि वह बिना वारंट के किसी के घर की तलाशी ले सकती है। किसी प्रकार के कोई न्यायिक आदेश की जरूरत नहीं होगी। मात्र पुलिस को विश्वास होना चाहिए वह तलाशी लेने के नाम पर कभी भी किसी के घर में घुस सकती है। इस बिल से पुलिस को असीमित अधिकार मिलेगा। व्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी। इस बिल का विपक्ष विरोध कर रहा था जिसे विधानसभा के द्वारा पास कराने के लिए संसदीय इतिहास में पहली बार सदन के अंदर पुलिस को बुलाकर सदस्यों को पीटते हुए बाहर करवाया गया। यही है प्रजातंत्र का संसदीय कारनामा।

PRISM®
CEMENT

प्रिज़्म® चैम्पियन प्लस

ज़िम्मेदारी मज़बूत और टिकाऊ निर्माण की.

Toll free: 1800-3000-1444
Email: cement.customerservice@prismjohnson.in

दूर की सोच®

म्यांमार में लोकतंत्र की तलाश

म्यांमार में लोकतंत्र की सबसे बड़ी उम्मीद आंग सान सू की से कहां चूक हो गई कि वहां की सत्ता पर एक बार फिर सेना का कब्जा हो गया। दशकों के संघर्ष के बाद उन्हें देश की कमान मिली थी। 2015 के चुनाव में जब सू की को जबर्दस्त जीत मिली थी तब लगा था कि म्यांमार के हालात सुधर जाएंगे, लेकिन एक बार फिर म्यांमार सैन्य शासन के हाथों में चला गया है। जाहिर है वहां एक अदद लोकतंत्र की तलाश अब भी जारी है। सैन्य शासन के 5 दशक के बाद मार्च 2016 में म्यांमार में लोकतंत्र बहाल हुआ था। म्यांमार के सांसदों ने आंग सान सू की के करीबी तिन क्यां को देश का पहला असैन्य राष्ट्रपति चुना था। वैसे तो सू की पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने चुनाव में भारी जीत हासिल की थी। दोनों सदनों में उसे बहुमत भी मिले थे। बावजूद इसके म्यांमार में सेना ने भी मजबूत पकड़ बनाए रखी।

गौरतलब है कि साल 1962 में सत्ता को अपने हाथों में लेने वाली वहां की सेना ने म्यांमार के संविधान में एक ऐसा प्रविधान कर दिया कि आंग सान सू की बड़ी जीत हासिल करने के बावजूद राष्ट्रपति बनने से वंचित हो गई थीं। उस प्रविधान के अनुसार जिनके करीबी परिजन विदेशी नागरिक हों वे राष्ट्रपति नहीं बन सकते। मालूम हो कि आंग सान सू की के बेटों के पास विदेशी नागरिकता थी यही उनके राष्ट्रपति बनने की राह में रोड़ा था। हालांकि 2018 में म्यांमार की कमान तिन क्यां की जगह विन मिंट को दे दी गई थी। कुल मिलाकर म्यांमार लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़ चला था, मगर क्या पता था कि कोरोना के बीच वहां के लोकतंत्र को भी तानाशाही नामक वायरस जकड़ लेगा। एक बार फिर म्यांमार की जमीन पर लोकतंत्र बंधक हो जाएगा।

म्यांमार में इस सैन्य तख्तापलट और आंग सान सू की समेत कई शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी पर अमेरिका, इंग्लैंड समेत दुनिया के तमाम छोटे-बड़े देश चिंता जता रहे हैं। अमेरिका ने तो स्पष्ट किया है कि लोकतंत्र को बहाल करने के लिए सही कदम न उठाने पर कार्रवाई करेंगे। संयुक्त राष्ट्र ने भी इस पर चिंता जताई है। सवाल है कि म्यांमार में इस बार राजनीतिक संकट क्यों उत्पन्न हुआ? असल में सेना यह आरोप लगा रही है कि वहां चुनाव परिणामों में धांधली हुई है। मालूम हो कि नवंबर 2020 के चुनाव में वहां संसद के संयुक्त निचले और ऊपरी सदनों में सू की की पार्टी ने 476 सीटों में 396 सीटों पर जीत हासिल कर ली थी। यह जीत सेना को नागवार गुजरी। उसने धांधली का आरोप लगाते हुए लोकतंत्र को बंधक बना लिया।

सेना के पास साल 2008 के सैन्य मसौदा संविधान के अंतर्गत अभी भी कुल सीटों में से 25 फीसदी आरक्षित हैं। इतना ही नहीं कई प्रमुख मंत्री पद भी सेना के लिए आरक्षित हैं। सेना बड़े पैमाने पर धांधली का आरोप लगा तो रही है, पर सुबूत देने में वह असफल है। ऐसे में यह साफ प्रतीत होता है कि उसका इरादा लोकतांत्रिक सत्ता को हड़पने का था। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सेना द्वारा पहले वहां लोकतंत्र पर कब्जा किया गया, फिर उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। अब तक यंगून, मांडले समेत करीब दो दर्जन शहरों और कस्बों में सैकड़ों प्रदर्शनकारी मारे जा चुके हैं। देखा जाए तो पुलिस और सैनिक आक्रामक रवैया अपनाए हुए हैं। हालांकि इन सबके बीच वहां लोकतंत्र की रक्षा और बहाली को लेकर भी बातें सामने आ रही हैं। सैन्य शासन जुंटा के प्रमुख ने कहा है कि वह हर कीमत पर जनता की रक्षा करेंगे और जल्द ही चुनाव कराएंगे, लेकिन इसका समय नहीं बता रहे हैं।

म्यांमार में कभी अंग्रेजों का राज था। साल 1937 से पहले औपनिवेशिक सत्ता ने उसे भारत का ही एक राज्य घोषित कर रखा था। बाद में उसे भारत से अलग कर अपना एक उपनिवेश बना लिया। गौरतलब है कि 1980 के पहले इसका नाम बर्मा था। 4 जनवरी, 1948 को बर्मा ब्रिटिश शासन से मुक्त हुआ और 1962 तक वहां पर लोकतंत्र के तहत सरकारें चुनी जाती रही थीं। मगर 2 मार्च, 1962 को सेना के तत्कालीन जनरल ने चुनी हुई सरकार का तख्तापलट करते हुए सैन्य शासन की स्थापना कर दी। वहां के संविधान को निलंबित कर दिया। सैन्य शासन के उस दौर में मानवाधिकार के उल्लंघन के भी आरोप लगते रहे। वहां सैन्य सरकार को मिलिट्री जुंटा कहा जाता था। फिर लंबे संघर्ष और कई उतार-चढ़ाव के बाद आखिरकार वहां पर लोकतंत्र बहाल हुआ, जिसका श्रेय 3 दशकों से इसके लिए प्रयासरत आंग सान सू की को जाता है। मगर एक हकीकत यह भी है कि जहां लोकतंत्र को हड़पने की स्थिति बनती हो वहां ऐसा बार-बार बनने की संभावना भी रहती है। पाकिस्तान भी इसका बड़ा उदाहरण है।

● **ऋतेन्द्र माथुर**

भारत को चिंतित होना लाजमी

पड़ोसी म्यांमार में सैन्य तख्तापलट होने और शीर्ष नेताओं को हिरासत में लेने के चलते भारत का चिंतित होना लाजमी है। पड़ोसी देशों में सत्ता के लोकतांत्रिक ढंग से हस्तांतरण का भारत हमेशा से समर्थन करता रहा है। जाहिर है कानून के शासन और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विरूद्ध तानाशाही का म्यांमार में होना मानवता के हित में नहीं है। भारत का मानना है कि लोकतंत्र समर्थक शक्तियों को अलोकतांत्रिक ढंग से नहीं कुचला जाना चाहिए। भारत की लगभग 1600 किमी लंबी सीमा म्यांमार से लगती है। भारत को इस सीमा पर अलगाववादियों के हिंसक गतिविधियों का भी सामना करना पड़ता रहा है। इसके अलावा अफगानिस्तान के बाद म्यांमार नशीले पदार्थों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। वहां से पूर्वोत्तर में इनकी बड़ी खेप आना भारत के लिए एक बड़ी समस्या रही है। नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार, विद्रोही गतिविधियों एवं तस्करी की बुराइयों से निपटने के लिए दोनों देशों के बीच 1993 में एक संधि भी हुई थी। भारत-म्यांमार व्यापार संबंध 1970 में हुए एक व्यापार समझौते के बाद प्रगाढ़ हुए हैं। नवंबर 2015 में वहां लोकतंत्र बहाल होने से भारत को एक और लोकतांत्रिक पड़ोसी का मिलना भी तय हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तब वैश्विक फलक पर दिखने लगे थे।

आज देश की महिलाएं आत्मनिर्भरता की राह पर तेजी से आगे बढ़ चुकी हैं जिसमें केंद्र की मोदी सरकार का व्यापक और महत्वपूर्ण योगदान है। यह पहली बार हुआ जब महिलाएं पूर्णकालिक तौर पर रक्षा, वित्त, विदेश और शिक्षा मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण पदों पर सुशोभित हुई हैं।

आत्मनिर्भरता की ओर आधी आबादी

स्वतंत्र भारत की यात्रा में महिलाओं की स्वतंत्रता मात्र कागजों में छपे शब्दों तक ही सीमित रही, चाहे वह संविधान की पुस्तक हो या कानून की। वर्ष 2014 में जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री चुने गए तो उनकी अनेक प्राथमिकताओं में एक महिला सुरक्षा एवं सशक्तीकरण भी था। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि अब योजनाएं मात्र फाइलों में सीमित न रहें, बल्कि धरातल पर समयबद्ध रूप से अमल में भी लाई जाएं।

नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले देश में महिलाओं की स्वतंत्रता महज दिखावा रहा। मोदी युग के शुरू होने के पश्चात ही महिलाएं वास्तव में अपनी स्वतत्रंता को महसूस कर रही हैं और उसे जी सकती हैं। एक महिला जो अशिक्षित है, सामाजिक तौर पर जिसकी पहचान नहीं है, आर्थिक रूप से वह पति या अन्य किसी पर निर्भर है और जिसका हर रोज मानसिक और शारीरिक शोषण हो रहा हो, उसके लिए स्वतंत्रता के क्या मायने हैं? भारतीय सभ्यता में भले ही महिलाओं को देवी का दर्जा दिया गया है, परंतु व्यावहारिक रूप से ऐसा नहीं है।

हमारा समाज पितृसत्तात्मक है अर्थात् पुरुष प्रधान है और लिंग भेद एक कटु सत्य है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत में अब भी कई ऐसी महिलाएं हैं जो गरीबी और अभाव में अपना जीवन बसर कर रही हैं। आजादी के सात दशकों बाद भी अधिकांश महिलाओं को समानता का अधिकार नहीं मिल पाया है। केंद्र और राज्य सरकारों ने महिलाओं के लिए कई योजनाएं शुरू कीं, परंतु उनका प्रभावी अनुपालन संभव नहीं हो पाया। परिणामस्वरूप महिलाओं विशेषकर ग्रामीण इलाकों की महिलाओं के जीवन यापन के स्तर में अपेक्षित सुधार नहीं हो पाया। किसी भी सरकार को देशवासियों के हित में बिना किसी भेदभाव के लोक कल्याण का काम करना चाहिए, पर दुर्भाग्यवश ज्यादातर सरकारों ने महिलाओं के उत्थान हेतु सिर्फ वादे किए। भारत वह देश है, जहां महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित सबसे ज्यादा कानून हैं, पर भारतीय नारी न तो पूर्ण रूप से सुरक्षित है, न ही सशक्त।

पिछली सरकारों की 'चलता है' नीति को 'चलना पड़ेगा' नीति द्वारा प्रतिस्थापित किया गया और इसी नीति ने उन योजनाओं को हर महिला तक पंहुचाने हेतु हर संबंधित व्यक्ति या अधिकारी की जिम्मेदारी तय की। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जन धन योजना, मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, राष्ट्रीय पोषण मिशन, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वच्छ भारत समेत तमाम अन्य योजनाओं को वंचित महिलाओं तक पहुंचाने का काम मोदी सरकार ने किया, जिसकी प्रशंसा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने भी की है। विश्व बैंक ने महिलाओं के उत्थान हेतु इन प्रयासों को भरपूर सराहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन योजनाओं के माध्यम से देश की महिलाओं के विश्वास को जीता है और यही वजह है कि वह कई बार अनेक मंचों से यह कह चुके हैं कि हमारा भविष्य महिलाओं के बेहतर भविष्य पर ही निर्भर करता है।

यह देश में पहली बार हो रहा है जब गांव की एक गरीब महिला जिसे सेनेटरी नैपकिन के बारे में पता तक नहीं था आज जन औषधि केंद्र से बेहद सस्ती दरों पर अपने लिए नैपकिन खरीद पा रही है और स्वयं को कई सारी बीमारियों से बचा रही है। यह पहली बार हो रहा है जब एक कामकाजी महिला मां बनने के बाद 26 सप्ताह की आधिकारिक छुट्टी पर जा सकती है और अपने बच्चे की सही से देखभाल कर सकती है। एक सिंगल मदर को पासपोर्ट बनवाने के लिए अब अपने पति या पिता का नाम लिखना जरूरी नहीं है। किसी भी मुस्लिम महिला को अब तीन तलाक जैसी प्रथा का सामना नहीं करना पड़ रहा है। गावों में हर घर में शौचालय की सुविधा होना एक सपना जैसा था जिसे मोदी सरकार ने साकार किया। एक आम गृहिणी को लकड़ी आधारित पारंपरिक चूल्हे से मुक्ति दिलाते हुए एलपीजी गैस का सिलेंडर मुहैया कराने की पहल मोदी सरकार ने ही की है। महिलाएं अब जीरो बैलेंस पर बैंक में अपना खाता खोल पा रही हैं और तमाम सरकारी स्कीम से जुड़ते हुए प्रत्यक्ष हस्तांतरण के जरिए अपने बैंक अकाउंट में रकम प्राप्त कर रही हैं।

● **ज्योत्सना अनूप यादव**

महत्वपूर्ण पदों पर महिलाएं काबिज

यह पहली बार हुआ जब महिलाएं पूर्णकालिक तौर पर रक्षा, वित्त, विदेश और शिक्षा मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण पदों पर सुशोभित हुई हैं। यह भी पहली बार संभव हुआ है कि सशस्त्र बलों में महिला अधिकारी पुरुषों की भांति फाइटर प्लेन उड़ा सकती हैं और नेवी तथा आर्मी में समान उच्च पदों पर जा सकती हैं। प्रधानमंत्री द्वारा बीते वर्षों स्वतंत्रता दिवस पर दिया गया भाषण भी महिलाओं पर केंद्रित था जिसमें उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में महिलाओं की भूमिका की चर्चा की। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा है कि देश की महिलाओं को सशक्त करने की आवश्यकता है और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि पहले की भांति कोई भी महिला शोषित या वंचित न रहे। कुल मिलाकर निर्विवाद रूप से यह कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं की वास्तविक क्षमता को पहचाना है।

Anu Sales Corporation

We Deal in Pathology & Medical Equipments

Add: Ground Floor, 17/1, Shanti Niketan, Near Chetak Bridge, Bhopal-462023

M. : 9329556524, 9329556530, E-mail : ascbhopal@gmail.com

व्हाट्सएप

रक्षा बेटी नमस्ते। शादी की बधाई। हैप्पी ससुराल गेंदा फूल। तुम्हारी शिकायत कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देने स्वयं तुम्हारे विवाह समारोह में नहीं आया। बेटी जी व्हाट्सएप पर तुम्हारा निमंत्रण पत्र मिला था। एक ही छोटे से कस्बे में होते हुए भी तुम्हें अथवा तुम्हारे परिवार के किसी भी सदस्य को कार्ड घर पर देने आने का समय नहीं मिल पाया। वरना आशीर्वाद देने स्वयं मंडप तक आता। व्हाट्सएप पर प्राप्त कार्ड का उत्तर व्हाट्सएप पर ही शगुन के दो हजार रुपए के नोट पर एक रुपए का सिक्का रखकर फोटो लेकर भेज तो दी ही थी। जिस प्रकार ऑनलाइन कार्ड आया उसी प्रकार शगुन भेजकर आगे के लिए तुम्हें एक सबक सिखाने का प्रयास किया है। चिंता मत करना। नाराज नहीं हूं। जिस नोट की फोटो भेजी है वह नोट सीलबंद लिफाफे में तुम्हारी धरोहर के रूप में सुरक्षित है। जब भी समय निकालकर मिलने आओगी वह लिफाफे की बहुत छोटी सी अमानत तुम्हें मिल जाएगी। प्रतीक्षा रहेगी ही। तुम्हारे सुनोजी एजी पति परमेश्वर को शुभकामना एवम तुम्हें स्नेह प्यार आशीर्वाद। स्नेह सहित- कैलाश अंकल।

- अनाम

संयुक्त परिवार

फोन पर शिकायती लहजे में उमा बोली- 'मां तुम्हारी सलाह पर संयुक्त परिवार से अलग होकर मैं सुखी नही बल्कि ज्यादा ही परेशान हो गई थी। कभी आटा खत्म, तो कभी सब्जी मसाले के अभाव में आए दिन परेशान होकर वापस ही अपनी सासू मां के पास आ गई हूं।'

मंदिर से आकर घर में प्रवेश करते हुए उमा की बातें सुनकर सासू मां ने कहा- 'अच्छा किया जो वापस आ गई' तुझे परेशान देखकर मैंने ही बेटे राकेश को समझाते हुए एक माह के लिए जरूरी आटा, दाल, मसालों के साथ तेरा तथा बेटे का सामान बांधकर किराए के मकान में खुशी-खुशी विदा किया था, ताकि संयुक्त परिवार में सबके सामूहिक सहयोग से काम करने और अकेले रहने में अंतर को महसूस कर सके। सुबह का भुला शाम को लौट आए तो भुला नहीं कहाता बहूं।'

वे आगे बोली- 'तेरे दादा स्वसुर कहा करते थे कि हमारे देश की सनातन संस्कृति की जड़ें संयुक्त परिवारों में है, जहां रहकर ही सबको आपसी स्नेह और सहयोग की समझ आती है।'

उमा एकाकी और संयुक्त परिवार में फर्क समझ चुकी थी।

- लक्ष्मण रामानुज लड़ीवाला

नारी ने भरमाया है

प्रकृति सृष्टि का गूढ़ तत्व है,
समझ न कोई पाया है।
नर क्या समझे, नारायण को,
नारी ने भरमाया है।।
नर, सागर की, गहराई नापे।
मौसम की कठिनाई भी भांपे।
आसमान में उड़ता है नर,
इससे देखो, पर्वत कांपे।
नारी की मुस्कान ने जीता,
प्रकृति की कैसी माया है।
नर क्या समझे, नारायण को,
नारी ने भरमाया है।।
वेद ज्ञान से, भरे पड़े हैं।
कुरान और हदीस लड़े हैं।
नारी प्रेम की चाह में ये नर,
बुद्धिहीन से, पीछे खड़ें हैं।
सिद्धांत गढ़ो, कुछ भी कह लो,
नर नारी का साया है।
नर क्या समझे, नारायण को,
नारी ने भरमाया है।।
उपदेश नहीं, कुछ कर दिखलाओ।
चाहो नहीं, बस प्यार लुटाओ।
सबको मुफ्त की सीख हो देते,
चलकर उन पर, खुद दिखलाओ।
छल, कपट, धोखे में फंसाकर,
गान मिलन का गाया है।
नर क्या समझे, नारायण को,
नारी ने भरमाया है।।

- दिलीप भाटिया

डिस्टेंसिंग फैक्टर में सुपर रोमांच

खेल प्रेमियों और खिलाड़ियों पर भी वैश्विक महामारी कोरोना ने खूब कहर बरपाया। आईपीएल जैसे रोमांचक मुकाबले भी इस महामारी के साये में हो रहे हैं। दर्शक घर में हैं और खिलाड़ी होम ग्राउंड से दूर। ऊपर से कई तरह की बंदिशें। इन सबके बावजूद 52 दिनों तक चौकों-छक्कों की बरसात में खेल प्रेमी सराबोर होने को बेताब हैं। आईपीएल के 14वें सीजन का आगाज हो चुका है। रोमांच से भरपूर यह भारतीय क्रिकेट लीग इस बार फिर कोरोना के साये में हो रही है। आप भले ही इस बार भी मैदान में जाकर मैच का लुत्फ न उठा पाएं, लेकिन घरों में बैठकर चौकों और छक्कों का आनंद ले सकेंगे। आईपीएल में इस बार कई बदलाव नजर आएंगे। अब तक सभी टीमें अपने होम ग्राउंड पर मैच खेलती रही हैं, लेकिन महामारी के कारण इस बार सभी मैच तटस्थ स्थानों पर ही होंगे। यानी सभी टीमें इन स्थलों पर ही रहेंगी और मैच खेलेंगी। कई नए खिलाड़ी भी इस आईपीएल सीजन में आगाज करेंगे। कई टीमों के नए कप्तान नजर आएंगे तो कुछ टीमों के खिलाड़ी भी बदले दिखेंगे। पिछली बार की तरह इस बार भी कोरोना का खतरा लीग पर बरकरार है। जिस तेजी से देश में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, उससे चिंता और बढ़ गई है। मुंबई में आंशिक लॉकडाउन ने स्थिति को और गंभीर कर दिया है। हालांकि, अभी बीसीसीआई आईपीएल कराने को लेकर आश्वस्त है। टूर्नामेंट 9 अप्रैल से 30 मई तक यानी 52 दिन चलेगा।

शुरुआत से पहले ही लीग पर कोरोना का असर दिखने लगा है। 3 टीमों के 4 खिलाड़ी कोरोना पॉजीटिव मिल चुके हैं। इनमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के ओपनर देवदत्त पडिक्कल व डेनियल सैम, दिल्ली कैपिटल्स के अक्षर पटेल और कोलकाता नाइट राइडर्स के नीतीश राणा शामिल हैं। अब तक स्टाफ और खिलाड़ियों को मिलाकर कुल 20 लोग कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं। इनमें मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम के 10 स्टाफ मेंबर और 6 ईवेंट मैनेजर, चेन्नई सुपर किंग्स की कंटेंट टीम का एक सदस्य शामिल है। ऐसे में आईपीएल टीमों की चिंता अपने खिलाड़ियों को महामारी से बचाए रखने की है। लीग में खेलने वाले सभी खिलाड़ी, टीम स्टाफ इस समय बायो बबल में हैं और टूर्नामेंट खत्म होने तक उन्हें बायो बबल में ही रहना होगा। बायो बबल का मतलब यह है कि इसमें रहने वाले लोगों का संपर्क बाहरी दुनिया से पूरी तरह से कट जाता है। बायो बबल में जाने से पहले सभी खिलाड़ी, कोचिंग और सपोर्ट स्टाफ, मैच अधिकारी, होटल स्टाफ का कोरोना टेस्ट कराया जाता है। सभी रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद उन्हें बायो बबल में प्रवेश दिया जाता है। यहां तक कि कोरोना टेस्ट करने वाली मेडिकल टीम को भी इसके बाहर जाने की अनुमति नहीं होती। इस घेरे में वही लोग होते हैं, जो कोरोना टेस्ट से गुजर चुके हैं और पूरी तरह से संक्रमण से दूर हैं। बायो बबल में शामिल किए गए लोगों को सिर्फ मैदान और होटल तक ही रहने की अनुमति है। बबल के अंदर जितने लोग हैं, सिर्फ उनसे ही वह मिल सकते हैं। विशेष परिस्थिति में बाहर जाने वालों को बायो बबल में लौटने से पहले क्वारंटाइन होना पड़ेगा। क्रिकेट में समय-समय पर नियम बदलते रहते हैं। जब से नई टेक्नोलॉजी आई है, ग्राउंड पर मौजूद अंपायरों का काम थोड़ा आसान हो गया है, लेकिन कुछ फैसलों में अब भी फील्ड अंपायर का ही निर्णय अहम होता है और उसे ही तवज्जो दी जाती है। फील्ड अंपायर के किसी निर्णय पर रिव्यू लेने पर उनकी ओर से दिए गए सॉफ्ट सिग्नल को अहमियत दी जाती है, लेकिन आईपीएल के इस सीजन में थर्ड अंपायर अपना निर्णय खुद लेंगे। इसमें मैदान में मौजूद अंपायर के सॉफ्ट निर्णय का कोई असर नहीं पड़ेगा। इस बार शॉर्ट रन पर अंतिम निर्णय भी थर्ड अंपायर का होगा। शॉर्ट रन का फैसला फील्ड अंपायर करते रहे हैं, लेकिन इस बार थर्ड अंपायर फील्ड अंपायर के फैसले को बदल सकेंगे। पिछले सीजन में नो बॉल का फैसला थर्ड अंपायर पर छोड़ दिया गया था।

खिलाड़ियों और कप्तानों को बदलने के लिए मशहूर रही किंग्स इलेवन पंजाब की टीम ने इस बार नाम भी बदल लिया है। टीम अब पंजाब किंग्स के नए नाम के साथ मैदान में उतरेगी। दिल्ली की टीम भी अपना नाम बदल चुकी है। दिल्ली डेयर डेविल्स अब दिल्ली कैपिटल्स है। यही नहीं टीमें अपनी किस्मत बदलने के लिए जर्सियां भी बदलती रहती हैं। इस बार मुंबई इंडियंस नई जर्सी में नजर आएगी। पहले की तरह नीले रंग की इस जर्सी में सुनहरे (गोल्डन) रंगों का ज्यादा इस्तेमाल है। जर्सी में ब्रह्मांड की संचरना के 5 मूल तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का समावेश है और यह फ्रेंचाइजी के मूल्यों को दर्शाता है। टीम प्रवक्ता का कहना है कि मुंबई इंडियंस ने हर साल एक विरासत को आगे बढ़ाया है, जो हमारे मूल मूल्यों और विचारधाराओं पर आधारित है। हमारे 5 आईपीएल खिताब इन मूल्यों के लिए हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

● आशीष नेमा

युवाओं के हाथों टीम की कमान

इस बार आईपीएल में भारतीय टीम के सदस्य ऋषभ पंत और संजू सैमसन अपनी-अपनी टीमों की कप्तानी करते नजर आएंगे। 26 साल के संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स के कप्तान होंगे। वे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्मिथ की जगह लेंगे। 23 साल के ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी करेंगे। वे श्रेयस अय्यर की जगह टीम की अगुवाई करेंगे। श्रेयस कंधे में फ्रैक्चर के कारण आईपीएल से बाहर हो गए हैं। अब देखना यह होगा कि दोनों ही भारतीय युवा खिताब की दौड़ में अपनी टीमों को कहां तक ले जा पाते हैं। इस बार आईपीएल में कई ऐसे खिलाड़ी नजर नहीं आएंगे, जो अब तक लीग की 'जान' रहे हैं। इनमें से कई खिलाड़ियों ने संन्यास ले लिया है और कई चोट के कारण मैच से बाहर हो गए हैं। चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से खेलने वाले ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज शेन वॉटसन और मुंबई इंडियंस की ओर से खेलने वाले श्रीलंका के तेज गेंदबाज लसिथ मलिंगा ने पिछले सीजन में संन्यास लेने की घोषणा की थी। दोनों ही टीमों को इन दिग्गजों की कमी खलेगी। इनके अलावा, ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड, मिचेल मार्श, जोस फिलिप, दक्षिण अफ्रीका के डेल स्टेन और दिल्ली के कप्तान श्रेयस अय्यर आईपीएल नहीं खेलेंगे। श्रेयस और मिचेल मार्श चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर हैं। दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने खुद को इस सीजन के लिए अनुपलब्ध बताया है।

13 साल की उम्र में मॉडलिंग करने लगी थीं 'वांटेड गर्ल' आयशा टाकिया

सलमान खान के साथ फिल्म वांटेड में नजर आईं एक्ट्रेस आयशा टाकिया का जन्म 9 अप्रैल, 1986 को मुंबई में हुआ था। उन्होंने मुंबई के सेंट एंथनी गर्ल्स हाई स्कूल से अपनी स्कूलिंग पूरी की थी। आयशा ने 13 साल की उम्र में ही मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा था। वह विज्ञापन में कॉम्प्लान गर्ल बनकर खासी चर्चित हुई थीं। इसके बाद फाल्गुनी पाठक के म्यूजिक वीडियो मेरी चूनर उड़-उड़ जाए ने उन्हें बॉलीवुड की नजर में ला दिया था।

इन फिल्मों में किया काम... 2004 में आई फिल्म टार्जनः द वंडर कार से आयशा ने डेब्यू किया था। इसके बाद वे शाहिद कपूर के साथ फिल्म दिल मांगे मोर में नजर आई थीं। अभय देओल के साथ उनकी रोमांटिक फिल्म सोचा न था (2004) दर्शकों द्वारा खासी पसंद की गई। 2009 में रिलीज सलमान और आयशा स्टारर फिल्म वांटेड सुपरहिट थी। उनकी आखिरी फिल्म आप के लिए हम 2013 में रिलीज हुई थी।

सर्जरी के कारण आईं सुर्खियों में... आयशा कभी ब्रेस्ट इंप्लांट करवाकर सुर्खियों में आई थीं। इसके बाद उन्होंने चेहरे की सर्जरी करवाकर भी काफी सुर्खियां बटोरी थीं हालांकि आयशा ने सर्जरी की खबरों का खंडन किया था। 2009 में आयशा ने रेस्त्रां ओनर और समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी के बेटे फरहान आजमी से शादी की थी। वेडिंग के बाद उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली थी। आयशा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं।

सूरत की बाढ़ ने छीन लिया था हमारा घरः प्रतीक गांधी

पिछले साल रिलीज हुई वेब सीरीज स्कैम 1992 में निभाए गए हर्षद मेहता के किरदार ने प्रतीक गांधी को रातोंरात स्टार बना दिया। हाल ही में एक बातचीत में प्रतीक ने हंसल मेहता के निर्देशन में बनी इस वेब सीरीज से पहले वाली जिंदगी के बारे में बताया। उनके मुताबिक, घर चलाने के लिए उन्होंने टीवी टावर लगाने और एंकरिंग करने जैसे काम भी किए हैं। इतना ही नहीं, 2006 में सूरत में आई बाढ़ में जब उनका घर तबाह हो गया तो उन्होंने और उनके पूरे परिवार ने एक रूम और किचन वाले घर में रहकर गुजारा किया है।

प्रतीक गांधी ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा- जब मैंने पहला स्टेज परफॉर्मेंस दिया, तब मैं चौथी कक्षा का छात्र था। यह सिर्फ पांच मिनट का स्किट था। लेकिन तब मुझे जो तालियां मिलीं, वे मेरे साथ रह गईं। यहीं से मेरा अभिनय प्रयास शुरू हुआ और जल्दी ही मेरे टीचर्स ने मुझे दूसरे प्लेज में शामिल कर लिया। लेकिन हम मिडिल क्लास थे। पापा सपोर्टिव थे। लेकिन वे कहते थे- पहले डिग्री लो, फिर जो करना हो करो। इसलिए मैं इंजीनियरिंग करने चला गया। तब भी मैं छोटे-मोटे प्ले कर रहा था। इश्क तो एक्टिंग से ही था।

ग्रैजुएट होने के बाद मैं बॉम्बे चला गया। 4 साल तक मैंने एक प्रोजेक्ट में इस आधार पर काम किया कि मैं एक्टिंग कर सकूं। लेकिन तब महीने की कोई इनकम नहीं थी। इसलिए मैंने टीवी टावर इनस्टॉल और एंकरिंग करने जैसे अजीब काम किए। लेकिन 2006 में सूरत में आई बाढ़ ने हमारा घर छीन लिया। मेरी फैमिली मुंबई आ गई और हम चारों एक रूम-किचन वाले घर में रहने लगे।

हेलन से रिश्ता टूटने पर सदमे में आ गए थे सतीश कौल

बी आर चोपड़ा के महाभारत में इंद्र देव के किरदार में नजर आए अभिनेता सतीश कौल का निधन हो गया है। वे 74 साल के थे और कोविड-19 से संक्रमित थे। पॉपुलर फिल्म कर्मा में नजर आए सतीश लंबे समय से बिस्तर पर थे और कोई अपना उनकी सुध लेने वाला भी नहीं था। पिछले साल भी उन्होंने लॉकडाउन के समय आर्थिक तंगी से जूझने की बात कही थी।

8 सितंबर 1954 को कश्मीर में जन्मे सतीश ने पंजाबी और बॉलीवुड की 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। बॉलीवुड में वे भक्ति में शक्ति (1978), डांस-डांस (1987), राम लखन (1989), ऐलान (1994), जंजीर (1998) और प्यार तो होना ही था (1998) जैसी फिल्मों में नजर आए तो पंजाबी में जट पंजाबी (1979), छम्मक छल्लो (1982), ससी पन्नू (1983), और पटोला (1987) जैसी फिल्में की हैं। कहा जाता है कि बॉलीवुड से ज्यादा वे पंजाबी सिनेमा में ही पॉपुलर थे। सतीश का सबसे चर्चित अफेयर बॉलीवुड की मशहूर डांसर हेलन के साथ बताया जाता है। दोनों कुछ सालों तक एक-दूसरे को डेट करते रहे लेकिन फिर हेलन ने सलीम खान से शादी कर ली। इस बात से सतीश को काफी गहरा सदमा भी लगा था। सतीश कौल की निजी जिंदगी काफी उतार-चढ़ाव भरी थी। उनकी पत्नी निम्मी सिंह थीं जिनके साथ सतीश की शादी ज्यादा नहीं चली। दोनों का एक बेटा ऋषभ था। सतीश ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी पत्नी चाहती थीं कि वो अमेरिका चलें और घरजमाई बनकर उनके परिवार वालों के साथ रहें। सतीश इस बात के लिए राजी नहीं हुए और पत्नी उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर अमेरिका चली गईं।

मैं मैरेज (या कि मरण) बाद की इस अपनी 'मुसीबत' के सड़े स्वर से मीठे स्वर में आए बदलाव को महसूस कर रहा था तथा मन-मुदित भी हो रहा था। वैसे सुंदर-सुंदर-सी 'आती-जातीयों' को चोरी-छिपे देखकर मैंने अपने नयनों को ताजा गुलाब की तरह तरोताजा भी कर लिया था दुकानों के साइन बोर्ड देखने के साथ ही, सो यह अलग बात है तथा आप भी इस बारे में मेरी घर वाली को मत बताना।

मैरेज करोगे तो ऐसे ही मरोगे...!

प्रिय पाठकों,
आप सभी को मेरा नमस्कार

कुछेक 'कमसमझ' लोगों की तरह मैंने भी अपना 'मैरेज' (विवाह) कर अपना 'मरण' तय करवा लिया था। अब आप मेरे मैरेज (या कि मरण) के बाद मेरी दुर्गति व दुर्मति की कहानी सुन लीजिएगा, थोड़ी-थोड़ी इंदौरी व मालवी भाषा व बोली के साथ। और हां, पढ़ने के बाद आप जी भरकर हो... हो... कर हंस लीजिएगा या कि फिर एक तगारी आंसू जरूर बहा लीजिएगा, जो भी आपकी इच्छा हो। दिल हल्का हो जाएगा।

जब से मेरा मैरेज हुआ है, मेरा तो मरण ही हो गया है। कहां तो मैंने सोचा था, क्या सोचा था? वो ये कि विवाह के बाद मैं चांद-तारों में विचरण करूंगा। लेकिन हां, चांद-तारे तो मिले जरूर मुझे लेकिन बदले हुए स्वरूप में। वो कैसे? वो ऐसे कि मैरेज बाद मेरा इत्ता मरण हुआ.., इत्ता मरण... कि मेरे सिर में 'चांद' निकल आया यानी कि खोपड़ी के सारे बाल सफा हो गए। और रही बात तारों की, तो मैं जिंदगी की जद्दोजहद (या कि जहर) में इस कदर उलझा कि मुझे तो दिन में ही 'तारे' नजर आने लगे। आसमानी तारे क्या खाक मिलते?

एक बार की बात है कि मैं अपनी गाड़ी पर अपनी लाड़ी को बैठाल के एक शादी समारोह की ओर जा रिया था। मेनरोड से गुजरते समय मेरी निगाहें रोड के दोनों ओर स्थित दुकानों के साइन बोर्ड की ओर रह-रहकर जा रही थीं। अब 'इनका' मन थोड़ा शंकालु तो होता ही है, अत: पीछे बैठी मेरी लाड़ी ने जब मुझे इधर-उधर ताक-झांक करते देखा तो वह बोली कि 'क्यों रे, तू इधर-उधर क्या देख रिया है? सीधा गाड़ी क्यों नहीं चलाता? क्या तेरको पता नहीं है कि मैं पीछे बैठी हूं। क्या तेरा मन अभी भी नहीं भरा है मेरसे? चल, सीधा गाड़ी चला।'

अब पीछे से उनका जुबानरूपी 'हंटर' तो बरस ही गया था, लेकिन फिर भी मैंने अपेक्षित धीरज धारते हुए अत्यंत ही ठंडे स्वर में कहा कि 'हे देवी, मैं इधर-उधर ताक-झांक नहीं कर रिया हूं, बल्कि मैं तो कोई साड़ी-वाड़ी की दुकान देख रिया हूं कि कोई नया लेटेस्ट आयटम बाजार में आया है क्या? ताकि तेरको मैं साड़ी दिला सकूं। तेरको तो गलतफहमी हो गई है।'

और फिर देखो चमत्कार! 'लाड़ी' ने जैसे ही 'साड़ी' का सुना तो उसके 'सड़े' स्वर में 'इमरती' जैसी मिठास न जाने कहां से आ गई। वो बड़े ही मीठे स्वर में बोली कि 'अच्छा तो तू साड़ी-वाड़ी की दुकान देख रिया था, मेरको क्या मालूम? मैं तो समझी थी कि अब तक मुझसे तेरा मन भरा नहीं होगा, अत: तू इसीलिए इधर-उधर ताक-झांक कर रिया हेगा। चल अच्छा, अब तू मेरको साड़ी कब दिलाएगा? मैं तेरे लिए मनपसंद भोजन और मिठाई वगैरह बनाकर खिलाऊंगी।'

मैं मैरेज (या कि मरण) बाद की इस अपनी 'मुसीबत' के सड़े स्वर से मीठे स्वर में आए बदलाव को महसूस कर रहा था तथा मन-मुदित भी हो रहा था। वैसे सुंदर-सुंदर-सी 'आती-जातीयों' को चोरी-छिपे देखकर मैंने अपने नयनों को ताजा गुलाब की तरह तरोताजा भी कर लिया था दुकानों के साइन बोर्ड देखने के साथ ही, सो यह अलग बात है तथा आप भी इस बारे में मेरी घर वाली को मत बताना। पर उसे मेरे द्वारा इस बारे में बताना खतरे से खाली थोड़े ही था, अत: बात घुमाकर उसके मन की करते हुए मैंने 'साड़ी का दांव' फेंक दिया था।

वो सभी धर्मों के धर्मग्रंथों में भी कहा गया है न कि भगवान (ईश्वर) और भागवान (स्त्री) से कभी पंगा मोल नहीं लेना! नहीं तो आदमी कि वो दुर्गति होती है..., वो दुर्गति होती है... कि न ही पूछो। और दुर्मति भी। अत: समझौता कर लेने में ही भलाई (और 'मलाई' भी) है।

अब विवाह करके ओखली में सर डाल ही लिया है तो मूसल से क्या डरना? अत: इस बला (कौन कहता है कि वो अबला है?) को जैसे-तैसे तालमेल बैठाते हुए अपन जिंदगी की गाड़ी पार कर ही लेंगे। वैसे अतीत से अभी तक का इतिहास खंगाला और देखा जाए तो आदमी जन्म से लेकर आखिरी तक किसी न किसी महिला से किसी न किसी रूप में जूते खाता ही रहा है। काफी लंबी परंपरा है यह। वो ऐसे कि बचपन में शरारत करने पर माताजी मरम्मत कर देती थी, बड़े होने पर बड़ी बहनजी मार-ठुकाई लगाती थी और फिर सबसे 'डेंजरस जोन' तब शुरू होता है, जब आदमी का विवाह होता है। और फिर तो जोरू द्वारा 'आरती' का तो लंबा ही इतिहास है। और आगे बढ़ने पर बिटिया रानी भी अपने हाथ साफ कर लिया करती है बहुधा।

थोड़े दिन और बीते होंगे कि लाड़ी बाई बोली कि मेरको पीहर जाना है। मेरे भाई की शादी है। तो इस पर मैं 'हर्षित' होते हुए बोला कि 'तू कब जा री है थारे पीहर? अच्छा तो मैं भी तेरे लिए तैयारी किए देता हूं।' वो कहते हैं न कि 'मुसीबत' जितनी दूर रहे, उतना ही अच्छा। ये जितने दिन पीहर में रहेगी, उतनी ही मेरे मन को शांति मिलेगी। और मन की शांति के लिए मुझे मंदिर-मस्जिद व पहाड़ आदि पर नहीं जाना पड़ेगा। यहीं घर में 'स्वर्गीय' (स्वर्ग सरीखा-सा) सुख मिल जाएगा!

हां तो प्रिय पाठकों, मैं अपनी 'मरण' कहानी यहीं पर समाप्त करता हूं और आपकी भी कोई कहानी हो तो मुझे भी सुनाइएगा। आपको मेरी शुभ कामनाएं ताकि आपकी मेरी तरह 'दुर्गति' न हो।

और हां, चलते-चलते एक विशेष सावधानी- घरवाली से 'जुबानालाप' के दौरान सिर पर एक हेलमेट अनिवार्य रूप से धारण करें...! 'दुर्घटना से सावधानी भली।'

● **प्रमोद दीक्षित 'मलय'**

For Any Medical & Pathology Equipments Contact Us

Science House Medicals Pvt.Ltd.

17/1, Sector-1, Shanti Niketan, Near Chetak Bridge, Bhopal (M.P.) INDIA-462023
GST. No. : 23AAPCS9224G1Z5 Email : shbpl@rediffmail.com
PH. : +91-0755-4241102, 4257687, Fax : +91-0755-4257687

श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

मेरी_सुरक्षा_मेरा_मास्क

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री

यदि आप होम आइसोलेशन में हैं तो ...

कोविड-19 प्रोटोकॉल अनुसार

होम आइसोलेशन संबंधी निर्देश

कोरोना पॉजीटिव व्यक्ति की जिम्मेदारी

- अपने संपर्क में आये सभी व्यक्तियों की जानकारी सर्वप्रथम जिला सर्वेलेन्स अधिकारी को उपलब्ध करा दें।
- अपने संपर्क में आये सभी परिचितों को दूरभाष पर तुरंत सूचित कर उन्हें नजदीक के फीवर क्लीनिक में जांच कराने की समझाईश दें।
- संपर्क में आये परिचितों में से लक्षण रहित को अपने संपर्क दिनांक से 5वें से 10वें दिन के बीच जांच कराने की सलाह दें।

24x7 हेल्पलाइन नं.
104 व 1075

होम आइसोलेशन हेतु आवश्यक व्यवस्थायें

- संक्रमित व्यक्ति एक पृथक हवादार शौचालय युक्त कक्ष में रहे।
- संक्रमित व्यक्ति होम आइसोलेशन अवधि में अपने कमरे से बाहर न निकले, अपने कमरे में ही खाना खाये तथा अन्य व्यक्तियों के सीधे संपर्क में न आये।
- अपने कपड़ों, कमरे की आमतौर पर छूये जाने वाली सतहों (दरवाजे के हैन्डल, बिजली के बटन आदि) तथा शौचालय की सफाई 1 प्रतिशत सोडियम हाईपोक्लोराइड सौल्यूशन से करें।

कोरोना पॉजीटिव व्यक्ति के उच्च जोखिम वाले संपर्क

- घर के सदस्य।
- सीधे शारीरिक संपर्क अथवा संक्रमित स्राव के सीधे संपर्क में बगैर व्यक्तिगत सुरक्षा साधनों के आया व्यक्ति।
- बंद वातावरण में 1 मीटर से कम दूरी में आमने-सामने संपर्क में आया व्यक्ति।
- संक्रमण का जोखिम लक्षण उत्पन्न होने के 14 दिन के पूर्व से संभावित होता है।

होम आइसोलेशन के दौरान सावधानियां

- कक्ष से बाहर न निकलें और न ही किसी से मिलें।
- घर के अन्य सदस्यों, विशेषकर वृद्ध, गर्भवती महिलायें, बच्चों से दूरी बनायें।
- सामाजिक/धार्मिक कार्यक्रमों में सम्मिलित न हों।
- पर्याप्त संतुलित आहार तथा तरल पेय पदार्थों का सेवन।
- समुचित आराम करें तथा व्यक्तिगत सुरक्षा व साफ-सफाई पर ध्यान दें।
- चिकित्सकीय परामर्श अनुरूप औषधियों का सेवन जारी रखें।

होम आइसोलेटेड रोगी के घर के सदस्यों के लिये सावधानियां

- वृद्ध संक्रमित व्यक्तियों की देखभाल घर के युवा सदस्य करें।
- वयस्क देखभालकर्ता सदैव 3 परत मास्क का उपयोग करें।
- संक्रमित व्यक्ति को भोजन, पानी, औषधियां आदि देते समय दूरी बनाये रखें।
- घर से बाहर न निकलें तथा अतिथियों को घर पर आमंत्रित न करें।
- देखभाल के दौरान सर्दी, खांसी, बुखार, गले में खराश आदि होने पर तुरंत समीप के फीवर क्लीनिक में संपर्क/जांच करवायें।

कोरोना-19 पॉजीटिव व्यक्ति के लक्षण दिखने पर परिवहन व्यवस्थायें

- सक्षम व्यक्ति जिला कोविड कंट्रोल एवं कमांड सेंटर से चर्चा कर उपलब्ध विस्तर के आधार पर स्वयं के साधन से चिन्हांकित केंद्रों पर जा सकते हैं।
- स्वयं का परिवहन अनुपलब्ध होने पर 108 परिवहन व्यवस्था प्राप्त की जा सकती है।
- परिवहन के दौरान वाहन में मास्क का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जाये।
- हाथों की स्वच्छता हेतु सेनिटाइजर का उपयोग किया जाये।
- खिड़कियां खुली रखी जायें एवं ड्राइवर से दूरी बनाकर रखी जाये।
- बंद एवं वातानुकूलित वाहनों का उपयोग नहीं किया जाये।
- ड्राइवर द्वारा मास्क एवं दस्तानों का उपयोग किया जाये।
- यथासंभव एक वाहन में ड्राइवर के अतिरिक्त 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा सफर नहीं किया जाये।

तीन बात से डरे कोरोना – दूरी, मास्क, हाथ को धोना

मास्क/फेस कवर पहनें | दो गज दूरी बनाएं | हाथों को अच्छे से साबुन और पानी से धोएं

आपके परिवार का कोई सदस्य 45 वर्ष से ऊपर है, तो वैक्सीनेशन अवश्य कराएं।

सभी नियमों का पालन करेंगे और करायेंगे, हम कोरोना से बचेंगे और अपनों को बचायेंगे।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा जनहित में जारी